13 भाषाओं में प्रकाशित

योजना

जून 2026 | ₹22

1957 से विकास को समर्पित मासिक पत्रिका

YOJANA • യോജന • योजना • ਯੋਜਨਾ • યોજના • ಯೋಜನಾ • திட்டம் • পরিকল্পনা • যোজনা • యోజన • ଯୋଜନା • یوجنا

नक्सल-मुक्त भारत

विद्यालय | सड़क | अस्पताल | बिजली | रोज़गार | अवसर

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

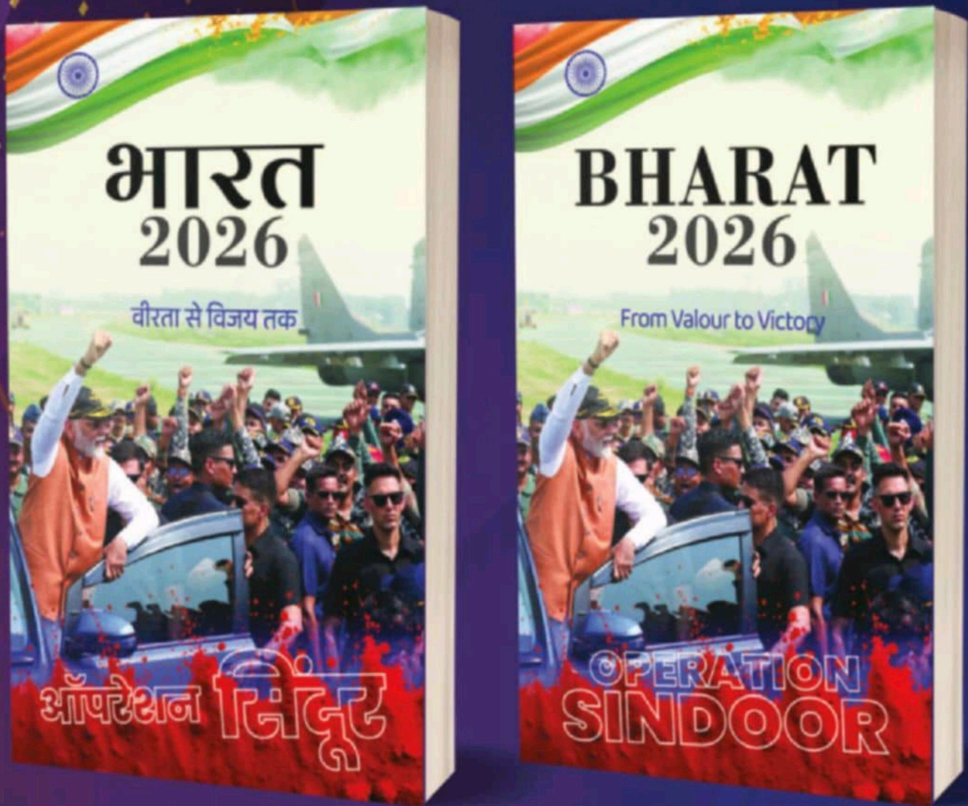

विशेष मूल्य
₹306.00*
* सीमित समय के लिए

भारत के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों तथा नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों का विश्वसनीय संकलन

ऑर्डर देने के लिए संपर्क करें :

फोन : 011 24365609 | ईमेल : businesswng@gmail.com

ऑनलाइन खरीद के लिए www.bharatkosh.gov.in पर जाएं

वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in

अन्य उपयोगी पुस्तकों/पत्रिकाओं के लिए कृपया पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली में पधारें

@publicationsdivision | @DPD_India | @dpd_india

योजना

वर्ष : 70
अंक : 06

जून 2026
ज्येष्ठ, शक संवत् 1948

मूल्य : ₹22
पृष्ठ : 56

प्रधान संपादक
कुलश्रेष्ठ कमल

संपादक
त्रिनाथ त्रिपाठी

उत्पादन अधिकारी
मिहिर कुमार बासु

आवरण : **बिंदु वर्मा**

संपादकीय कार्यालय
648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
ईमेल : yojanahindi-dpd@gov.in

योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से सम्बन्धित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।

योजना में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय-वस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं है।

योजना में प्रकाशित आलेखों में प्रयुक्त मानचित्र व प्रतीक आधिकारिक नहीं है, बल्कि सांकेतिक हैं। ये मानचित्र या प्रतीक किसी भी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

योजना लेखकों द्वारा आलेखों के साथ अपने विश्वसनीय स्रोतों से एकत्र कर उपलब्ध कराए गए आंकड़ों/तालिकाओं/इन्फोग्राफिक्स के सम्बन्ध में उत्तरदायी नहीं है। योजना किसी भी लेख में केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत किसी भी ब्रांड या निजी संस्थाओं का समर्थन या प्रचार नहीं करती है।

योजना की सदस्यता शुल्क जमा करने के बाद पत्रिका प्राप्त होने में कम से कम 8 सप्ताह का समय लगता है। इस अवधि के समाप्त होने के बाद ही योजना प्राप्त न होने की शिकायत करें।

योजना न मिलने की शिकायत या पुराने अंक मंगाने के लिए नीचे दिए गए ई-मेल पर लिखें-
sec-circulation-moib@gov.in
या संपर्क करें-
हेल्पलाइन नं. : 011-24044000/01
(सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर प्रातः 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक)

योजना की सदस्यता की जानकारी लेने तथा विज्ञापन छपवाने के लिए संपर्क करें-
अभिषेक चतुर्वेदी, संपादक, पत्रिका एकांश
प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 779, सातवां तल,
सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003

इस अंक में...

6 नक्सल-मुक्त भारतः एक ऐतिहासिक उपलब्धि
अमित शाह

10 संघर्ष से प्रगति तक छत्तीसगढ़ की परिवर्तन यात्रा
विजय शर्मा

15 नक्सल-मुक्त भारत एक निर्णायक रणनीतिक बदलाव
कुलदीप सिंह

19 वामपंथी उग्रवाद उन्मूलन के लिए केंद्र-राज्य समन्वित सरकारी रणनीति
राजीव कुमार

27 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में भारतीय डाक की भूमिका
दुष्यन्त मुद्गल

30 बस्तर ओलंपिकः शांति, सहभागिता और बदलाव की नई धारा
सुंदरराज पट्टिलिंगम

34 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शिक्षा और सशक्तीकरण का आधार
अजीत कुमार श्रीवास्तव

38 सुरक्षा से संपर्क तकः नक्सल-मुक्त भारत में दूरसंचार क्रांति की भूमिका
रीतेश कावडिया

41 सुरक्षा, समन्वय और संकल्प ऐसे बना नक्सल-मुक्त भारत
कंचन लक्ष्मण

45 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विश्वास, विकास और लोकतंत्र की जीत
अभिराम घड्याल पाटिल

48 बस्तर पंडुमः संस्कृति, पहचान और शांति की पुनर्स्थापना

51 मन की शांति से समाज की शांति तक योग का जीवन दर्शन
डॉ. हंसाजी योगेंद्र

आगामी अंक - विकसित भारत@2047

'योजना' में प्रकाशित आलेखों एवं सामग्री पर पाठकों से प्रतिक्रिया और सुझाव आमंत्रित हैं। इन्हें 'आपकी राय' कॉलम में छापा जायेगा।

नोट :- योजना का आवरण प्रतीकात्मक चित्र पर आधारित है। प्रदर्शित बच्चे नक्सल प्रभावित नहीं हैं।

प्रकाशन विभाग के देशभर में स्थित विक्रय केन्द्रों की सूची के लिए देखें पृ.सं. 37

योजना हिंदी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेज़ी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, ओड़िया, पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित।

JOIN THE INDIAN AIR FORCE
DISHA
INDIAN AIR FORCE
AIR FORCE COMMON ADMISSION TEST - 02/2026
AFCAT
Registrations open till 19 June 2026
Same Registration Portal For
AFCAT ENTRY | GATE SCORE BASED ENTRY | NCC SPECIAL ENTRY
ENTRY & BRANCHES
• AFCAT Entry: Flying/ Technical/ Weapon System/ Administration/ Logistics/ Accounts/ Education/ Meteorology
• GATE Score Based Entry: Technical (Valid GATE score is mandatory)
• NCC Special Entry: Flying (NCC Air Wing 'C' certificate is mandatory)
For AFCAT Entry registration and online exam are mandatory/ NCC Special Entry registration mandatory and no online exam/ GATE Score Based Entry for Technical Branch only and no online exam
Aadhar Card is mandatory for online registration
Registrations open from 20 May 2026 till 19 June 2026
For more details, refer to Employment News dated 16 May 2026 and for detailed notification visit our website careerairforce.gov.in and afcat.edcil.co.in
FOR UPDATES, FOLLOW US ON
011-23013690
1800-112-448
careeriniaf@gmail.com
www.careerairforce.gov.in
DISHA, Air Headquarters (Vayu Bhawan) Motilal Nehru Marg, New Delhi - 110106
CBC 10801/13/0001/2627

YH-2902/2026

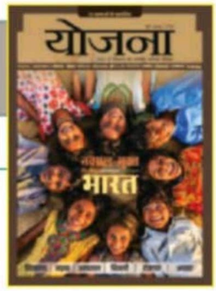

नक्सल-मुक्त भारत
सुरक्षा, विकास और विश्वास की पुनर्स्थापना

भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में कुछ उपलब्धियां केवल प्रशासनिक सफलता नहीं होतीं, बल्कि वे राज्य, समाज और नागरिकों के बीच विश्वास की पुनर्स्थापना का प्रतीक बन जाती हैं। मार्च 2026 में देश को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त घोषित किया जाना भी ऐसी ही एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस उपलब्धि का मूल आधार केंद्र और राज्यों के बीच मज़बूत समन्वय पर आधारित समग्र सरकारी दृष्टिकोण रहा। यह रणनीति चार प्रमुख स्तंभों पर निर्मित थी- वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा उपायों को मज़बूत करना, पिछड़े क्षेत्रों में विकास को गति देना, स्थानीय समुदायों के अधिकारों और हितों की रक्षा सुनिश्चित करना तथा सतत जनसंपर्क और संवाद के माध्यम से विश्वास का वातावरण तैयार करना।

योजना का यह अंक नक्सलवाद के प्रश्न को केवल क़ानून-व्यवस्था की चुनौती के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक, विकासात्मक और मानवीय संदर्भ में देखने का प्रयास करता है। यह दर्शाता है कि किसी भी दीर्घकालिक आंतरिक संघर्ष का समाधान केवल बंदूक से नहीं, बल्कि सुशासन, शिक्षा, अवसर और सामाजिक विश्वास के समन्वय से संभव होता है। देश को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त कराने पर लोकसभा में चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस उपलब्धि को एक स्पष्ट नीति, दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और सुरक्षाबलों के असाधारण साहस का परिणाम बताया।

भारत में वामपंथी उग्रवाद ने लंबे समय तक उन क्षेत्रों को प्रभावित किया, जहां भौगोलिक कठिनाइयों, सीमित प्रशासनिक पहुंच और सामाजिक वंचना ने अलगाव की भावना को गहरा किया। ऐसे में हाल के वर्षों में अपनाई गई बहुआयामी रणनीति ने इस संघर्ष की दिशा बदलने का कार्य किया। सुरक्षा अभियानों, ख़ुफ़िया समन्वय, तकनीकी निगरानी और केंद्र-राज्य सहयोग ने उग्रवाद की संरचनाओं को कमज़ोर किया, वहीं विकास और पुनर्वास के प्रयासों ने लोगों के भीतर विश्वास का नया आधार तैयार किया।

इस अंक में शिक्षा को विशेष रूप से परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में रेखांकित किया गया है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की भूमिका यह दर्शाती है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केवल ज्ञान का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक स्थिरता और आत्मविश्वास निर्माण का आधार भी बन सकती है। जब दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे आधुनिक शिक्षा, डिजिटल संसाधनों और प्रतियोगी अवसरों से जुड़ते हैं, तो उनके सामने हिंसा नहीं, बल्कि संभावनाओं का नया संसार खुलता है। आकांक्षा स्वयं उग्रवाद के विरुद्ध एक प्रभावी प्रतिरोध बन जाती है।

इसी प्रकार, कौशल विकास और रोज़गार आधारित पहल भी इस परिवर्तन की केंद्रीय धुरी हैं। नई अर्थव्यवस्था में केवल सुरक्षा सुनिश्चित करना पर्याप्त नहीं; युवाओं को सम्मानजनक आजीविका, तकनीकी दक्षता और भविष्य के अवसरों से जोड़ना भी उतना ही आवश्यक है।

यह अंक यह भी संकेत देता है कि स्थायी शांति केवल प्रशासनिक नियंत्रण से नहीं आती, उसके लिए सांस्कृतिक आत्मविश्वास और सामाजिक पहचान का सम्मान भी आवश्यक है। बस्तर पंडुम जैसे आयोजन इस बात के उदाहरण हैं कि संस्कृति और परंपरा समाज को जोड़ने, भय को कम करने और सामुदायिक गर्व को पुनर्जीवित करने की कितनी बड़ी शक्ति रखते हैं। जब किसी क्षेत्र की पहचान हिंसा से हटकर कला, लोक परंपरा, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने लगे, तो वह परिवर्तन केवल प्रतीकात्मक नहीं रहता, वह सामाजिक मनोविज्ञान को भी बदल देता है। योग और मानसिक संतुलन पर आधारित इस अंक का विमर्श भी इसी व्यापक मानवीय दृष्टि को आगे बढ़ाता है। योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मानुशासन, संतुलन और आंतरिक चेतना का माध्यम है।

अंततः 'नक्सल-मुक्त भारत' केवल एक राजनीतिक या सुरक्षा संबंधी घोषणा नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक भारत की उस क्षमता का प्रमाण है, जिसमें उग्रवाद के कारण विकास की मुख्यधारा से अछूते क्षेत्रों को भी विकास, संवाद और संवैधानिक मूल्यों के माध्यम से नई दिशा दी जा सकती है। आगे की चुनौती इस उपलब्धि को स्थायी शांति, समावेशी विकास और सामाजिक विश्वास में परिवर्तित करने की है। यही विकसित और आत्मविश्वासी भारत की वास्तविक पहचान होगी। ❑

upscnotes.in

स्पष्ट नीति
दृढ़ इच्छाशक्ति

अमित शाह

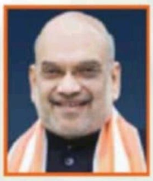

नक्सल-मुक्त भारत: एक ऐतिहासिक उपलब्धि

वामपंथी उग्रवाद से देश को मुक्त कराना मोदी सरकार की उन बड़ी उपलब्धियों में से एक है, जिसके लिए आने वाली पीढ़ियां इस कालखंड को याद रखेंगी। पांच दशकों से भी अधिक समय तक जो समस्या देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर चुनौती बनी रही, वह आज समाप्त हो चुकी है। यह परिणाम अपने आप नहीं आया। इसके पीछे एक स्पष्ट नीति, दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और हमारे सुरक्षाबलों का असाधारण साहस है।

वामपंथी उग्रवादियों और उनके समर्थकों ने दशकों तक भोले-भाले आदिवासियों के सामने एक झूठा नैरेटिव प्रस्तुत किया कि वे उनके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। परंतु यह एक विचारधारा की लड़ाई थी, न कि विकास की मांग। इस सच को आज पूरे देश के सामने स्पष्ट करना आवश्यक है।

वामपंथी उग्रवाद की जड़ें विकास में नहीं, विचारधारा में थीं

यह समझना ज़रूरी है कि नक्सलवाद गरीबी या विकास की कमी के कारण नहीं फैला, बल्कि नक्सलवाद के कारण इस पूरे क्षेत्र में वर्षों तक गरीबी रही। वर्ष 1960 के दशक में नक्सलबाड़ी क्षेत्र में साक्षरता दर 35 प्रतिशत, बस्तर में 23 प्रतिशत, सहरसा में 33 प्रतिशत और बलिया में 31 प्रतिशत थी। प्रति व्यक्ति आय भी इन चारों क्षेत्रों में लगभग समान थी। फिर भी नक्सलवाद केवल उन्हीं क्षेत्रों में पनपा जहां घने जंगल थे, नदी-नाले थे और राज्य की पहुंच सीमित थी। सहरसा और बलिया में नक्सलवाद इसलिए नहीं आया क्योंकि वहां का भूगोल उनके अनुकूल नहीं था।

माओवादी विचारधारा का ध्रुव वाक्य है: "सत्ता बन्दूक की नली से निकलती है।" यह विकास के लिए नहीं, अपनी विचारधारा के अस्तित्व के लिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए था। इन्होंने तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा या भगत सिंह को अपना आदर्श नहीं माना, इन्होंने माओ को अपना आदर्श माना। यह भी उन्होंने विदेश से आयात किया।

जब वामपंथी उग्रवादियों को लगा कि आदिवासी पढ़-लिख जाएंगे तो उनके साथ नहीं रहेंगे, तो उन्होंने स्कूल जला दिए। बैंक खाते खुल जाएंगे तो हमारे साथ नहीं रहेंगे, इसलिए बैंकें जला दीं। दवाखाने जला दिए गए। इन्होंने उस क्षेत्र में विकास को वर्षों तक नहीं पहुंचने दिया। यही इनकी असली नीति थी।

लेखक भारत सरकार में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं।

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

18 मई, 2026 को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस अधिकारियों को किया सम्मानित

रेड कॉरिडोरः एक विशाल समस्या

12 राज्यों, 17 प्रतिशत भूभाग और 20 करोड़ की आबादी वाले इस क्षेत्र में क़ानून का शासन लगभग समाप्त कर दिया गया था। दोनों ओर से 20 हजार युवा मारे गए। कई लोग पूरे जीवन के लिए दिव्यांग बन गए। 3,500 से अधिक सुरक्षाकर्मी लड़ते-लड़ते शहीद हो गए। जहानाबाद पर हमले में 1,000 सशस्त्र नक्सलियों ने सीआरपीएफ के कैंप और जेल को कब्ज़ा करके 389 कैदियों को मुक्त करा लिया। झारखंड में 70 ट्रकों में एक साथ आग लगा दी गई। जनताना टैक्स की वार्षिक वसूली 240 करोड़ रुपये थी। आंध्र-ओडिशा सीमा पर दर्जनों स्कूलों और बुनियादी ढांचे का सुनियोजित विनाश किया गया।

यूपीए कालः नीतिगत अस्पष्टता का दौर

वर्तमान सरकार की नीति और उपलब्धियों को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि पिछले शासनकाल में क्या हुआ और क्यों यह समस्या इतनी विकराल हो गई।

वर्ष 1970 से लेकर वर्ष 2004 तक के कालखंड में, चार साल छोड़कर, पूरे समय कांग्रेस पार्टी का शासन रहा। यही वह काल था जब माओवादी विचारधारा फैली, पनपी और एकत्रित हुई। वर्ष 2004 में जब दो प्रमुख उग्रवादी गुट मिलकर सीपीआई माओवादी बने। इस पूरे विस्तार के लिए जो राजनीतिक वातावरण जिम्मेदार था, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने स्वयं पूरे देश के सामने स्वीकार किया था कि कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट की तुलना में भी देश की आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी समस्या हथियारबंद माओवादी हैं। स्वीकृति थी, पर कार्रवाई नहीं हुई। यही वह दौर था जब समस्या की गंभीरता स्वीकार करने के बावजूद निर्णायक राष्ट्रीय रणनीति विकसित नहीं हो सकी।

यूपीए काल में कई ऐसे उदाहरण सामने आए जिनमें शहरी नेटवर्क, कथित बौद्धिक समर्थन और संस्थागत उदारता पर गंभीर प्रश्न उठे और कुछ मामलों में नक्सल समर्थक तत्वों के साथ वैचारिक सहानुभूति के आरोप भी सामने आए। 76 जवानों के एक साथ शहीद होने के बाद तत्कालीन गृह मंत्री ने नक्सलियों से कहा कि हम आपसे हथियार डालने को नहीं कह सकते। सलवा जुडूम के आदिवासी स्वयंसेवकों से हथियार छीन लिए गए, जिसके बाद नक्सलियों ने उन्हें चुन-चुनकर मार डाला।

यूपीए काल में जो नीतिगत ढिलाई और वैचारिक सहानुभूति रही, उसी ने इस समस्या को जीवनदान दिया। इसके विपरीत, वर्तमान सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट रहीः जो वार्ता करना चाहता है, उसके साथ वार्ता और जो गोली चलाता है, उसे गोली का जवाब। यही दोनों कालखंडों का मूल अंतर है।

वर्ष 2014 के बादः नीति में बदलाव

वर्ष 2014 में जब नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आई तो एक स्पष्ट नीति और दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति इस काम में जुड़ी।

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

UPSC NEW BOOKS PDF

2026 EDITION

अब UPSC STANDARD BOOKS 2026 की PDF सीधे टेलीग्राम पर लें सकते है बस हमारी टेलीग्राम बॉट पर मैसेज करें

Telegram Bot - @pdfhub2026bot

सीधे मैसेज भेजने के लिए MESSAGE NOW पर क्लिक करें

Message Now

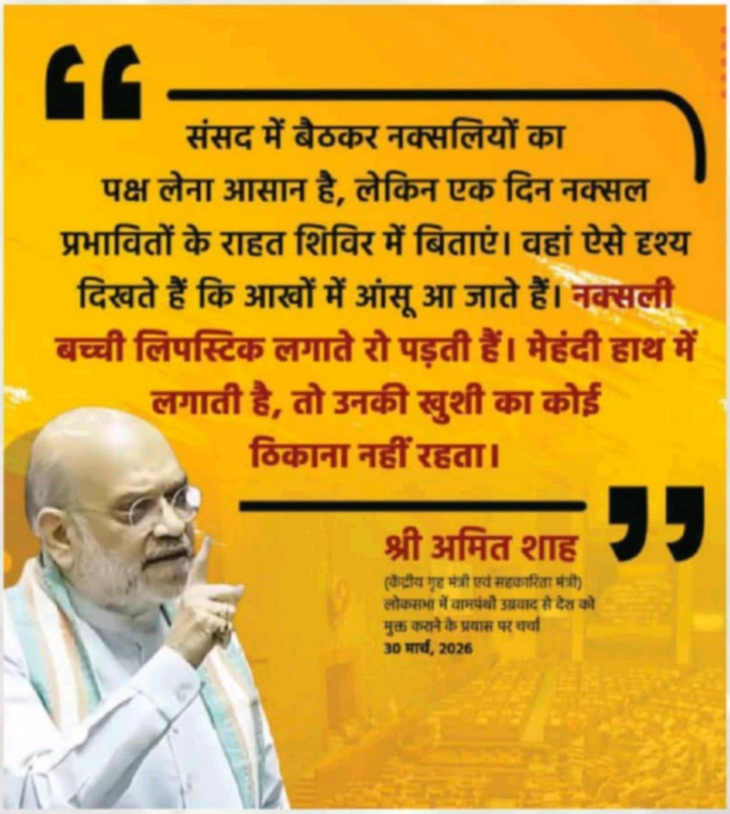

सुरक्षा अभियानः परिणाम और उपलब्धियां

वर्ष 2014 में 126 नक्सल प्रभावित जिले थे, आज केवल दो बचे हैं। वर्ष 2015 में 35 सर्वाधिक प्रभावित जिले थे, आज शून्य हैं। नक्सल घटनाएं दर्ज करने वाले 350 पुलिस थाने थे, अब मात्र सात हैं। मोदी जी के 11 साल के कार्यकाल में 596 सुदृढ़ पुलिस थाने बनाए गए। पिछले छह वर्षों में 406 नए सीएपीएफ शिविर बनाए गए, 68 नाइट लैंडिंग हेलीपैड बनाए गए और 400 बुलेट प्रूफ तथा ब्लास्ट प्रूफ गाड़ियां जवानों को दी गईं।

वर्ष 2024, 2025 और 2026 के संयुक्त आंकड़े के अनुसार, मार्च 2026 तक तीन साल में 706 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए, 2,218 गिरफ्तार हुए और 4,839 लोगों ने आत्मसमर्पण किया। इन्हें पकड़कर जेलों में डाला गया और अदालतों की शरण में ले जाया गया।

इस अभियान में नवीनतम तकनीक का उपयोग किया गया। ड्रोन सर्विलांस, सैटेलाइट का उपयोग, इमेजिंग टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा एनालिसिस से सफलता प्राप्त हुई। 'ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट' विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा जिसमें तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित माओवादियों के स्थायी शिविर को 21 दिनों के अभियान में ध्वस्त किया गया। वहां 400-500 कैडर एकत्रित थे, पांच साल का अनाज भरा था और आईईडी बनाने के कारखाने थे। यह अभियान जिसमें जवानों को 45 डिग्री तापमान में 300 ग्राम पानी पर काम करना पड़ा, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है।

सीएपीएफ और राज्य पुलिस वही रहे, परंतु केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय, एक्शनेबल इंटेलिजेंस और जिम्मेदारियों का निर्धारण हुआ। ऑल एजेंसी एप्रोच अपनाया गया जिसमें केवल सशस्त्र कैडरों को नहीं, बल्कि एनआईए, ईडी और ख़ुफ़िया एजेंसियों के माध्यम से उनके नेटवर्क, फंडिंग और सपोर्ट सिस्टम पर भी प्रहार किया गया।

20 अगस्त, 2019 को गृह मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण बैठक में पुलिस को-ऑर्डिनेशन, मॉडर्नाइजेशन और ख़ुफ़िया एजेंसियों के समन्वय की व्यापक रणनीति तैयार की गई। 24 अगस्त, 2024 को यह घोषणा की गई कि 31 मार्च, 2026 तक देश को नक्सलवाद से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाएगा। यह केवल एक राजनीतिक घोषणा नहीं थी, यह एक संकल्प था जो पूरा हुआ।

माओवादी संगठन का केंद्रीय नेतृत्व पूर्णतः समाप्त हो चुका है। वर्ष 2024 की शुरुआत में 21 सेंट्रल कमेटी मेंबर और पोलित ब्यूरो सदस्य थे। इनमें से एक पकड़ा गया, सात ने आत्मसमर्पण किया, 12 मारे गए और एक फरार है। दंडकारण्य की 37 सदस्यीय स्टेट कमिटी भी पूरी तरह समाप्त हो चुकी है।

विकास का अभियानः समानांतर प्रयास

सुरक्षा अभियान के साथ-साथ विकास का काम भी तेज़ गति से चला। वर्ष 2014 के बाद इस पूरे क्षेत्र में 17,589 किलोमीटर सड़कें बनाने की मंजूरी दी गई, जिनमें से 12,000 किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं। लगभग 20,000 करोड़ रुपये खर्च हो

upscnotes.in

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक नवंबर, 2025 को छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में विकासात्मक और बदलावकारी परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के दौरान एक प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए।

चुके हैं। 5,000 मोबाइल टावर 6,000 करोड़ रुपये के खर्च से लगाए गए और 8,000 नए 4जी टावर बनाने का निर्देश दिया गया है। 1,804 बैंक शाखाएं खुली हैं, 1,321 एटीएम खुले हैं, 37,850 बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंस बनाए गए और 6,025 डाकघर खुले। 259 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्वीकृत किए गए, 47 आईटीआई और 49 स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाए गए।

जगदलपुर में 240 बिस्तरों का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बनाया गया। बस्तर के हर गांव में स्कूल और राशन की दुकान का अभियान चला। प्रत्येक नक्सल-मुक्त पंचायत होते ही गांव के विकास के लिए एक करोड़ रुपये दिए जाने की व्यवस्था की गई।

पुनर्वासः एक संवेदनशील प्रयास

आत्मसमर्पण करने वालों के लिए अत्यंत प्रभावी पुनर्वास नीति अपनाई गई। आत्मसमर्पण के लिए 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि, सामूहिक आत्मसमर्पण पर दोगुनी राशि, हथियार जमा कराने पर अतिरिक्त मुआवजा, 10,000 रुपये प्रति माह 36 महीने तक और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। सरेंडर शिविरों में स्वयंसेवी संस्थाएं उन्हें सामान्य नागरिक जीवन में लाने का काम कर रही हैं। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों में 1,20,000 कलाकारों और 5,50,000 आदिवासी लोगों की भागीदारी हुई।

सुशासन, विकास और संवैधानिक मूल्यों की जीत

यह उपलब्धि केवल एक सुरक्षा अभियान की सफलता नहीं है। यह उस दृष्टि की जीत है जिसमें सुशासन, विकास और संवैधानिक मूल्यों पर विश्वास को केंद्र में रखा गया। इसका पूरा श्रेय सीएपीएफ के जवानों, विशेषकर कोबरा, सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस, डीआरजी के जवानों और वहां के स्थानीय आदिवासी वाशिंदों को जाता है जिन्होंने इस लंबी लड़ाई में अपना अमूल्य योगदान दिया। जो हजारों युवा मारे गए, जो सुरक्षाकर्मी शहीद हुए और जिन्होंने इस देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया, उन सभी को विनम्र श्रद्धांजलि।

लोकतंत्र का मूल सिद्धांत यही है कि किसी भी समस्या का समाधान बहस से निकल सकता है, हथियारों से नहीं। आज जब बस्तर विकसित हो रहा है और वहां के हर गांव में विकास पहुंच रहा है, तो यह प्रमाणित होता है कि राज्य की उपस्थिति, सुशासन और विकास मिलकर किसी भी चुनौती को परास्त कर सकते हैं। ❑

upscnotes.in

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

विजय शर्मा

संघर्ष से प्रगति तक छत्तीसगढ़ की परिवर्तन यात्रा

देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन तथा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सशस्त्र नक्सलवाद की समाप्ति का संकल्प सिद्ध हुआ है। इस ऐतिहासिक सफलता के मूल में निःसंदेह मज़बूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ पुलिस और सुरक्षा बलों के वीर जवानों का अद्वितीय पराक्रम, अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान निहित है।

आज छत्तीसगढ़, विशेषकर बस्तर अंचल, दीर्घकाल तक व्याप्त नक्सल हिंसा, भय और असुरक्षा के वातावरण से उबरकर शांति, विकास और सुशासन के एक नवयुग में प्रवेश कर रहा है। विगत लगभग चार दशकों तक नक्सलवाद ने इस अंचल को गहन पीड़ा तथा असंख्य घाव दिए। अनगिनत निर्दोष लोगों का जीवन छीना, असंख्य परिवारों को असहनीय वेदना दी और अनेक लोगों को जीवनपर्यंत विकलांगता का दंश सहने पर विवश किया। क्रांति के नाम पर आतंक मचाया और यहां के लोगों तक लोकतंत्र और संविधान का प्रकाश पहुंचने नहीं दिया। प्रगति और समृद्धि के सारे रास्ते अवरुद्ध रखे। लोगों को सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाओं तक से वंचित रखा गया। आज बस्तर में शांति और सुशासन का स्वर्णिम प्रभात उदित हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन तथा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सशस्त्र नक्सलवाद की समाप्ति का संकल्प सिद्ध हुआ है। इस ऐतिहासिक सफलता के मूल में निःसंदेह मज़बूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ पुलिस और सुरक्षा बलों के वीर जवानों का अद्वितीय पराक्रम, अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान निहित है।

डीआरजी और स्थानीय युवाओं की भूमिका

बस्तर में सुरक्षा बलों ने केवल मोर्चा नहीं संभाला, बल्कि विश्वास भी जीता। बस्तर में निर्णायक बदलाव तब शुरू हुआ जब सुरक्षा रणनीति स्थानीय समाज की समझ के साथ आगे बढ़ी। इसी स्थानीय समझ ने सुरक्षा अभियानों को प्रभावी बनाया। डीआरजी (डिस्ट्रिक्ट रिज़र्व गार्ड) जैसी इकाइयों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डीआरजी को लेकर एक भ्रांति है कि यह सिर्फ आत्मसमर्पित नक्सलियों से बनी टीम है। जबकि वास्तविकता यह है कि डीआरजी में ऐसे सदस्य सिर्फ 10 से 15 फीसदी ही हैं, बाकी पूरे बस्तर से भर्ती किए गए नौजवान हैं। ये वे युवा हैं जो बस्तर के लोगों, उनकी बोलियों, संस्कृति और परंपराओं के साथ बस्तर के जंगल, पहाड़ियों, पगडंडियों यानी बस्तर की भौगोलिक और सामाजिक संरचना को भीतर से जानते हैं। इनकी शारीरिक बनावट, कद-काठी बस्तर के जंगल के अनुरूप है, जो इनके लंबे और कठिन अभियानों में सहायक होते हैं। इन खूबियों के अलावा बस्तर के इन जवानों में अपनी धरती को लाल आतंक से मुक्त करने की प्रबल भावना है। यही कारण है कि डीआरजी प्रमुख स्ट्राइकिंग फोर्स के रूप में, एंटी नक्सल अभियानों में सबसे आगे रही। आज समूचा छत्तीसगढ़ जब नक्सल मुक्त हो रहा है तो इसमें राज्य की डीआरजी फोर्सेज के साथ-साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का भी अविस्मरणीय योगदान है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों ने भी लंबे समय तक कैंप लगा कर बस्तर में सभी दूरस्थ क्षेत्रों को सुरक्षित करने का काम किया और अभियान के लिए आधार तैयार किया। बस्तर के अंदरूनी इलाकों तक विकास कार्यों को आगे बढ़ाने और जनसुविधाएं पहुंचाने के लिए बड़े-बड़े बलिदान भी सुरक्षा बलों के जवानों ने दिए।

तकनीक और केंद्र-राज्य समन्वय

नक्सल मोर्चे पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी दृढ़ता के साथ अपने सुरक्षा बलों के साथ खड़ी रही। आधुनिक तकनीक, ड्रोन निगरानी, रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रैकिंग और केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय

लेखक छत्तीसगढ़ सरकार में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हैं।

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक नवंबर, 2025 को छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का अवलोकन किया।

ने पहली बार सुरक्षा बलों को नक्सल मोर्चे पर बढ़त दिलाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर आईटीबीपी के रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्निकल विंग, एनएसजी के बम डिस्पोजल स्क्वॉड, एनटीआरओ, डीआरडीओ तथा इसरो ने भी बिना देर किए तकनीकी और अन्य सामग्रियों की सहायता उपलब्ध कराई।

हथियार खरीदने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, जिसमें डेढ़ से दो वर्ष का समय लग जाता है। तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए जब यह बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष रखी गई तब उन्होंने सभी संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर नक्सल अभियान के लिए प्रभावी अत्याधुनिक हथियार एके-47 और इंसास स्नाइपर अन्य सुरक्षा संस्थाओं से लोन पर लेकर छत्तीसगढ़ के डीआरजी फोर्स को उपलब्ध कराया जो नक्सल विरोधी अभियान में मील का पत्थर साबित हुआ। इसके साथ ही उन्नत तकनीक वाले अनमैन्ड एरियल व्हीकल (यूएवी) भी उपलब्ध कराये गए। दूरस्थ घने जंगल-पहाड़ियों में होने वाले नक्सली मूवमेंट के वीडियो फुटेज और रेडियो फ्रीक्वेंसी की आसूचना से सटीक ऑपरेशन हुए, जिसमें जवानों ने बिना किसी क्षति के बड़ी सफलताएं प्राप्त की। बिना क्षति के सफलताएं प्राप्त करना, यह पहले सोच से परे था, जो कि समन्वय से संभव हो पाया।

आर्थिक मोर्चे पर नक्सलवाद पर प्रहार

अनेक आयामों पर एक साथ काम करके बस्तर में नक्सली उन्मूलन के लक्ष्य को पाया गया है और उन आयामों में से एक आर्थिक उन्नति और लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम भी है। आर्थिक विकास के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने बस्तर के लोगों की जीवन शैली के अनुरूप लघु वनोपज आधारित आय के स्रोतों को अधिक विकसित किया। तेंदूपत्ता जैसे सबसे महत्वपूर्ण वनोपज को निजी ठेकेदारों की व्यवस्था से हटाते हुए सीधे सरकार को एजेंसी बनाया गया, जिससे जनता को सीधा लाभ मिला और नक्सलियों को आर्थिक आधार पर गहरी चोट पड़ी। राज्य सरकार अपने संसाधनों और केंद्र सरकार के सहयोग से बस्तर में आर्थिक उन्नति के स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए संकल्पित है, इसको शीघ्र पूरा करने का प्रयास जारी है।

हथियार से संविधान तकः पुनर्वास की मानवीय पहल

छत्तीसगढ़ सरकार ने पुनर्वास की नई नीति लागू की, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि जिस समाज के दोषी यह नक्सली थे, जिन्होंने बस्तर में समूह में आदिवासियों की हत्याएं की, उन्हें उन्हीं समाज प्रमुख मांझी-चालकी के समक्ष पुनर्वास कराकर, समाज ने बड़े हृदय के साथ इनको स्वीकार किया। पुनर्वास के दौरान नक्सलियों ने संविधान की किताब हाथ में लेकर यह संदेश दिया कि वे अब जंगलों में हथियार लेकर नहीं घूमेंगे, बल्कि भारत के संविधान को स्वीकार करेंगे। ऐसे लोगों का लाल कालीन बिछाकर स्वागत किया गया। पुनर्वासितों के लिए बस्तर के हर जिले में पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए गए, जहां उन्हें आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए उनकी दिनचर्या का कार्यक्रम तैयार किया गया। रोज़गार परक प्रशिक्षण तथा किट प्रदान की गई। उन्हें पुनर्वास केंद्रों में बुनियादी शिक्षा प्रदान की जा रही है।

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

उनके आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बनवाए जा रहे हैं और बैंक खाते खुलवाए जा रहे हैं। जिन्होंने कभी सड़क, बिजली, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, मॉल आदि नहीं देखा, ऐसे पुनर्वासितों और युवा साथियों को 'लयोर ओयाना' (युवा आमंत्रण) के तहत रायपुर भ्रमण कराया जा रहा है। विधानसभा सत्र का अवलोकन कराया जा रहा है, ताकि देश-प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था से परिचित हो सकें। पुनर्वासित लोग समाज के साथ रच-बस सकें इस उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री के सरकारी निवास पर सामूहिक भोजन का आयोजन किया गया। वास्तव में पुनर्वास का अर्थ कुछ दिन बिता लेना ही नहीं है, पुनर्वास अर्थात आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और शैक्षणिक पुनर्वास है। ऐसे अनेक लोग आए जिनके शरीर में गोलियां फंसी थीं, उनका ऑपरेशन कर गोलियों को बाहर निकाला गया तो शारीरिक पुनर्वास हुआ। ऐसे सारे ही आयामों पर पुनर्वास की प्रक्रिया यहां पूर्ण की गई है। पुनर्वास केंद्रों में सभी को स्मार्टफोन दिया गया है, ताकि वे नए जमाने से जुड़ सकें।

दिल्ली तक पहुंची नक्सल पीड़ितों की आवाज़

बस्तर में नक्सलियों के आईईडी विस्फोट से प्रभावित लोगों की संख्या हजारों में है। बहुत सारे लोग मारे गए, जो बच गए वे जीवन भर के लिए दिव्यांग हो गए हैं। उनके जीवन की अपनी व्यथा-कथा है। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें नक्सलियों ने गांव से बाहर निकाल दिया। ऐसे भी लोग हैं जो नक्सलियों की गोली से हताहत हुए। नई सरकार बनने के बाद ऐसे सभी लोगों ने मिलकर दिल्ली का प्रवास किया और राष्ट्रपति महोदया के समक्ष अपनी बात रखी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने घर के आंगन में पंडाल लगाकर उन्हें भोजन कराया, उनकी बातों को गंभीरता से सुना। इन नक्सल पीड़ित लोगों ने कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में बैठकर दुनिया का अनूठा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें एक तरफ बस्तर के नक्सल पीड़ित बैठे थे और दूसरी तरफ दुनिया भर की मीडिया थी। इस तरीके से बस्तर के आम नागरिक के दर्द को दिल्ली तक पहुंचाने का काम भी किया गया।

बस्तर ओलंपिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण

बस्तर के युवाओं के बीच खेल और समाज में संस्कृति यह दो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो बस्तर की जीवन शैली का आधार हैं। पुनर्वास की दिशा में अपील करते हुए इस बात पर ज़ोर दिया गया कि और नौजवान नक्सलवाद की तरफ ना जाएं, इसलिए बस्तर ओलंपिक 2025 और 2026 का आयोजन किया गया। जहां गांव-गांव से लाखों की संख्या में युवाओं ने बस्तर ओलंपिक में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वैसे ही बस्तर में सांस्कृतिक मूल्य बहुत ऊंचे हैं। उन सांस्कृतिक मूल्यों के संवर्द्धन तथा संरक्षण के लिए बस्तर पंडुम 2025 और 2026 का आयोजन किया गया। बस्तर की गोंड, मुरिया, मारिया दोरला आदि सभी जनजातियों की पारंपरिक वेशभूषा, नृत्य, वाद्य यंत्र, लोकनाट्य, तीज-त्योहार, खाद्य-पदार्थ, पेय-पदार्थ, इन सभी को एक साथ एक स्तर पर देश-दुनिया के पटल पर रखने के लिए बस्तर पंडुम का आयोजन किया गया।

आज बस्तर में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है यह जवानों की भुजाओं की ताकत से ही संभव हो सका है। छत्तीसगढ़ के अन्य क्षेत्रों में भी नक्सल उन्मूलन की दिशा में इतने जवानों ने अपनी शहादत

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 18 मई, 2026 को जगदलपुर में आयोजित उजर बस्तर कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा द्वारा सम्मानित किया गया।

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

13 दिसंबर, 2025 को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आयोजित बस्तर ओलंपिक का समापन समारोह

दी है कि 25 वर्ष के बाद भी किसी पुलिस की टीम को मिलने वाला राष्ट्रपति का कलर अवॉर्ड, छत्तीसगढ़ को 24 वर्ष की छोटी उम्र में ही प्रदान किया गया। नक्सल मुक्ति में समूचा बस्तरिया समाज, बस्तर के पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों और बस्तर के पत्रकारों ने भी महत्वपूर्ण सहयोग किया।

शहादत, समाज और सहयोग से मिली सफलता

नेल्सन मंडेला ने कहा था कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। यह बात माओवादी लीडर भली भांति जानते थे, इसीलिए बस्तर पर अपना प्रभुत्व बरकरार रखने के लिए असली शिक्षा कभी पहुंचने नहीं दी। कोई शिक्षक यदि पढ़ाना चाहता तो उसे पीटा जाता, जिससे कोई वहां पढ़ाने को तैयार नहीं था। वहां के स्थानीय पढ़े-लिखे युवाओं को प्रेरित कर शिक्षादूत बनाकर शिक्षा का अलख जगाने का प्रयास किया, तो माओवादियों ने शिक्षादूतों की हत्याएं शुरू कर दीं। स्कूल, कॉलेज, यहां तक कि आंगनबाड़ी केंद्रों को भी तोड़ा गया या बंद करा दिया गया था। ज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए सरकार ने पुराने ध्वस्त किए गए या बंद किए गए सुकमा के 123 स्कूलों और बीजापुर के 265 ऐसे स्कूलों को पुनः प्रारम्भ कराने का कार्य किया। स्थानीय लोग बताते हैं कि बीजापुर के बेचापाल, कावड़गांव, कोडोली, मुतवेडी, पीरामुंडा, जीदपल्ली, नैमेड और तोड़का ये ऐसे ग्राम थे, जहां पिछले 20 सालों से स्कूलों को खुलने नहीं दिया जाता था। युवाओं को सीधे संगठन में मर्जी से या जबरदस्ती शामिल किया जाता था, इससे इंकार का मतलब सीधे मौत होता था। अब इस क्षेत्र में शिक्षा का वातावरण विकसित हो रहा है। इसका सुखद परिणाम है कि बीजापुर के भैरमगढ़ विकासखंड के धुर नक्सल प्रभावित ग्राम गुदमा के युवा अंकित सकनी ने यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को पास कर मिसाल कायम की। ऐसे ही अब बस्तर के युवा आगे बढ़कर प्रदेश का मान बढ़ाएंगे।

जहां बंद थे स्कूल, वहां गूंज रही बच्चों की आवाज़

शासन का उद्देश्य केवल इन क्षेत्रों को सामंतवादी लोगों की तरह इसे जीतना नहीं है बल्कि वर्षों से पिछड़े लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। डर के साए में विकास का स्वप्न देखना एक उपहास मात्र होता, जिसके लिए अर्द्धसैनिक बलों द्वारा बनाए गए कैम्पों को विकास के केंद्र बिंदु के रूप में स्थापित करने का कार्य किया गया और नियद नेल्ला नार (मेरा अच्छा गांव) पहल प्रारम्भ की गई। जिसके तहत 99 सुरक्षा कैम्पों के अंतर्गत आने वाले 144 ग्राम पंचायत और 500 से अधिक ग्रामों में 17 विभागों की 25 व्यक्तिमूलक तथा 18 सामुदायिक योजनाओं को जोड़ कर हर गांव में लोगों को शासन की सभी योजनाओं का लाभ दिलाना प्रारम्भ किया गया। ऐसे लोग जिनका ना कभी आधार कार्ड बना, ना वोटर आईडी कार्ड और ना ही राशन कार्ड, सबसे पहले उनके लिए पहचान पत्र बनाकर उन्हें ग्राम पंचायतों के माध्यम से सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं।

प्रदेश में वर्तमान सरकार के गठन के बाद से बस्तर के 87 प्रतिशत ग्रामों में मोबाइल कवरेज उपलब्ध है। सड़क संपर्क को बढ़ाने और जिला मुख्यालयों को गांवों से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना लाई गई है, जिसके तहत बस्तर में 38 बस परिचालन रूटों की शुरुआत की गई है। एनसीएईआर के सर्वे के मुताबिक अब 93 प्रतिशत ग्रामों में प्राथमिक स्कूल उपलब्ध हैं। 97 प्रतिशत छात्रों को मध्यान्ह भोजन प्राप्त हो रहा है। 97 प्रतिशत गांवों में आंगनबाड़ी केंद्र और 89 प्रतिशत ग्रामीणों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाया गया है।

दुर्दांत हिड़मा के गांव की बदल रही तस्वीर

कभी माओवाद का पोस्टर बॉय कहलाने वाले माड़वी हिड़मा, जिसे माओवाद का हीरो बनाने का प्रयास अर्बन नक्सल समूहों ने किया, पर उसके गांव की हकीकत कभी किसी ने बाहर आने नहीं दी। दिल्ली में बड़े-बड़े विश्वविद्यालय के एसी कमरों में बैठकर नक्सलियों के नारे लगाने वालों ने कभी खौफ के साए में जीने वाले ऐसे गांवों में झांक कर नहीं देखा। इस गांव में ना सड़क थी, ना पेयजल, ना ही कोई और सुविधा, था तो केवल डर। हर कोई डर में जीता था। 2024 में पूवर्ती में पहला कैम्प खुला, जिसके बाद यहां एक नया युग प्रारम्भ हुआ। सीआरपीएफ की 150वीं बटालियन ने न केवल यहां पर सुरक्षा और विश्वास कायम करने का काम किया बल्कि विकास कार्यों को भी आगे बढ़ाया। 2024 में पहली बार यहां लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यहां तक कि सड़क बनाने में सीआरपीएफ के जवानों ने सहयोग किया। इस गांव में बच्चों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, ऐसे में सीआरपीएफ द्वारा गुरुकुल भी प्रारम्भ किया गया। जहां अक्षर ज्ञान के साथ 100 से अधिक बच्चों को मूलभूत शिक्षा देने का कार्य किया जा रहा है। यहां लोगों को बिहान योजना द्वारा आजीविका देने के

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

UPSC NEW BOOKS PDF

2026 EDITION

अब UPSC STANDARD BOOKS 2026 की PDF सीधे टेलीग्राम पर लें सकते है बस हमारी टेलीग्राम बॉट पर मैसेज करें

Telegram Bot - @pdfhub2026bot

सीधे मैसेज भेजने के लिए MESSAGE NOW पर क्लिक करें

Message Now

साथ ही युवाओं को राजमिस्त्री, वेल्डर, फिटर जैसे रोज़गारपरक कार्यों का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। पहले पूवर्ती के लोगों को राशन लेने के लिए मीलों दूरी तय करनी पड़ती थी, अब गांव में ही राशन दुकान खुल गई है। गांव के सभी मजरों टोलों में विद्युत आपूर्ति का प्रबंध किया जा रहा है।

खेल के मैदान से जीवन की नई शुरुआत

बस्तर ओलंपिक के माध्यम से बस्तर के युवाओं को अपना कौशल दिखाने का मौका प्राप्त हुआ, जहां 2024 में 1.65 लाख युवाओं ने इसमें भाग लिया था, वहीं वर्ष 2025 में 3.91 लाख युवाओं ने इसके लिए पंजीयन कराया। इसमें खास बात यह थी कि ओलंपिक मशाल वाहक के रूप में कभी अतिसंवेदनशील माने जाने वाले पूवर्ती के युवा कबड्डी खिलाड़ी डोडा विजय ने भूमिका निभाई थी। इस ओलंपिक में जहां पूरे बस्तर संभाग के युवाओं ने भाग लिया, वहीं ऐसा पहली बार हुआ कि नक्सल पीड़ित परिवारों के लोग और पुनर्वास कर चुके 300 नक्सल युवाओं ने भी बढ़-चढ़कर प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। पूवर्ती की ही पुनर्वास कर चुकी मुचाकी रनवती ने संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक में पहला स्थान प्राप्त किया। वर्तमान में मुचाकी पुनर्वास केंद्र सुकमा में सिलाई और राजमिस्त्री का प्रशिक्षण लेकर अपना नया भविष्य गढ़ रहीं हैं।

बंदूक से मेहंदी तक: लौटती बचपन और स्त्री अस्मिता

पुनर्वास केंद्रों में छोटी बच्चियों ने भी पुनर्वास किया है, जो 15, 20 और 25 साल की हैं। ऐसी बच्चियों ने अपने जीवन के इस किशोरावस्था को जंगलों में बिताया है। जब उन बच्चियों से एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता ने पूछा कि क्या तुम मेहंदी लगाओगी, तो वे भावुक हो गईं। यह बीजापुर के पुनर्वास केंद्र की एक वास्तविक घटना है। बच्चियों ने कहा कि अगर मिल जाएगा तो जरूर लगाएंगी। महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शृंगार के सारे सामान ले जाकर के उनके साथ ज़मीन पर बैठकर, उनको मेहंदी लगाई और शृंगार किया। बच्चियां अपने आप को देखकर स्तब्ध हो गईं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। यह कल्पना की जा सकती है कि 25 वर्ष तक पैंट शर्ट पहनकर एक बच्ची को जंगलों में बंदूक लेकर घुमाया गया, उसके मौलिक भावनाओं का क्या हश्र हुआ होगा, और उस बच्ची को उस समय कैसा लगा होगा, जब मेहंदी उसके हाथों में लगाई गई। नक्सलियों ने उनका यह मौलिक अधिकार भी छीन लिया था। आज बस्तर में सभी बच्चियां घर वापस आ चुकी हैं। पुनर्वास केन्द्रों में उन्हें महिला होने का एहसास हो रहा है। अब वे आजाद होकर सामान्य जीवन जी रही हैं, जैसा जीवन उनका होना चाहिए।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 17 नवंबर, 2025 को बस्तर में 'पंडुम कैफे' का शुभारंभ किया।

पीड़ितों ने देश को सुनाई नक्सल हिंसा की सच्चाई

नक्सल हिंसा का एक आयाम उसके द्वारा फैलाई गई भ्रांति भी थी, जिसे दूर करते हुए 55 माओवादी हिंसा से पीड़ित लोगों ने दिल्ली कूच किया। जहां उन्होंने 'केंजा नक्सली-मनवा माटा' (सुनो नक्सली हमारी बात) के तहत नक्सल हिंसा की अपनी करूण वेदनाओं को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने रखा और जंतर-मंतर तथा जेएनयू से नक्सल हिंसा का असली स्वरूप सबको बताया। बताया कि कैसे लोग दिल्ली में जिन आतंकियों के गुणगान करते हैं, उन्होंने बस्तर के स्वर्ग को बारूद के धुएं में समाहित कर दिया है। किसी ने अपने पिता को खोया, किसी ने अपनी आंख, किसी के दोनों हाथ ही नहीं बचे। उन्होंने कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में राष्ट्रीय मीडिया के सामने अपनी दुखद कथा को बयां किया।

कभी बंदूक थामने वाले हाथ अब परोस रहे हैं स्वादिष्ट व्यंजन

बस्तर में बदलाव और पुनर्वास की एक प्रेरणादायक कहानी के रूप में लक्ष्मू पोयाम और पूलमाथी मंडावी आज नई पहचान बना रहे हैं। दोनों कम उम्र में माओवादी संगठन के प्रभाव में आकर उससे जुड़ गए थे। बस्तानार क्षेत्र के जमगांव निवासी लक्ष्मू वर्ष 2006 में मात्र 14 वर्ष की उम्र में संगठन में शामिल हुए, जबकि लोहांडीगुड़ा क्षेत्र की पूलमाथी मंडावी वर्ष 2009 में इसी रास्ते पर चली गईं। गांवों में आयोजित बैठकों और भावनात्मक प्रचार के प्रभाव में आकर दोनों ने हथियारबंद आंदोलन को अपना भविष्य मान लिया था। समय के साथ लक्ष्मू संगठन में डीवीसीएम रैंक तक पहुंचे और गुरिल्ला कमांडर के रूप में कार्य करने लगे। वहीं पूलमाथी प्लाटून कमांडर बनीं। दोनों ने जंगलों में रहकर हथियार चलाने और गुरिल्ला गतिविधियों का प्रशिक्षण लिया। लेकिन वर्षों तक लगातार संघर्ष, असुरक्षा, कठिन जीवन और भविष्य की अनिश्चितता ने उन्हें यह महसूस कराया कि हिंसा का रास्ता केवल भय और नुकसान की ओर ले जाता है। सरकार की पुनर्वास नीति, विश्वास निर्माण के प्रयासों और मुख्यधारा में लौटने वालों को मिल रहे सहयोग से प्रभावित होकर दोनों ने जनवरी 2025 में आत्मसमर्पण कर नई जिंदगी की शुरुआत की। आज वे पंडुम कैफे पहल से जुड़कर सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन जी रहे हैं। कभी बंदूक थामने वाले हाथ अब लोगों को स्वादिष्ट व्यंजन खिलाने का काम कर रहे हैं। अब उनका जीवन भय और बंदूक के साए से निकलकर शांति, स्वतंत्रता और सम्मान की ओर बढ़ चुका है। ❑

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

रणनीति

कुलदीप सिंह

नक्सल-मुक्त भारत एक निर्णायक रणनीतिक बदलाव

नक्सल-मुक्त भारत की कहानी सिर्फ सेना या पुलिस की कामयाबी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एकीकृत शासन-व्यवस्था की कहानी है। जो यह दर्शाती है कि मज़बूत राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत समन्वय, पेशेवर सुरक्षा अभियान और विकास के प्रति प्रतिबद्धता किस तरह से मिलकर लंबे समय से चले आ रहे उग्रवाद का सामना कर उसे खत्म कर सकती है।

नक्सल-मुक्त भारत का दृष्टिकोण सुरक्षा लक्ष्य के उद्देश्य से कहीं ज्यादा है। यह नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुशासन बहाल करने, विकास को बढ़ावा देने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजूबत करने की दिशा में केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नक्सलवाद दशकों तक भारत की सबसे गंभीर आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में से एक बना रहा। जिसने (नक्सल) विकास कार्यों को बाधित कर, सुरक्षाकर्मियों को निशाना बनाकर और सामाजिक-आर्थिक कमज़ोरियों का फायदा उठाकर मध्य और पूर्वी भारत के बड़े हिस्सों को प्रभावित किया। हालांकि, हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है। गृह मंत्रालय ने निरंतर सुरक्षा अभियानों, मज़बूत केंद्र-राज्यों के बीच मज़बूत समन्वय, विकास आधारित योजनाओं और रणनीतिक नेतृत्व के माध्यम से नक्सल खतरे को खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

इस बदलाव के केंद्र में यह समझ थी कि नक्सल चुनौती से केवल बल प्रयोग के जरिए नहीं निपटा जा सकता। इसके लिए सुरक्षा अभियानों के साथ सुशासन, बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी योजनाओं को जोड़ते हुए 'व्होल-ऑफ-गवर्नमेंट' यानी समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाया गया। यद्यपि क़ानून-व्यवस्था संवैधानिक रूप से राज्य का विषय है और नक्सल विरोधी अभियानों में राज्य पुलिस अग्रिम मोर्चे पर रही, लेकिन गृह मंत्रालय ने रणनीतिकार, समन्वयक और बल गुणक (फोर्स मल्टीप्लायर) की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह अंतर महत्वपूर्ण है कि अभियान का संचालन राज्यों ने किया, लेकिन इसकी संरचनात्मक और रणनीतिक दिशा भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने तय की।

गृह मंत्रालय ने मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) को खत्म करने के उद्देश्य से 'समाधान' सिद्धांत (स्मार्ट लीडरशिप, एग्रेसिव स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डैशबोर्ड बेस्ड केआरए एंड केपीआई, हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, एक्शन प्लान फॉर इच थिएटर एंड नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग) के माध्यम से एक बहुआयामी, जीरो टॉलरेंस नीति तैयार की। मार्च 2026 तक,

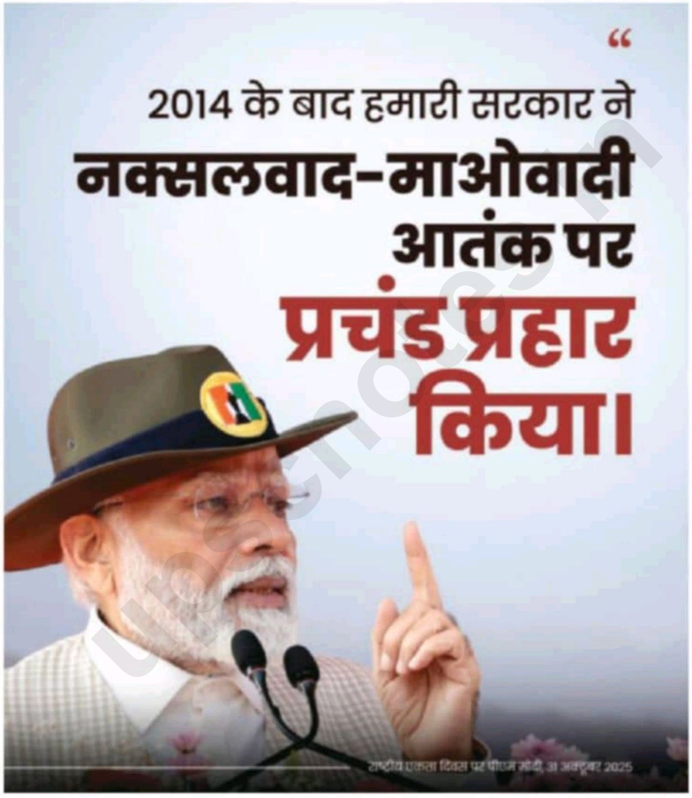

लेखक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्होंने सीआरपीएफ में एडीजी और एसडीजी-सेंट्रल ज़ोन के पद पर रहते हुए वर्ष 2017 से 2021 के दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कई बड़े नक्सल विरोधी अभियानों का नेतृत्व किया। उन्होंने सीआरपीएफ और एनआईए में महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया। वर्तमान में वे मणिपुर सरकार के सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं।
ईमेलः advisorsec.manipur@gmail.com

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

सुरक्षा बलों ने उन्नत ख़ुफ़िया जानकारी, फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस और 'रेड कॉरिडोर' में विकास के माध्यम से लगभग सभी सीपीआई (माओवादी) नेतृत्व को निष्क्रिय कर दिया और अब 'ग्रोथ कॉरिडोर' पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

मुख्य परिवर्तनकारी रणनीतियां और कार्यनीति (2014-2026)

नेतृत्व और नीति परिवर्तन

गृह मंत्रालय के तहत अपनाई गई जीरो-टॉलरेंस नीति में प्रतिक्रियात्मक कदमों के बजाय सक्रिय अभियानों पर ज़ोर दिया गया, जिसका उद्देश्य वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) को मिलने वाले वैचारिक, वित्तीय और रसद संबंधी समर्थन को समाप्त करना था। वहीं गृह मंत्रालय के एलडब्ल्यूई विभाग ने एक 'राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना (2015)' लागू की, जिसमें "ट्रेस, टारगेट, न्यूट्रलाइज" रणनीति को प्राथमिकता दी गई। साथ ही विकास और सुरक्षा के समन्वय को इसके प्रमुख परिणाम के रूप में निर्धारित किया गया।

फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसः सुरक्षा नियंत्रण का विस्तार

नक्सलवाद के खिलाफ हालिया सफलता की एक प्रमुख विशेषता केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) - मुख्य रूप से सीआरपीएफ (केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल) (जिसमें कोबरा - कमांडो बटालियन फॉर रेसोल्यूट एक्शन यूनिट्स शामिल हैं), बीएसएफ (सीमा सुरक्षा बल), आईटीबीपी (भारत-तिब्बत सीमा पुलिस) और एसएसबी (सशस्त्र सीमा बल) की बढ़ी हुई भूमिका रही है। इन सुरक्षाबलों ने नक्सल विरोधी अभियानों की रीढ़ के रूप में कार्य करते हुए राज्य पुलिस को मारक क्षमता, ख़ुफ़िया जानकारी और रणनीतिक सहयोग प्रदान किया।

वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) विरोधी अभियानों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के रूप में सीआरपीएफ (विशेष रूप से कोबरा बटालियन) ने नक्सल प्रभावित इलाकों में फिर से नियंत्रण स्थापित करने, उग्रवादियों के ठिकानों को ध्वस्त करने और घने जंगलों में टारगेटेड अभियान चलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन इलाकों में माओवादी समूहों को पारंपरिक रूप से सामरिक लाभ प्राप्त होता था।

नक्सल प्रभावित इलाकों में उग्रवादियों की पकड़ कमज़ोर करने और सुरक्षा शून्य पैदा करने के उद्देश्य से 350 से अधिक सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए। इन कैंपों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के साथ-साथ राज्य पुलिस की विशेष इकाइयां भी शामिल हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट रिज़र्व गार्ड, महाराष्ट्र के सी-60 कमांडो, ओडिशा के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) और झारखंड के जैगुआर बल प्रमुख हैं। इन संयुक्त सुरक्षा कैंपों की भूमिका सिर्फ अभियानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इन्होंने क्षेत्र में सुरक्षा नियंत्रण मज़बूत करने, सड़कों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने, चुनावों के दौरान मतदान केंद्रों की रक्षा करने और दुर्गम इलाकों में प्रशासन की वापसी में अहम योगदान दिया। सुरक्षा व्यवस्था मज़बूत होने के बाद इन इलाकों में फिर से स्कूल खुलने लगे, सड़कें बनने लगी, और दूर-दराज़ के गांवों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंची और सरकारी योजनाओं का लाभ ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचना संभव हो सका।

आक्रामक अभियानों से नक्सली नेतृत्व पर निर्णायक प्रहार

अब रणनीति निष्क्रिय रोकथाम से आगे बढ़कर आक्रामक और सक्रिय अभियानों पर केंद्रित हो गई है। संयुक्त ऑपरेशन बेस (350 से अधिक) की स्थापना के साथ, 'ऑपरेशन ऑक्टोपस', 'ऑपरेशन डबल-बुल' और 'ऑपरेशन बूढ़ा पहाड़' चलाया गया। इन ऑपरेशन के तहत सुरक्षा बलों ने नक्सली नेतृत्व और उनके कमांड संरचना को सफलतापूर्वक निशाना बनाया, जिसके परिणामस्वरूप 2025 में 300 से अधिक नक्सलियों को मार गिराया गया और 200 से अधिक को गिरफ्तार किया गया। सीपीआई (माओवादी) के शीर्ष नेतृत्व को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। जिसमें 21 टॉप लीडर्स में से 12 को मार गिराया गया, सात ने आत्मसमर्पण किया और एक को गिरफ्तार किया गया। हालांकि एक नेता अभी भी फरार है।

राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर नज़र बनाए रखने में गृह मंत्रालय की नेतृत्वकारी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। उग्रवाद-विरोधी अभियान अक्सर तब विफल हो जाते हैं जब ध्यान अस्थायी या बिखरा हुआ होता है। इसके विपरीत, नक्सल विरोधी रणनीति को निरंतरता, नियमित निगरानी और स्पष्ट रूप से तय लक्ष्यों का लाभ मिला है। इस निरंतर संस्थागत प्रयास ने यह सुनिश्चित किया है कि सुरक्षा अभियानों के माध्यम से प्राप्त लाभों को शासन और विकासात्मक योजनाओं के माध्यम से सुदृढ़ किया जाए।

"समग्र सरकारी दृष्टिकोण" के माध्यम से प्रभावी ऑपरेशनल समन्वय

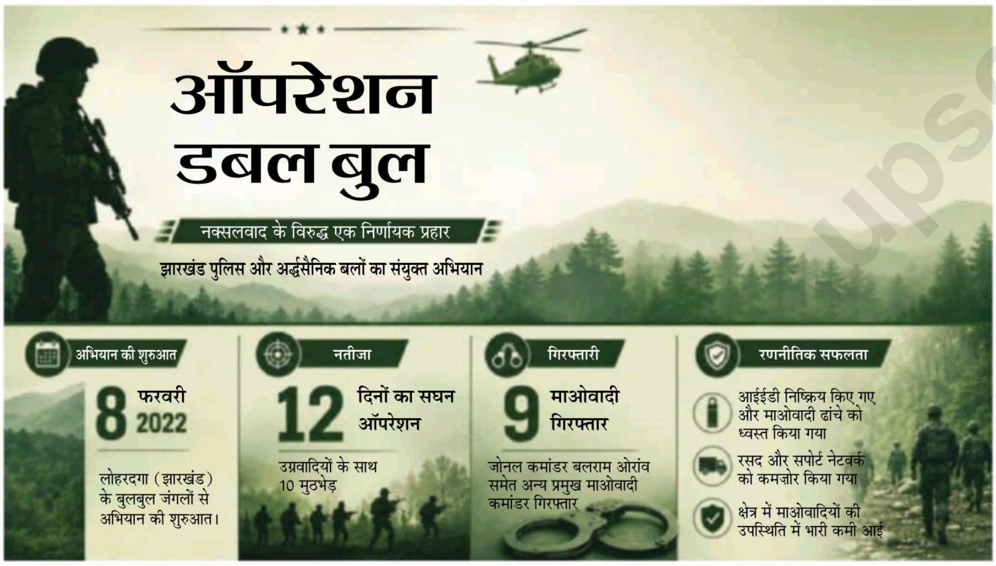

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

हासिल किया गया है, जिससे दूर-दराज़ के इलाकों में सुरक्षा की कमी दूर हुई है। मल्टी-एजेंसी सेंटर को सभी सुरक्षा बलों को रियल टाइम ख़ुफ़िया जानकारी प्रदान करने का अधिकार दिया गया है। सीएपीएफ और राज्य पुलिस बलों के बीच अभियानों में बेहतर तालमेल बैठाने के उद्देश्य से 15 नए ज्वाइंट टास्क फोर्स गठित किए गए हैं। माओवादियों के वित्तीय संसाधनों को सीमित करने के लिए गृह मंत्रालय में (वर्ष 2016) दो मल्टी डिसिप्लिनरी समूह भी स्थापित किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप करीब 40 करोड़ रुपये ज़ब्त किए जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक नवंबर, 2025 को छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में एक प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए।

'नक्सल-मुक्त भारत' की दिशा में एक और महत्वपूर्ण रणनीति केवल हथियारबंद नक्सलियों को निशाना बनाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि उग्रवाद के पूरे समर्थन तंत्र और ढांचों को खत्म करने की भी रही। इसके साथ ही भर्ती, रसद, जबरन वसूली नेटवर्क और प्रचार मशीनरी को बाधित करने के प्रयासों ने माओवादी समूहों की संगठनात्मक क्षमता को कमज़ोर कर दिया। साथ ही, आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीतियों ने नक्सली कैडरों को मुख्यधारा में फिर से शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया है, जिससे उग्रवाद की ताकत और भी कम हो गई है।

सुरक्षा के साथ विकास और अधिकारों का समावेश

गृह मंत्रालय की रणनीतिक दिशा एक बहु-आयामी राष्ट्रीय दृष्टिकोण के कार्यान्वयन के माध्यम से स्पष्ट रूप से दिखाई दी है, जिसमें सुरक्षा, विकास, अधिकार और सुविधाएं तथा जनसंपर्क को साथ लेकर चलने की नीति अपनाई गई। इसके अंतर्गत राज्यों को पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, प्रभावित जिलों में बुनियादी ढांचे के विकास और क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों, दूरसंचार, कौशल विकास, शिक्षा और बैंकिंग सुविधाओं से जुड़ी केंद्रीय योजनाओं ने सीधे तौर पर उन परिस्थितियों को कमज़ोर किया, जिनका फायदा उग्रवादी संगठन उठाने की कोशिश करते थे।

सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) में 155 प्रतिशत की वृद्धि की गई है और पिछले 11 वर्षों में परिचालन आवश्यकताओं, प्रशिक्षण और आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों के पुनर्वास के लिए 3,371 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसी तरह, विशेष अवसंरचना योजना (एसआईएस) में विशेष राज्य बलों और ख़ुफ़िया शाखाओं को मज़बूत करने के लिए 371 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। 246 सुदृढ़ पुलिस स्टेशनों (एफपीएस) के निर्माण के लिए 620 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। इसके अतिरिक्त, गतिशीलता बढ़ाने, नाइट लैंडिंग हेलीपैड, निगरानी प्रणाली, ड्रोन ट्रैकिंग, एआई आधारित डेटा एनालिटिक्स, जीआईएस मैपिंग, ख़ुफ़िया तंत्र के उन्नयन आदि पर भी भारी राशि खर्च की गई।

रेड कॉरिडोर से विकास कॉरिडोर तक

निर्णायक कारक अभूतपूर्व केंद्र-राज्य समन्वय रहा है, जो अब केवल समय-समय पर होने वाले सहयोग से आगे बढ़कर एक संस्थागत साझेदारी में बदल गया। इस परिवर्तन की बागडोर गृह मंत्रालय के हाथों में रही है। नियमित सुरक्षा समीक्षा, संयुक्त परिचालन योजना, ख़ुफ़िया जानकारी साझा करने की व्यवस्था और प्रभावित राज्यों को लक्षित सहायता प्रदान करके, गृह मंत्रालय ने सभी क्षेत्रों में एक ही उद्देश्य को बनाए रखने का प्रयास किया है। इन प्रयासों के जरिए सरकार का लक्ष्य 'रेड कॉरिडोर' के दौर को समाप्त करना है और उसकी जगह सड़कों, स्कूलों तथा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) जैसी विकास परियोजनाओं को स्थापित करना है, ताकि नक्सलवाद के प्रभाव को स्थायी रूप से खत्म किया जा सके।

महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य की रणनीति में अब स्थानीय समुदायों का विश्वास जीतने पर अधिक ज़ोर दिया जा रहा है। यह इसलिए भी अहम है क्योंकि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई केवल सशस्त्र हिंसा को समाप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकों का राज्य व्यवस्था पर विश्वास बहाल करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। कई क्षेत्रों में सुरक्षा बलों और नागरिक प्रशासन ने आदिवासी समुदायों तथा वंचित वर्गों के साथ बेहतर संवाद और सहभागिता स्थापित करने की दिशा में काम किया है। जनकल्याणकारी कार्यक्रमों, नागरिक

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

छत्तीसगढ़ के बस्तर में जन सेवा केंद्र का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

सहायता अभियानों और जवाबदेह प्रशासन ने उस अलगाव की भावना को कम करने में मदद की है, जिसका फायदा उग्रवादी पहले उठाते थे।

दुर्गम क्षेत्रों में सतर्कता की निरंतर आवश्यकता

पहले नक्सल प्रभावित रहे कई जिलों में नक्सली हिंसा में आई कमी इस बात का प्रमाण है कि इस रणनीति से सकारात्मक परिणाम मिले हैं। जिन क्षेत्रों को कभी उग्रवादियों का गढ़ माना जाता था, वहां अब शासन व्यवस्था बहाल हो गई है, संपर्क व्यवस्था बेहतर हुई है, आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में नागरिकों की भागीदारी भी बढ़ी है। पहले अशांत रहे क्षेत्रों में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए चुनाव इस परिवर्तन का सशक्त प्रतीक हैं। नक्सल-मुक्त भारत की उपलब्धि के साथ, भारत ने एक ऐतिहासिक पड़ाव हासिल किया है। फिर भी, उग्रवाद के कुछ क्षेत्र अभी भी मौजूद हैं, विशेष रूप से उन दुर्गम इलाकों में जहां चरमपंथी समूह फिर से संगठित होने का प्रयास करते हैं। इसलिए, निरंतर सतर्कता आवश्यक है। नक्सल-रोधी अभियानों की सफलता तभी स्थायी सिद्ध हो सकती है, जब उसके साथ निरंतर विकास, उत्तरदायी शासन और संस्थागत सुदृढ़ता भी सुनिश्चित की जाए।

आगे बढ़ते हुए, नक्सल विरोधी अभियान से मिले अनुभव आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक मॉडल प्रस्तुत करते हैं। पहला, सुरक्षा संबंधी कदम तब सबसे अधिक प्रभावी होते हैं जब उन्हें विकास और सुशासन के साथ जोड़ा जाए। दूसरा, जटिल और विभिन्न क्षेत्रों में फैले खतरों से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच मज़बूत समन्वय अनिवार्य है। तीसरा, विशेष रूप से गृह मंत्रालय जैसी संस्थाओं के माध्यम से केंद्रीय नेतृत्व दीर्घकालिक सफलता के लिए आवश्यक रणनीतिक एकरूपता प्रदान कर सकता है, भले ही संचालन की मुख्य जिम्मेदारी राज्यों के पास हो और चौथा, सीआरपीएफ तथा अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जैसे पेशेवर और परिस्थितियों के अनुरूप ढलने वाले सुरक्षा बल देश की आंतरिक सुरक्षा के महत्वपूर्ण स्तंभ बने रहेंगे।

समन्वित शासन प्रबंधन की एक मिसाल

इस प्रकार, 'नक्सल-मुक्त भारत' की कहानी केवल सैन्य या पुलिसिंग की सफलताओं तक सीमित नहीं है। यह समन्वित शासन-प्रबंधन की एक मिसाल है। यह दर्शाती है कि किस प्रकार राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत समन्वय, पेशेवर सुरक्षा अभियान और विकास के प्रति प्रतिबद्धता मिलकर लंबे समय से चली आ रही उग्रवादी चुनौती का सामना कर सकते हैं और उसे समाप्त कर सकते हैं। इस अभियान में राज्य पुलिस ने अग्रणी भूमिका निभाई है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) - विशेष रूप से सीआरपीएफ (सीआरपीएफ) ने एक मज़बूत परिचालन आधार के रूप में कार्य किया, जबकि गृह मंत्रालय ने वह रणनीतिक दिशा प्रदान की जिसने पूरे ढांचे को एकजुट बनाए रखा।

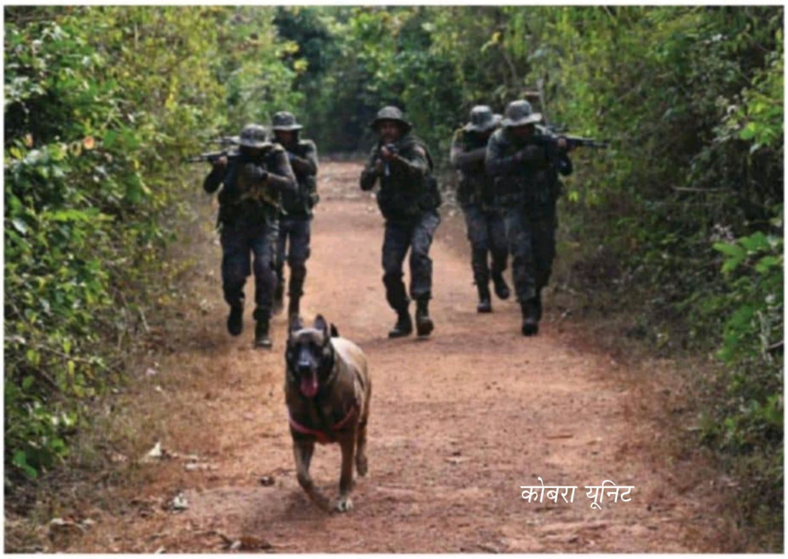

कोबरा यूनिट

नक्सल-मुक्त भारत की यह उपलब्धि सहकारी संघवाद की शक्ति, सुरक्षा बलों की पेशेवर क्षमता और भारतीय राज्य की उस स्थायी सामर्थ्य का प्रमाण बनकर उभरती है, जिसके माध्यम से सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी शांति, व्यवस्था और विकास को पुनर्स्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार, 'नक्सल-मुक्त भारत' केवल सुरक्षा के क्षेत्र में हासिल की गई एक उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय संकल्प और लोकतांत्रिक दृढ़ता की पुनर्पुष्टि भी है। ❑

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

समन्वित कार्रवाई

राजीव कुमार

वामपंथी उग्रवाद उन्मूलन के लिए केंद्र-राज्य समन्वित सरकारी रणनीति

वर्ष 1967 के नक्सलबाड़ी आंदोलन से शुरू होकर मार्च 2026 में भारत को वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) मुक्त घोषित किए जाने तक की यात्रा, स्वतंत्र भारत की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक को दर्शाती है। यह सिद्ध करता है कि गहराई तक जड़ जमा चुके उग्रवादी आंदोलनों का समाधान सुरक्षा अभियानों, विकास पहल, उत्तरदायी शासन तथा सामुदायिक सहभागिता की समन्वित और संतुलित रणनीति के माध्यम से किया जा सकता है।

30 मार्च, 2026 का दिन भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बन गया। इसी दिन संसद में लोकसभा के पटल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की- "मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम नक्सलवाद से मुक्त हो चुके हैं।"

दशकों पुरानी वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) की समस्या से भारत का मुक्त होना कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। मुश्किल से ढाई वर्ष पहले, जब गृह मंत्री ने 31 मार्च, 2026 तक भारत को वामपंथी उग्रवाद मुक्त बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया था, तब बहुत कम लोगों को विश्वास था कि यह संभव हो पाएगा। लेकिन पिछले एक दशक में सुरक्षा और विकास के मोर्चों पर सुव्यवस्थित तथा दृढ़तापूर्वक लागू की गई अनेक पहल के कारण यह असंभव प्रतीत होने वाली उपलब्धि हासिल की जा सकी।

वामपंथी उग्रवाद की वैचारिक जड़ें

भारत में वामपंथी उग्रवाद की जड़ें 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में हुए नक्सलबाड़ी विद्रोह से जुड़ी हैं। यह भारतीय राज्य व्यवस्था को चुनौती देने वाले सशस्त्र माओवादी आंदोलन की शुरुआत थी। 1969 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के गठन ने इस आंदोलन को वैचारिक संरचना और दिशा प्रदान की। चारु मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल जैसे नेताओं ने माओ त्से तुंग से प्रेरित होकर लोकतांत्रिक माध्यमों के बजाय सशस्त्र क्रांति के जरिए सत्ता हासिल करने की बात कही। 1970 के दशक में पुलिस की कड़ी कार्रवाई से यह आंदोलन कमज़ोर पड़ा और अस्थायी रूप से इसका पतन हुआ।

1980 के दशक में विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में पीपुल्स वॉर ग्रुप के उदय के साथ यह आंदोलन पुनः उभरा और धीरे-धीरे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड तथा ओडिशा तक फैल गया। यद्यपि विभिन्न माओवादी गुट अक्सर आपस में प्रतिस्पर्धा करते थे, लेकिन 2004 में वे एकजुट होकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के रूप में संगठित हुए, जो बाद में भारत के बड़े हिस्सों में वामपंथी उग्रवाद हिंसा को संचालित करने वाला प्रमुख संगठन बन गया।

रणनीति और कार्यप्रणाली

माओवादी आंदोलन का उद्देश्य भारत की संवैधानिक शासन व्यवस्था को हिंसक क्रांति के माध्यम से उखाड़ फेंकना रहा है, जिसे वे "दीर्घकालिक जनयुद्ध" कहते हैं। भूमि विवाद, गरीबी और सामाजिक असमानता जैसी समस्याओं का लाभ उठाकर माओवादी समूह धीरे-धीरे आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा और आसपास के राज्यों में फैल गए।

हालांकि, यह समझना महत्वपूर्ण है कि नक्सलवाद का प्रसार केवल पिछड़ेपन का परिणाम नहीं था। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमालयी क्षेत्र के कई जिलों में सामाजिक-आर्थिक स्थिति समान या उससे भी खराब थी, फिर भी वहां माओवादी विस्तार नहीं हुआ। माओवादियों ने रणनीतिक रूप से ऐसे क्षेत्रों का चयन किया जहां घने जंगल, दुर्गम भूभाग और शासन व्यवस्था की कमज़ोर उपस्थिति थी, जो गुरिल्ला युद्ध संचालन के लिए रणनीतिक रूप से अनुकूल थे।

कमज़ोर संपर्क व्यवस्था और सीमित सरकारी उपस्थिति का फायदा उठाकर माओवादियों ने छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पड़ोसी क्षेत्रों के दूरस्थ जनजातीय जिलों में अपने गढ़

लेखक गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव (वामपंथी उग्रवाद) के पद पर कार्यरत हैं। ईमेलः jslwe-mha@nic.in

upscnotes.in

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक नवंबर, 2025 को छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का अवलोकन किया।

स्थापित किए। एक बार मज़बूत पकड़ बना लेने के बाद उन्होंने थानों, पंचायत भवनों और सरकारी ढांचों पर हमले करके तथा अधिकारियों को डराकर स्थानीय शासन व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से कमज़ोर किया।

इसके बाद उन्होंने तथाकथित 'मुक्त क्षेत्रों' में 'जनताना सरकार' नामक समानांतर शासन व्यवस्था स्थापित की। ये संरचनाएं स्थानीय लोगों से वसूली करती थीं, ठेकेदारों से जबरन धन ऐंठती थीं और 'जन न्याय' के नाम पर 'कंगारू अदालतें' चलाती थीं। जनजातीय समुदायों को लोकतांत्रिक संस्थाओं और सरकारी एजेंसियों से दूर करने के लिए सरकार विरोधी दुष्प्रचार अभियानों का सहारा लिया गया।

भय और दबाव के इस माहौल में अनेक जनजातीय युवक-युवतियां स्वेच्छा से या मज़बूरी में माओवादी कैडर में शामिल हो गए। कई मामलों में गरीब परिवारों को अपने बच्चे माओवादियों को सौंपने के लिए मज़बूर किया गया ताकि उनका कैडर मज़बूत हो सके। यही एक प्रमुख कारण था कि माओवादी संगठनों में महिला कैडरों की संख्या भी काफी अधिक रही।

माओवादियों ने विकास कार्यों, विशेषकर सड़कों, पुलों, रेलवे लाइनों और मोबाइल टावरों का भी सक्रिय रूप से विरोध किया, क्योंकि उन्हें डर था कि बेहतर संपर्क व्यवस्था से सुरक्षा बलों की कार्रवाई आसान हो जाएगी। परिणामस्वरूप शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बैंकिंग और वित्तीय समावेशन से जुड़ी सरकारी योजनाएं दूर-दराज़ के गांवों तक नहीं पहुंच सकीं। विडंबना यह रही कि जो समूह स्वयं को गरीबों का प्रतिनिधि बताते थे, वही इन समुदायों के विकास में सबसे बड़ी बाधा बन गए।

वामपंथी उग्रवादी हिंसा का चरम दौर

2004 में सीपीआई (माओवादी) के गठन के बाद वामपंथी उग्रवाद की हिंसा में तेज़ बढ़ोतरी हुई और 2009-10 के दौरान यह अपने चरम पर पहुंच गई, जबकि इस संगठन को गैरक़ानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम के तहत प्रतिबंधित किया जा चुका था। वर्ष 2010 में हिंसा की 1,936 घटनाएं और 1,005 मौतें दर्ज की गईं। इस दौरान सिल्दा कैंप हमला और दंतेवाड़ा के ताड़मेटला में घात लगाकर हमला जैसी बड़ी घटनाएं हुईं, जिनमें 76 सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु हुई।

दशकों तक माओवादियों ने जनजातीय क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए नागरिकों, सुरक्षा बलों, आधारभूत संरचना और विकास परियोजनाओं को निशाना बनाया। जीरम घाटी हमला जैसी घटनाओं ने इस उग्रवाद की क्रूरता को और स्पष्ट किया। कुल मिलाकर, वामपंथी उग्रवाद की हिंसा में लगभग 8,600 नागरिकों की जान गई, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। साथ ही, इससे प्रभावित क्षेत्रों के विकास पर गंभीर असर पड़ा।

सुरक्षा, विकास और विश्वास निर्माण पर समान ज़ोर

जब वामपंथी उग्रवाद अपने सबसे व्यापक और हिंसक स्वरूप में था, तब इसका प्रभाव भारत के लगभग एक-तिहाई जिलों तक फैल चुका था। तिरुपति से पशुपतिनाथ तक फैले इस विस्तृत क्षेत्र को

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

तथाकथित रूप से "रेड कॉरिडोर" के नाम से जाना जाता था। यह समझते हुए कि इस चुनौती का समाधान व्यापक रणनीति से ही संभव है, भारत सरकार ने 2015 में "समन्वित प्रयास" पर आधारित एक नीति और कार्य योजना तैयार की।

इस रणनीति के चार प्रमुख स्तंभ थे:

- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा उपायों को मज़बूत करना
- प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को तेज़ करना
- स्थानीय समुदायों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना
- विश्वास निर्माण पहल के माध्यम से स्थानीय आबादी से संपर्क बढ़ाना

केंद्र और राज्यों द्वारा इस रणनीति के समन्वित कार्यान्वयन से महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या 2015 में 126 से घटकर मार्च 2026 तक शून्य हो गई।

सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करना

क़ानून-व्यवस्था राज्य का विषय है, इसलिए वामपंथी उग्रवाद रोधी अभियानों में राज्य पुलिस बलों को प्रमुख हितधारक और अग्रणी बल माना गया। इसी के अनुरूप प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा ढांचे को मज़बूत करने तथा सुरक्षा संबंधी रिक्तता को समाप्त करने के लिए विशेष प्रयास किए गए।

सुरक्षा संबंधी रिक्तता को भरना

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित मुख्य क्षेत्रों में सुरक्षा शिविर स्थापित करने को प्राथमिकता दी गई। इसका उद्देश्य प्रत्येक पांच किलोमीटर पर एक सुरक्षा शिविर स्थापित करना था। इसके परिणामस्वरूप 833 नए सुरक्षा शिविर स्थापित किए गए, जिनमें से 406 शिविर वर्ष 2019 के बाद बनाए गए। केवल वर्ष 2025 में 87 शिविर स्थापित किए गए, जबकि मार्च 2026 तक अतिरिक्त 14 शिविर और स्थापित किए गए।

वर्तमान में, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 121 बटालियनें और लगभग 400 कंपनियां तैनात हैं। इनमें केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) शामिल हैं।

सीआरपीएफ ने बस्तर क्षेत्र के 1,143 स्थानीय युवाओं की भर्ती करके बस्तरिया बटालियन का गठन भी किया। इस पहल से न केवल सुरक्षा अभियानों में स्थानीय भागीदारी मज़बूत हुई, बल्कि जनजातीय युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर भी उत्पन्न हुए।

राज्यों का क्षमता निर्माण

राज्य पुलिस कर्मियों के स्थानीय भूगोल, भाषा और सामाजिक परिस्थितियों से बेहतर परिचित होने के कारण केंद्र सरकार ने उनकी क्षमताओं को मज़बूत करने पर विशेष ज़ोर दिया।

विशेष अवसंरचना योजना (एसआईएस): वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस अवसंरचना को मज़बूत करने के लिए एसआईएस योजना शुरू की गई। इसके अंतर्गत किलेबंद थानों के निर्माण, बेहतर प्रशिक्षण सुविधाओं और ख़ुफ़िया तंत्र को मज़बूत करने पर ध्यान दिया गया।

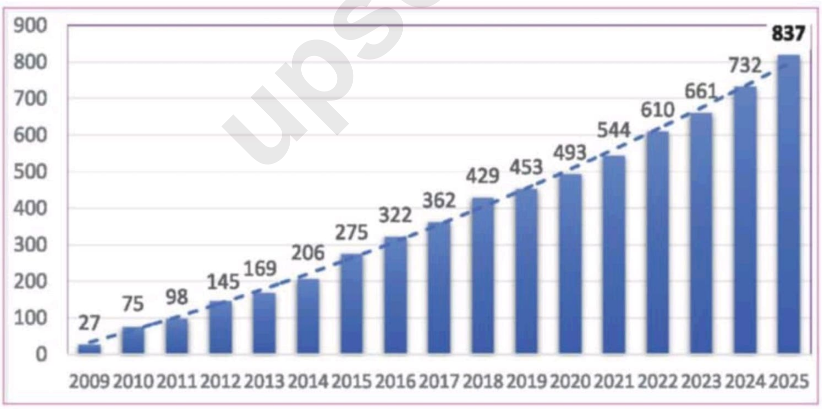

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित सुरक्षा शिविरों की संख्या

upscnotes.in
PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

माओवादी अक्सर हथियार और धन लूटने के लिए थानों को निशाना बनाते थे, इसलिए किलेबंद थानों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई। लगभग 706 किलेबंद थानों को स्वीकृति दी गई, जिनमें से करीब 660 का निर्माण पूरा हो चुका है।

इस योजना के तहत राज्य पुलिस बलों और ख़ुफ़िया इकाइयों के लिए ड्रोन, वाहन, हथियार, गोला-बारूद और अन्य परिचालन उपकरणों की खरीद में भी सहायता प्रदान की गई।

सुरक्षा संबंधी व्यय योजना (एसआरई): एसआरई योजना के अंतर्गत राज्यों को वामपंथी उग्रवाद रोधी अभियानों पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति की जाती है। इसमें प्रशिक्षण, रसद सहायता, सामुदायिक प्रहरी पहल, विशेष पुलिस अधिकारियों का मानदेय, अनुग्रह राशि, आत्मसमर्पण प्रोत्साहन तथा जन-जागरूकता अभियानों से संबंधित व्यय शामिल हैं।

वर्ष 2014-15 से अब तक इस योजना के अंतर्गत 3,756.38 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

वामपंथी उग्रवाद प्रबंधन हेतु केंद्रीय एजेंसियों को सहायता (एसीएएलडब्ल्यूईएम): एसीएएलडब्ल्यूईएम योजना के अंतर्गत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को दूर-दराज़ क्षेत्रों में अवसंरचना विकास तथा हेलीकॉप्टर सहायता जैसी परिचालन आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2014-15 से अब तक इस योजना के तहत 1,249.38 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

अंतरराज्यीय सीमाओं पर संयुक्त कार्य बल

माओवादी कैडर अक्सर सुरक्षा बलों से बचने के लिए अंतरराज्यीय सीमाओं का लाभ उठाते थे। इस चुनौती से निपटने के लिए पड़ोसी राज्यों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के कर्मियों को मिलाकर संयुक्त कार्य बल गठित किए गए। इन इकाइयों को राज्य सीमाओं के पार समन्वित अभियान चलाने की अनुमति दी गई, जिससे अभियानों की परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट (2025)

छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर स्थित कर्रेगुट्टालु पहाड़ियां घने जंगलों और दुर्गम भूभाग के कारण माओवादियों का एक प्रमुख ठिकाना बन गई थीं। अप्रैल-मई 2025 में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट शुरू किया, जिसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस बलों के 10,000 से अधिक जवान शामिल थे। इस अभियान में उस क्षेत्र में दोबारा संगठित हो रहे 400-500 सशस्त्र माओवादी कैडर को निशाना बनाया गया। कई मुठभेड़ों में 31 माओवादी निष्प्रभावी किए गए तथा बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए।

कुल मिलाकर, वर्ष 2025-26 में माओवादियों की ताकत में भारी गिरावट देखी गई। इस दौरान सैकड़ों माओवादी गिरफ्तार हुए, मारे गए या उन्होंने आत्मसमर्पण किया। साथ ही, वित्तीय और गोला-बारूद आपूर्ति शृंखलाओं को बाधित करने के प्रयासों ने सीपीआई (माओवादी) की परिचालन क्षमता को काफी कमज़ोर कर दिया।

एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों का विकास

तेज़ और समावेशी विकास सरकार की रणनीति का दूसरा प्रमुख स्तंभ था। उग्रवादी समूहों ने ऐसे अलग-थलग उग्रवादी गढ़ बना दिए थे जहां शासन और विकास नहीं पहुंच पाता था। विडंबना यह थी कि इस अलगाव का सबसे अधिक नुकसान जनजातीय समुदायों को ही उठाना पड़ा।

इसीलिए सड़कों, रेलवे, दूरसंचार, शिक्षा, बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया।

सड़क संपर्क: सड़क संपर्क को विकास की आधारशिला माना गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए जनसंख्या संबंधी मानदंडों में ढील दी गई, क्योंकि जनजातीय बस्तियां अक्सर बिखरी हुई और कम आबादी वाली होती हैं।

इसके अतिरिक्त, "वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना" के तहत 11,958 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों और 691 पुलों को स्वीकृति दी गई। वहीं, सड़क आवश्यकता योजना के अंतर्गत राज्य राजमार्ग स्तर की अतिरिक्त 5,361 किलोमीटर सड़कों को मंजूरी दी गई।

मुख्य माओवादी क्षेत्रों में, जहां ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं थे, वहां सरकार ने महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं के लिए सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को तैनात किया। इसके परिणामस्वरूप वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में सड़क घनत्व में लगभग 30 प्रतिशत वृद्धि हुई और राजमार्ग संपर्क में लगभग 80 प्रतिशत सुधार हुआ।

रेल संपर्क: रेल संपर्क वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में आर्थिक एकीकरण का प्रमुख प्रेरक बनकर उभरा है। दल्ली राजहरा और रावघाट के बीच 95 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का निर्माण पूरा

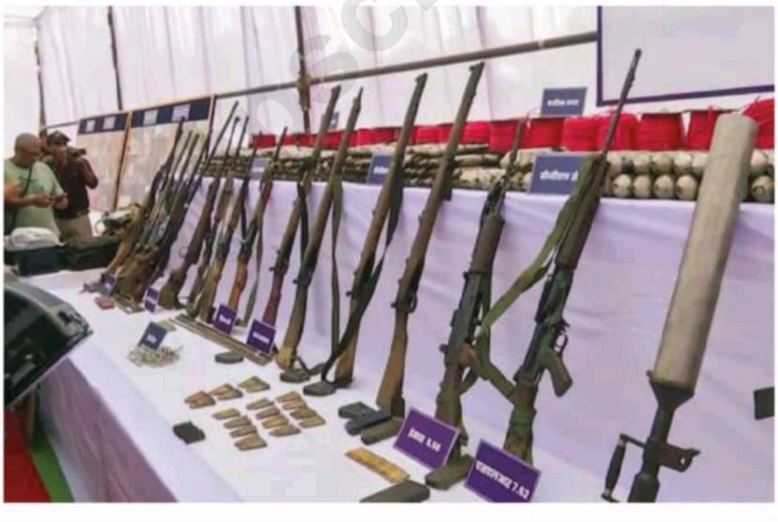

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

हो चुका है, जबकि 140 किलोमीटर लंबी रावघाट-जगदलपुर रेल परियोजना को स्वीकृति मिल चुकी है।

इसके अलावा, दंतेवाड़ा और मनुगुरु के बीच 180 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को भी मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर बस्तर दक्षिण भारत के प्रमुख बाज़ारों से जुड़ जाएगा और स्थानीय समुदायों के लिए व्यापार के अवसर बढ़ेंगे।

दूरसंचार संपर्क: दूरसंचार संपर्क जनजातीय क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का केंद्रीय आधार बन चुका है। दूरसंचार विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत 9,000 से अधिक मोबाइल टावर लगाए गए तथा कई 2जी टावरों का 4जी में उन्नयन किया गया।

आज वामपंथी उग्रवाद से गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों के लगभग 96 प्रतिशत गांव मोबाइल संपर्क से जुड़ चुके हैं, जिससे शिक्षा, बैंकिंग, ऑनलाइन सेवाओं और शासन तक पहुंच आसान हुई है।

शिक्षा और कौशल विकास: शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। कुल 259 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) स्वीकृत किए गए, जिनमें से 179 चल रहे हैं।

इसी प्रकार, 48 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और 61 कौशल विकास केंद्र स्वीकृत किए गए, जिनमें से अधिकांश चालू हो चुके हैं। जनजातीय क्षेत्रों की विशेष जनसंख्या परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दूरस्थ वामपंथी उग्रवाद प्रभावित ब्लॉकों में ईएमआरएस विद्यालय खोलने के लिए जनसंख्या मानदंडों में भी छूट दी गई।

वित्तीय समावेशन: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को सुगम बनाने और बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए वित्तीय समावेशन को प्राथमिकता दी गई। इसके तहत:

- 1,804 बैंक शाखाएं और 1,321 एटीएम स्थापित किए गए
- 74,720 बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंस की नियुक्ति की गई
- 2017 से 2024 के बीच 5,731 डाकघर खोले गए
- इन उपायों से दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं की पहुंच में उल्लेखनीय विस्तार हुआ।

स्वास्थ्य सुविधाएं: जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना कई दशकों तक कमज़ोर बनी रही। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए स्थापित फील्ड अस्पतालों को केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देश पर स्थानीय जनजातीय आबादी के लिए भी खोल दिया गया। लगभग 77,000 स्थानीय निवासियों ने इन सुविधाओं में उपचार प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत जगदलपुर में 240 बिस्तरों वाला सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित किया गया। आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में इंटरनेट संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने ऑफलाइन आवेदन प्रणाली शुरू की, जिससे अधिकारी दूरस्थ गांवों में भी कार्ड जारी कर सकें।

उत्तरदायी और समावेशी शासन

सरकार ने यह समझा कि जनजातीय क्षेत्रों में योजनाओं के कार्यान्वयन की चुनौतियों से निपटने के लिए कठोर प्रक्रियाओं के बजाय लचीलेपन तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप उपायों की आवश्यकता है।

आधार कवरेज

दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में लोगों को आधार से जोड़ने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) और डाक विभाग के सहयोग से विशेष अभियान चलाए गए।

मज़दूरी भुगतान

कमज़ोर इंटरनेट कनेक्टिविटी और बैंकिंग अवसंरचना को ध्यान में रखते हुए, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकसित भारत - गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी-राम जी) योजना के पुराने संस्करण के तहत नकद मज़दूरी भुगतान और ऑफलाइन उपस्थिति प्रणाली की अनुमति दी गई।

छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 2022 में लगाया गया मोबाइल टावर

upscnotes.in

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

स्वच्छता पहल

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, जिन क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं पर्याप्त नहीं थीं, वहां शौचालय निर्माण के लिए धनराशि ग्राम स्वच्छता समितियों के माध्यम से वितरित की गई। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि कल्याणकारी योजनाओं की अंतिम छोर तक प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए परिस्थितिनुकूल शासन व्यवस्था कितनी महत्वपूर्ण है।

विशेष केंद्रीय सहायता

महत्वपूर्ण अवसंरचना संबंधी कमियों को दूर करने के लिए गृह मंत्रालय ने वर्ष 2017 में विशेष केंद्रीय सहायता योजना शुरू की। इस योजना के तहत सबसे अधिक प्रभावित जिलों को सालाना 30 करोड़ रुपये दिए गए और संवेदनशील जिलों को सालाना 10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। इस योजना के अंतर्गत लगभग 15,000 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई, जिनमें स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, सड़कें, स्वास्थ्य केंद्र और पेयजल सुविधाएं शामिल हैं। वर्ष 2017 से अब तक इस योजना के तहत 4,097.47 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

स्थानीय समुदायों के अधिकार और हित

जनजातीय अधिकारों की सुरक्षा सरकार की रणनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ था, विशेषकर इसलिए क्योंकि माओवादी अक्सर भूमि और वन अधिकारों से जुड़ी शिकायतों का फायदा उठाते थे। इसी दिशा में, विभिन्न भूमि और वन अधिकार पहल के तहत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 10 राज्यों में लगभग 18 लाख भूमि-पट्टे वितरित किए गए।

स्थानीय समुदायों से संपर्क

सरकार ने वामपंथी उग्रवाद की चुनौती का सामना केवल सुरक्षा उपायों के माध्यम से नहीं, बल्कि सहानुभूति, समावेशन और विश्वास निर्माण के जरिए भी किया।

जनजातीय युवा संपर्क कार्यक्रमः इस कार्यक्रम के अंतर्गत हर वर्ष वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लगभग 5,000 जनजातीय युवाओं को भारत के महत्वपूर्ण शहरों और संस्थानों का दौरा कराया जाता है। इनसे उन्हें भारत की सांस्कृतिक, तकनीकी और संस्थागत विविधता से परिचित होने का अवसर मिलता है तथा राष्ट्रीय मुख्यधारा से उनका जुड़ाव मज़बूत होता है।

नागरिक कार्य कार्यक्रम (सीएपी): केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) स्थानीय समुदायों के साथ विश्वास निर्माण के लिए नागरिक कार्य कार्यक्रम के तहत चिकित्सा शिविर, खेलकूद कार्यक्रम और सामग्री वितरण अभियान आयोजित करते हैं। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात प्रत्येक सीएपीएफ कंपनी को इन गतिविधियों के लिए वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

जनजातीय संस्कृति का उत्सव

बस्तर ओलंपिक और पंडुम उत्सव जैसी पहल ने जनजातीय युवाओं को अपनी सांस्कृतिक पहचान का उत्सव मनाने और उसे प्रदर्शित करने के लिए मंच प्रदान किया है। इन आयोजनों को सोशल मीडिया पर मिली व्यापक पहचान ने स्थानीय समुदायों में गौरव तथा भागीदारी की भावना को और मज़बूत किया है।

आकर्षक आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति

माओवादी संगठनों से जुड़े अनेक लोग वैचारिक प्रतिबद्धता के बजाय भय, दबाव या परिस्थितियों के कारण उसमें शामिल हुए थे। इस वास्तविकता को समझते हुए सरकार ने आकर्षक आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीतियां लागू कीं, जिनके अंतर्गत वित्तीय सहायता, कौशल विकास और पुनर्वास समर्थन प्रदान किया जाता है। पिछले एक दशक में लगभग 10,000 माओवादी कैडर आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में लौट चुके हैं।

उभरती शहरी चुनौती

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगति के साथ-साथ सरकार ने यह भी महसूस किया कि शहरी केंद्रों में सक्रिय माओवादी वैचारिक नेटवर्क से निपटना भी आवश्यक है। इसी के तहत सरकार ने वर्ष 2018 में "शहरी क्षेत्रों में सीपीआई (माओवादी) की गतिविधियों के मुकाबले के लिए कार्ययोजना" शुरू की, जिसका उद्देश्य शहरी समर्थन तंत्र को ध्वस्त करना और माओवादी प्रचार के विरुद्ध वैकल्पिक विमर्श को मज़बूत करना था।

आजीविका के स्थायी अवसर

गृह मंत्रालय वामपंथी उग्रवाद के प्रभाव से मुक्त हुए क्षेत्रों में अब आजीविका के स्थायी अवसर सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके तहत स्थानीय

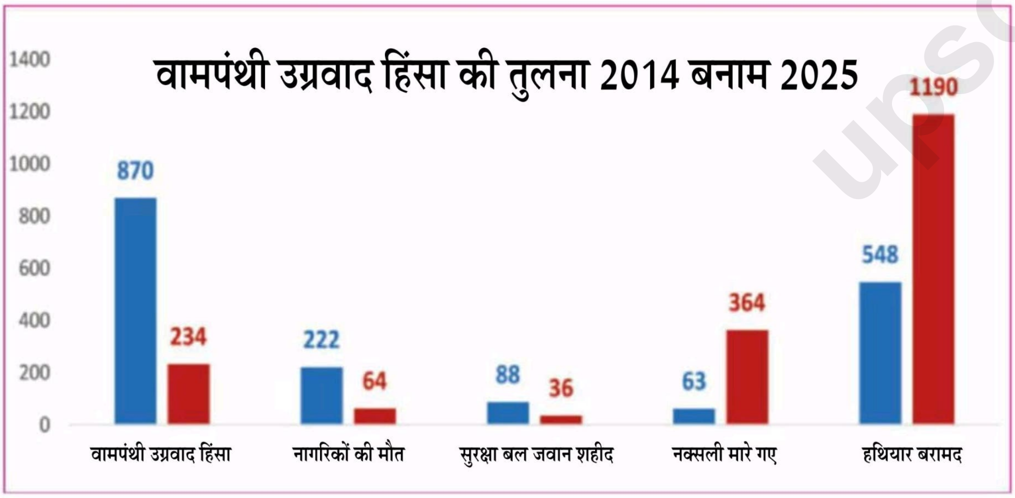

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

संसाधनों, कौशल और लोगों की आकांक्षाओं का जिला स्तर पर मानचित्रण पहले ही पूरा किया जा चुका है तथा दीर्घकालिक विकास योजना तैयार की गई है।

सरकार के प्रयासों के परिणाम ऐतिहासिक रहे हैं:

- वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसक घटनाओं में 88 प्रतिशत की कमी आई हैं। 2010 में जहां 1,936 घटनाएं हुईं वहीं 2025 में यह घटकर 234 रह गईं।
- नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की मौतों में लगभग 90 प्रतिशत की गिरावट आई। 2010 में 1,005 मौतें हुईं जबकि 2025 में 100 मौतें हुईं। अंततः मार्च/अप्रैल 2026 तक वामपंथी उग्रवाद की संगठनात्मक संरचना पूरी तरह ध्वस्त हो गई और उसकी परिचालन क्षमता गंभीर रूप से कमज़ोर पड़ गई। परिणामस्वरूप, वर्तमान समय में देश का कोई भी जिला वामपंथी उग्रवाद प्रभावित नहीं है। वामपंथी उग्रवाद मुक्त भारत का लक्ष्य अब पूर्णतः हासिल कर लिया गया है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि वामपंथी उग्रवाद दोबारा उभर न सके, सरकार वामपंथी उग्रवाद से मुक्ति के बाद एक व्यापक विकास रणनीति लागू कर रही है, जिसके तहत निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है:

- वामपंथी उग्रवाद मुक्त क्षेत्रों में सभी सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करना
- स्थायी आजीविका के अवसरों का निर्माण
- ज़मीनी लोकतंत्र और पंचायती राज संस्थाओं को मज़बूत करना
- पीड़ितों और आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों का पुनर्वास
- जनजातीय सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण
- उत्तरदायी और समावेशी शासन
- पहले पहुंच से बाहर रहे क्षेत्रों तक प्रशासनिक पहुंच का विस्तार
- शांति, विकास और सुशासन के नए युग की शुरुआत।

समन्वित सरकारी रणनीति की सफलता

दशकों तक हिंसा और अलगाव झेलने के बाद वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में अब शांति, सुशासन और विकास के एक नए युग की शुरुआत हुई है। 1967 के नक्सलबाड़ी आंदोलन से शुरू होकर मार्च 2026 में भारत को वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) मुक्त घोषित किए जाने तक की यात्रा, स्वतंत्र भारत की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक को दर्शाती है। यह दिखाती है कि गहराई तक जड़ जमा चुके उग्रवादी आंदोलनों का समाधान संतुलित रणनीति के माध्यम से संभव है, जिसमें सुरक्षा अभियान, विकास पहल, उत्तरदायी शासन और सामुदायिक भागीदारी का समन्वय हो। भारत की समन्वित सरकारी रणनीति की सफलता इस बात का एक महत्वपूर्ण वैश्विक उदाहरण प्रस्तुत करती है कि सहकारी संघीय ढांचे के भीतर समन्वित कार्रवाई के जरिए जटिल आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का प्रभावी समाधान कैसे किया जा सकता है।

हालांकि सुरक्षा संबंधी चुनौती अब काफी हद तक कम हो चुकी है, लेकिन स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए निरंतर विकास, प्रभावी शासन और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जनजातीय समुदायों की सार्थक भागीदारी आवश्यक होगी। भारत सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि पिछले एक दशक में हासिल उपलब्धियों को स्थायी रूप से मज़बूत किया जाए और इस दिशा में राज्यों को पूरा सहयोग दिया जाए। ❑

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

UPSC NEW BOOKS PDF

2026 EDITION

अब UPSC STANDARD BOOKS 2026 की PDF सीधे टेलीग्राम पर लें सकते है बस हमारी टेलीग्राम बॉट पर मैसेज करें

Telegram Bot - @pdfhub2026bot

सीधे मैसेज भेजने के लिए MESSAGE NOW पर क्लिक करें

Message Now

दृष्टि The Vision — Drishti IAS

IAS GS फाउंडेशन कोर्स
हिंदी व अंग्रेज़ी माध्यम

ऑफलाइन व लाइव ऑनलाइन (ऐप द्वारा)

- 1200+ घंटों की 500+ कक्षाएँ
- निशुल्क पुस्तकें + प्रिंटेड नोट्स
- संशय निवारण की सुविधा
- कक्षाओं को असीमित बार देखने की सुविधा

स्टेट PCS कोर्सेज़
हिंदी व अंग्रेज़ी माध्यम

ऑफलाइन व लाइव ऑनलाइन (ऐप द्वारा)

- UPPCS फाउंडेशन कोर्स
- MPPSC फाउंडेशन कोर्स
- RAS फाउंडेशन कोर्स
- BPSC फाउंडेशन कोर्स
- HCS फाउंडेशन कोर्स
- UKPSC प्रिलिम्स और मेन्स कोर्स
- PPSC फाउंडेशन कोर्स
- APSC फाउंडेशन कोर्स
- WBPSC फाउंडेशन कोर्स
- JPSC फाउंडेशन कोर्स
- OPSC फाउंडेशन कोर्स
- JKPSC प्रिलिम्स और मेन्स कोर्स

IAS प्रिलिम्स GS कोर्स 2027
हिंदी व अंग्रेज़ी माध्यम | ऑनलाइन (ऐप द्वारा)

- 400+ घंटों की कक्षाएँ
- ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़
- 18 महीनों की कोर्स वैधता
- संशय निवारण की सुविधा

IAS प्रिलिम्स CSAT कोर्स 2027
हिंदी व अंग्रेज़ी माध्यम | ऑनलाइन (ऐप द्वारा)

- 100+ घंटों की कक्षाएँ
- ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़
- 18 महीनों की कोर्स वैधता
- CSAT स्टडी मटीरियल

IAS मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026
हिंदी व अंग्रेज़ी माध्यम | ऑनलाइन (ऐप द्वारा)

पैकेज:
- I (11 टेस्ट्स)
- II (23 टेस्ट्स)
- III (35 टेस्ट्स)
- IV (24 टेस्ट्स)
- V (12 टेस्ट्स)
- VI (08 टेस्ट्स)

UPPCS प्रिलिम्स 2026 कोर्स
हिंदी व अंग्रेज़ी माध्यम | ऑनलाइन (ऐप द्वारा)

- 200+ कक्षाएँ
- ऑनलाइन मॉक टेस्ट्स
- 1 वर्ष की कोर्स वैधता
- संशय निवारण की सुविधा

72nd BPSC प्रिलिम्स कोर्स
हिंदी व अंग्रेज़ी माध्यम | ऑनलाइन (ऐप द्वारा)

- 200+ घंटों की कक्षाएँ
- संशय निवारण की सुविधा
- 1 वर्ष की कोर्स वैधता
- ऑनलाइन मॉक टेस्ट्स

टीचिंग एग्ज़ाम्स कोर्सेज़
हिंदी व अंग्रेज़ी माध्यम | ऑनलाइन (ऐप द्वारा)

- NTA/UGC-NET कोर्स
- Asst.Prof. कोर्सेज़ (BPSC, UPPCS, RPSC, MPPSC)
- BPSC TRE कोर्सेज़
- महापैक्स (Teaching, UGC, BPSC TRE)

ज्यूडिशियरी कोर्सेज़
हिंदी व अंग्रेज़ी माध्यम | ऑनलाइन (ऐप द्वारा)

- ज्यूडिशियरी फाउंडेशन कोर्स
- MP ADPO प्रिलिम्स कोर्स
- बिहार APO कोर्स
- बिहार ज्यूडिशियरी

SSC एग्ज़ाम्स कोर्सेज़
हिंग्लिश माध्यम | ऑनलाइन (ऐप द्वारा)

- SSC महापैक कोर्स
- लक्ष्य बैच – SSC CHSL 2026
- CGL फाउंडेशन कोर्स
- लक्ष्य कॉम्बो बैच (SSC CGL + CHSL 2026)

एडमिशन आरंभ
87501 87501

अभी डाउनलोड करें
Drishti Learning App
विंडोज़ पर भी उपलब्ध
अभी स्कैन करें

करोल बाग	नोएडा	प्रयागराज	जयपुर	लखनऊ	इंदौर	रांची	पटना
21, पूसा रोड, करोल बाग	C-171/2, सेक्टर - 15, नोएडा	ताशकंद मार्ग, सिविल लाइन्स, प्रयागराज	हर्ष टावर 2, टोंक रोड, जयपुर	बर्लिंगटन चौराहा, मार्ग, लखनऊ	12, AB रोड, भंवरकुआँ, इंदौर	क्रिस्टल हाइट्स, लालपुर चौक, रांची	शाही लेन, एस.पी. वर्मा रोड, पटना

YH-2896/2026

upscnotes.in

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

डाक संपर्क सेतु

दुष्यन्त मुद्‌गल

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में भारतीय डाक की भूमिका

ग्रामीण डाक सेवकों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर गहरी पहुंच और मानवीय संपर्क रखने वाले डाक नेटवर्क ने उन समुदायों में विश्वास और भरोसे का निर्माण किया है, जहां कभी पहुंचना कठिन माना जाता था।

भारतीय डाक ने वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में शासन और आवश्यक सेवाओं की पहुंच बढ़ाने में शांत लेकिन परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है, जिससे नक्सल-मुक्त भारत के व्यापक लक्ष्य को सार्थक बल मिला है। अपने ज़मीनी नेटवर्क का विस्तार करके विभाग ने यह सुनिश्चित किया है कि सबसे दूरस्थ और पहले उपेक्षित रहे क्षेत्रों को भी औपचारिक संचार और वित्तीय प्रणालियों के दायरे में लाया जाए।

इस पहुंच विस्तार का एक प्रमुख संकेतक पिछले कुछ वर्षों के दौरान वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में शाखा कार्यालयों (बीओ) का व्यवस्थित रूप से खोला जाना है। वर्ष 2016-17 में स्वीकृत पहल के तहत कुल 1,789 शाखा डाकघर स्थापित किए गए, जिन्होंने अंतिम छोर तक संपर्क (लास्ट-माइल कनेक्टिविटी) की मज़बूत नींव रखी। इस प्रयास को वर्ष 2021-22 में और अधिक गति मिली, जब 3,114 अतिरिक्त शाखा डाकघर खोले गए। यह संवेदनशील क्षेत्रों में सेवाओं की पहुंच को बढ़ाने के लिए केंद्रित प्रयास का परिचायक था। जैसे-जैसे देश नक्सल-मुक्त भारत की दिशा में निरंतर आगे बढ़ता गया, वैसे-वैसे एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों की संख्या में भी तेज़ी से कमी आई। इसी के अनुरूप नए शाखा डाकघरों की आवश्यकता में भी कमी आई और वर्ष 2024-25 में 294 शाखा डाकघर खोले गए। यह न केवल पूर्व उपलब्धियों के सुदृढ़ीकरण को दर्शाता है, बल्कि सतत विकास प्रयासों के सकारात्मक प्रभाव को भी रेखांकित करता है।

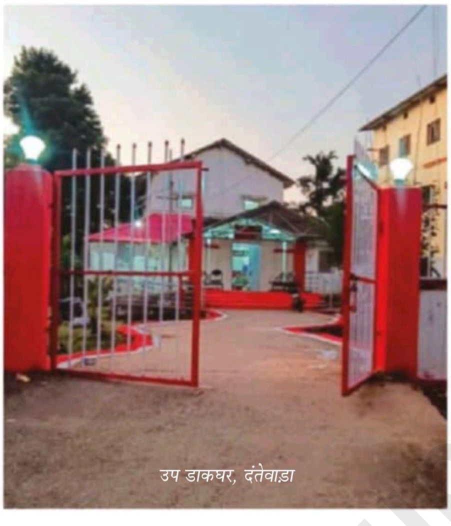

उप डाकघर, दंतेवाड़ा

ये शाखा डाकघर नागरिक-केंद्रित सेवाओं की एक विस्तृत शृंखला के लिए महत्वपूर्ण संपर्क केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, जिनमें डाक वितरण, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से बचत और बैंकिंग सुविधाएं, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), बीमा सेवाएं तथा आधार-सक्षम सेवाएं शामिल हैं। जिन क्षेत्रों में पारंपरिक बैंकिंग और प्रशासनिक ढांचा प्रभावी रूप से पहुंच बनाने में संघर्ष करता रहा, वहां भारतीय डाक सरकार और जनता के बीच एक विश्वसनीय तथा सुलभ माध्यम बनकर उभरा है।

सेवा वितरण से आगे बढ़कर डाकघरों की उपस्थिति ने एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों में समावेशन और राज्य की उपस्थिति की भावना को भी मज़बूत किया है। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देकर, संचार को सुगम बनाकर और कल्याणकारी योजनाओं की डिलीवरी सुनिश्चित करके भारतीय डाक ने उस अलगाव की भावना को कम करने में मदद की है, जो अक्सर उग्रवाद को बढ़ावा देती है। ग्रामीण डाक सेवकों के माध्यम से स्थानीय समुदायों से गहराई से जुड़े इस डाक नेटवर्क ने उन इलाकों में भी विश्वास और विश्वसनीयता स्थापित की है, जहां कभी पहुंचना अत्यंत कठिन था।

इस प्रकार, भारतीय डाक केवल पत्र और पार्सल ही नहीं पहुंचा रहा है, बल्कि स्थिरता, अवसर और एकीकरण भी पहुंचा रहा है। एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों में इसकी बढ़ती उपस्थिति इस बात का सशक्त प्रमाण है कि समावेशी विकास और अंतिम छोर तक संपर्क की व्यवस्था नक्सल-मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ❑

लेखक संचार मंत्रालय, भारत सरकार के भारतीय डाक विभाग में उप महानिदेशक (स्थापना एवं योजना) के पद पर कार्यरत हैं।
ईमेलः ddgmb@indiapost.gov.in

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नौ फरवरी, 2026 को जगदलपुर में आयोजित 'बस्तर पंडुम' महोत्सव का अवलोकन किया। यह महोत्सव आदिवासी कला और संस्कृति की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करता है।

स्रोतः पीआईबी

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

आशा की नई किरण

सुंदरराज पट्टिलिंगम

बस्तर ओलंपिक
शांति, सहभागिता और बदलाव की नई धारा

बस्तर का कायापलट साहस, दृढ़ता और सामूहिक प्रयास की प्रेरणादायक कहानी है। बस्तर ओलंपिक इस बदलाव की कहानी के केंद्र में खड़ा है, जो यह दर्शाता है कि खेल कैसे सीमाओं को पार कर विभाजनों को मिटा सकते हैं। यह आकांक्षाओं को उपलब्धियों में और चुनौतियों को अवसरों में बदल रहा है।

कभी वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से जुड़ा रहा बस्तर का इतिहास अब दृढ़ता, आशा और सकारात्मक परिवर्तन की कहानी के रूप में उभर रहा है। इस बदलाव के केंद्र में एक नवाचारी और जन-केंद्रित पहल है - बस्तर ओलंपिक। यह केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली सामाजिक आंदोलन बन चुका है, जो युवाओं को सशक्त कर रहा है, सामुदायिक संबंधों को मज़बूत बना रहा है और क्षेत्र में शांति को नई मज़बूती दे रहा है।

बस्तर ओलंपिक 2025, 2024 में आयोजित अपने पहले संस्करण की उल्लेखनीय सफलता पर आधारित है। एक खेल प्रयोग के रूप में शुरू हुआ यह आयोजन अब बस्तर के सामाजिक पुनरुत्थान और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बन गया है। यह सरकार द्वारा युवाओं की अपार ऊर्जा, प्रतिभा और आकांक्षाओं को रचनात्मक और राष्ट्र निर्माण गतिविधियों की ओर निर्देशित करने के सचेत प्रयास को दर्शाता है। दशकों तक हिंसा और अलगाव झेलने वाले इस क्षेत्र में, ऐसी पहल केवल मनोरंजन मात्र नहीं, बल्कि एक परिवर्तनकारी अभियान है।

संघर्ष से आत्मविश्वास की ओर: बस्तर ओलंपिक की भूमिका

बस्तर लंबे समय से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित रहा है, जहां युवाओं की कई पीढ़ियों को अवसरों, पहचान और अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के मंचों से वंचित रखा गया। हालांकि, एक बात अटल रही - प्रतिभा, साहस या क्षमता की कभी कमी नहीं रही। कमी थी तो सिर्फ़ पहुंच, प्रोत्साहन और मुख्यधारा में एकीकरण की। बस्तर ओलंपिक इस कमी को सीधे तौर पर पूरा करता है। खेलों में सुनियोजित अवसर प्रदान करके, यह युवाओं को अपनी अभिव्यक्ति करने, प्रतिस्पर्धा में भाग लेने और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का एक सम्मानजनक मार्ग प्रदान करता है। यह भय और संघर्ष की कहानी को आत्मविश्वास, आकांक्षा और नई उम्मीद की कहानी में बदल रहा है। खेल का मैदान अब ऐसा स्थान बन चुका है, जहां पहचान संघर्ष से नहीं, बल्कि क्षमता और प्रतिभा से तय होती है।

खेल अपने स्वभाव से ही अनुशासन, टीम भावना और पारस्परिक सम्मान को बढ़ावा देते हैं। बस्तर में इन मूल्यों का महत्व और भी गहरा हो गया है। ये समुदायों, नागरिकों और संस्थाओं के बीच तथा

लेखक आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्होंने बस्तर क्षेत्र में लगभग 14 वर्षों तक विभिन्न पदों पर कार्य किया है। उन्होंने 2005 में सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। वर्तमान में वो बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। ईमेलः igbastar@rediffmail.com

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

गांव से संभाग स्तर तक खेलों का सुव्यवस्थित विस्तार

बस्तर ओलंपिक महज एक प्रतीकात्मक आयोजन नहीं है; बल्कि इसे बेहद सुनियोजित और पेशेवर तरीके से आयोजित किया जाता है। प्रतियोगिता का आयोजन ब्लॉक, जिला और संभाग स्तर तक किया जाता है, जिससे इसकी व्यापक पहुंच और व्यवस्थित प्रगति सुनिश्चित होती है। 32 विकास खंडों में 60 से अधिक खेल के मैदानों की पहचान कर उन्हें तैयार किया गया है, जहां प्रशिक्षित रेफरी, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक और तकनीकी अधिकारियों की तैनाती की गई है।

लोगों के अंदर विश्वास को फिर से स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

व्यापक भागीदारी : बदलाव का सबसे बड़ा संकेत

बस्तर ओलंपिक की सफलता के सबसे प्रभावशाली संकेतकों में से एक है भागीदारी का व्यापक पैमाना। 2024 में, लगभग 165,000 युवाओं ने इस आयोजन के लिए पंजीकरण कराया था। 2025 में, यह संख्या बढ़कर 3,91,000 से अधिक हो गई है, लगभग तीन गुना वृद्धि। इसमें महिला प्रतिभागियों की भी अच्छी खासी संख्या शामिल है, जो लैंगिक समावेशन और सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऐसी अभूतपूर्व भागीदारी केवल एक आंकड़ा नहीं है; यह बदलती सोच का प्रतिबिंब है। यह दर्शाता है कि बस्तर के युवा हिंसा, संघर्ष और अलगाव के रास्ते को नहीं, बल्कि खेल के मैदान को चुन रहे हैं। साथ ही यह शासन और संस्थागत पहल में बढ़ते विश्वास को भी प्रदर्शित करता है।

नुआ बाटः मुख्यधारा में वापसी की नई राह

बस्तर ओलंपिक अपने गहन समावेशी दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। यह दूर-दराज़ के गांवों, आदिवासी समुदायों और यहां तक कि उन लोगों को एक मंच पर लाता है, जो कभी चरमपंथी विचारधाराओं से जुड़े थे। बस्तर रेंज के सभी सात जिलों के खिलाड़ियों के अलावा, 'नुआ बाट' नाम से एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसका स्थानीय आदिवासी बोली में अर्थ है 'नई राह'। नुआ बाट टीम में हिंसा का त्याग कर मुख्यधारा में शामिल हुए पूर्व माओवादी कार्यकर्ता, माओवादी हिंसा के शिकार लोग और दिव्यांग एथलीट शामिल किए गये। उन्हें एक नई पहचान और एथलीट के रूप में भाग लेने का अवसर दिया गया। इस पुनर्समावेशन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि समाज का कोई भी वर्ग पीछे न छूटे। इस पहल के माध्यम से एक सशक्त संदेश दिया गया है - विकास और सम्मान हर व्यक्ति का समान अधिकार है और बस्तर के भविष्य निर्माण में प्रत्येक नागरिक की महत्वपूर्ण भूमिका है।

इस आयोजन में पारंपरिक और आधुनिक दोनों प्रकार के खेलों को शामिल किया गया है। एथलेटिक्स, फुटबॉल, कबड्डी, खो-खो और वॉलीबॉल जैसे पारंपरिक तथा आधुनिक खेलों को शामिल करने से सांस्कृतिक निरंतरता सुनिश्चित होती है और साथ ही समकालीन खेल मानकों को बढ़ावा मिलता है। राष्ट्रीय स्तर के रेफरी और मानकीकृत बुनियादी ढांचे का उपयोग आयोजन की विश्वसनीयता और गुणवत्ता को और भी बढ़ावा देता है। इस प्रकार का सुनियोजित दृष्टिकोण अनुशासन को बढ़ावा देता है और प्रतिभागियों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर के समान प्रतिस्पर्धी वातावरण से परिचित कराता है। साथ ही यह क्षेत्र में खेल प्रबंधन के लिए संस्थागत क्षमता का निर्माण भी करता है।

राष्ट्रीय पहचान और व्यापक सराहना

बस्तर ओलंपिक का प्रभाव अब क्षेत्रीय सीमाओं से आगे बढ़कर राष्ट्रीय स्तर पर भी महसूस किया जा रहा है। इस पहल को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और सराहना मिली है, जहां इसे खेलों के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाने के एक सफल मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। उच्च स्तर पर मिली यह मान्यता इस बात को और मज़बूत करती है कि बस्तर की यह यात्रा केवल एक क्षेत्र विशेष की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारत के समावेशी विकास और शांति निर्माण की व्यापक राष्ट्रीय सोच का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

प्रसिद्ध खिलाड़ियों और खेल हस्तियों को आमंत्रित कर स्थानीय खिलाड़ियों के साथ संवाद और सहभागिता का अवसर देने से बस्तर ओलंपिक युवाओं के भीतर नई आकांक्षाओं तथा प्रेरणा का संचार करता है। युवा प्रतिभागियों को अपने आदर्श खिलाड़ियों को करीब से देखने और उनसे सीखने का अवसर मिलता है, जिससे उनके सपने अधिक वास्तविक, साकार और प्राप्त करने योग्य प्रतीत होते हैं।

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

बस्तर ओलंपिक 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

अवसर, प्रोत्साहन और मार्ग

बस्तर ओलंपिक की एक प्रमुख ताकत यह है कि यह भागीदारी को अवसरों में परिवर्तित करने में सक्षम है। विभिन्न स्तरों पर विजेताओं को पदक, प्रमाण पत्र और वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं, जो उन्हें पहचान और प्रेरणा दोनों प्रदान करते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे के प्रशिक्षण के लिए मार्ग प्रदान किए जाते हैं, जिसमें राज्य खेल अकादमियों तक पहुंच भी शामिल है।

इस आयोजन के माध्यम से शुरू की गई 'यूथ आइकन्स' की अवधारणा स्थानीय चैंपियनों की प्रेरणादायक कहानियों को खिलाड़ियों के सामने लाती हैं। मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से जब इन प्रेरक कहानियों को साझा किया जाता है तो इसका दूरगामी प्रभाव पड़ता है, जो अधिक से अधिक युवाओं को भागीदारी के लिए प्रेरित करता है और उन्हें अपनी क्षमता पर विश्वास करने का उत्साह देता है। इसके अतिरिक्त खेल किट, उपकरण और बुनियादी ढांचे का प्रावधान क्षेत्र में दीर्घकालिक खेल विकास में योगदान देता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि बस्तर ओलंपिक का प्रभाव केवल आयोजन तक सीमित न रहे, बल्कि आने वाले वर्षों तक खेल संस्कृति और युवा विकास को निरंतर आगे बढ़ाता रहे।

उग्रवाद को खत्म करने की एक पहल

बस्तर ओलंपिक का शायद सबसे गहरा प्रभाव उग्रवाद के तंत्र को कमज़ोर करने में इसकी भूमिका है। युवाओं को रचनात्मक गतिविधियों में शामिल करने से कट्टरपंथ की ओर उनकी संवेदनशीलता कम होती है। यह उपलब्धि मान्यता और अपनेपन पर आधारित एक वैकल्पिक पहचान प्रदान करता है। यह पहल सामुदायिक भागीदारी को भी बढ़ावा देती है। परिवार, स्थानीय नेता और सभी गांव प्रतिभागियों का समर्थन करने के लिए एकजुट होते हैं, जिससे गर्व और स्वामित्व की सामूहिक भावना पैदा होती है। यह सामाजिक एकता शांति बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके अलावा, ओलंपिक बेहतर कनेक्टिविटी, शिक्षा और आजीविका पहल जैसे व्यापक शासन प्रयासों का पूरक है, जो विकास के लिए एक समग्र ढांचा तैयार करता है। यह दर्शाता है कि केवल सुरक्षा उपाय ही पर्याप्त नहीं हैं; स्थायी शांति के लिए सामाजिक और भावनात्मक एकीकरण आवश्यक है।

उम्मीद का प्रतीक और भविष्य की नई दिशा

बस्तर ओलंपिक महज एक आयोजन नहीं है; यह दूरदृष्टि और प्रतिबद्धता के संगम से उत्पन्न संभावनाओं का प्रतीक है। यह इस विचार को मूर्त रूप देता है कि परिवर्तन बाहर से थोपा नहीं जा सकता है, बल्कि समुदायों के भीतर ही पोषित होता है। युवाओं को सशक्त बनाकर, संस्कृति का उत्सव मनाकर और समावेशिता को बढ़ावा देकर, यह एक लचीले और आत्मविश्वासी बस्तर की नींव रखता है।

जैसे-जैसे बस्तर स्थायी शांति और विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, बस्तर ओलंपिक एक महत्वपूर्ण उपलब्धि और भविष्य की दिशा दिखाने वाला, दोनों के रूप में उभरकर सामने आया है। यह दर्शाता है कि संघर्ष से ग्रस्त क्षेत्रों में भी, नवीन, सहभागी और मानव-केंद्रित दृष्टिकोणों के माध्यम से सकारात्मक परिवर्तन संभव है। बस्तर का परिवर्तन साहस, दृढ़ता और सामूहिक प्रयास की कहानी है। बस्तर ओलंपिक इस परिवर्तन की कहानी के केंद्र में खड़ा है, जो दर्शाता है कि खेल किस प्रकार सीमाओं को पार कर विभाजन को दूर कर सकता है। यह आकांक्षाओं को उपलब्धियों में और चुनौतियों को अवसरों में बदल रहा है। बस्तर की पहचान को एक संघर्ष क्षेत्र से प्रतिभा और आशा की जन्मभूमि के रूप में पुनर्परिभाषित करते हुए, बस्तर ओलंपिक न केवल धारणाओं को बदल रहा है, बल्कि वास्तविकता को भी बदल रहा है। यह खेल की एकता की शक्ति और स्थायी शांति तथा प्रगति के उत्प्रेरक के रूप में उसकी क्षमता का प्रमाण है। ❑

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक नवंबर, 2025 को छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का अवलोकन किया।

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

अजीत कुमार श्रीवास्तव

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शिक्षा और सशक्तीकरण का आधार

आकांक्षाओं को पोषित करके, आत्मविश्वास का निर्माण करके और समुदायों को मुख्यधारा से जोड़कर, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय उन आधारों को कमज़ोर करते हैं जिन पर उग्रवाद पनपता है। वे यह प्रदर्शित करते हैं कि शिक्षा केवल एक विकासात्मक साधन नहीं है, बल्कि शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने का एक माध्यम भी है।

वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई), जिसे सामान्यतः नक्सलवाद कहा जाता है, लंबे समय से भारत में शांति और विकास के मार्ग में एक बड़ी बाधा रहा है। यह मुख्यतः आदिवासी और वन क्षेत्रों में केंद्रित रहा, जहां गरीबी, अलगाव, आधारभूत संरचना की कमी तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सीमित पहुंच जैसी परिस्थितियों ने इसे बढ़ावा दिया। दशकों तक उग्रवादी समूहों ने इन कमज़ोरियों का लाभ उठाते हुए आदिवासी युवाओं को निशाना बनाया, जिनके पास अवसरों और जीवन के वैकल्पिक मार्गों का सीमित अनुभव था। ऐसे वातावरण में अलगाव की भावना अक्सर युवाओं को नक्सली समूहों में भर्ती होने की ओर धकेल देती थी। धीरे-धीरे यह स्पष्ट हो गया कि केवल सुरक्षा अभियानों से इस गहरी समस्या का समाधान संभव नहीं है; इसके सामाजिक-आर्थिक कारणों का समाधान भी आवश्यक है। इसी संदर्भ में शिक्षा, परिवर्तन का सबसे प्रभावी और स्थायी माध्यम बनकर उभरी है, जिसमें एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं।

आदिवासी आवासीय विद्यालयों की नींव वर्ष 1999 में रखी गई, जब संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत राज्यों को ऐसे संस्थानों की स्थापना हेतु निधि प्रदान की गई। किंतु वर्ष 2018 में एक महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन हुआ, जब ईएमआरएस को पूर्णतः

ईएमआरएस की नई इमारत

लेखक आदिवासी छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा समिति (नेशनल एजुकेशन सोसायटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स) के पूर्व आयुक्त हैं।
ईमेलः commissioner.nests@tribal.gov.in

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

आवासीय, निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (कक्षा 12 तक) प्रदान करने वाली केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत लाया गया। यह परिवर्तन एक स्पष्ट दृष्टिकोण को दर्शाता है कि आदिवासी क्षेत्रों में स्थायी शांति तभी संभव है, जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास सीधे लोगों तक पहुंचाया जाए। ईएमआरएस की परिकल्पना आदिवासी छात्रों को उनके अपने सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश में उच्च गुणवत्ता वाली आवासीय शिक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया, जिससे उन्हें सुरक्षा और अवसर दोनों मिल सकें। समय के साथ ये विद्यालय सामाजिक परिवर्तन के शक्तिशाली साधन बन गए हैं।

नक्सलवाद के खिलाफ शिक्षा की भूमिका

शिक्षा विशेष रूप से संघर्ष-प्रभावित क्षेत्रों में एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में कार्य करती है। ऐतिहासिक रूप से नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में निरक्षरता और जागरूकता की कमी ने समुदायों को वैचारिक रूप से प्रभावित या गुमराह किए जाने के प्रति संवेदनशील बनाया है। विद्यालयों तक पहुंच के अभाव में बच्चे अक्सर मुख्यधारा के समाज से कटे हुए बड़े होते हैं, और उन्हें अपने अधिकारों या अवसरों की सीमित समझ होती है।

शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित कर राज्य व्यक्तियों को ज्ञान, आलोचनात्मक सोच की क्षमता और जागरूकता से सशक्त बनाता है। शिक्षा रोज़गार के अवसरों के द्वार खोलती है, आर्थिक निर्भरता को कम करती है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास को मज़बूत करती है। यह आत्मविश्वास और अपनत्व की भावना विकसित करती है, जो अलगाव को रोकने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। जब युवाओं को आकांक्षाएं और अवसर मिलते हैं, तो उग्रवादी विचारधाराओं का आकर्षण स्वतः कम हो जाता है।

ईएमआरएस इन चुनौतियों का सीधे समाधान करते हैं, क्योंकि वे आदिवासी युवाओं पर केंद्रित हैं और उन्हें आवासीय व्यवस्था में संरचित तथा उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करते हैं। इससे न केवल क्षेत्रीय असमानताओं को कम किया जाता है, बल्कि वंचित समुदायों को राष्ट्रीय मुख्यधारा से भी जोड़ा जाता है।

आदिवासी अंचलों में विस्तार

नक्सलवाद के प्रभाव का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए सरकार ने रणनीतिक रूप से सबसे अधिक प्रभावित जिलों में ईएमआरएस का विस्तार किया। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में 259 विद्यालयों को स्वीकृति दी गई और जिनमें से 178 विद्यालय कार्यशील हो चुके हैं, जिससे उन क्षेत्रों को सीधे लक्षित किया गया जहां पारंपरिक रूप से उग्रवादी भर्ती अधिक रही है। शेष विद्यालय अगले वर्ष कार्यशील किए जाएंगे। आज, 50,000 से अधिक आदिवासी छात्र इन विद्यालयों में नामांकित हैं और सुरक्षित आवासीय परिसरों में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

विद्यालयी शिक्षा का यह आवासीय मॉडल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुरक्षित और सक्रिय वातावरण प्रदान करके ईएमआरएस छात्रों को शारीरिक और मानसिक रूप से उग्रवादी समूहों के प्रभाव से दूर रखते हैं। जो बच्चे अपना समय कक्षाओं में, खेलों में और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में बिताते हैं, वे भर्ती के प्रति बहुत कम संवेदनशील होते हैं। इस प्रकार ईएमआरएस संभावित भर्ती की प्रक्रिया को अवसरों और सकारात्मक विकल्पों के माध्यम से कमज़ोर कर देते हैं। इसके अतिरिक्त, इन विद्यालयों की उपस्थिति दूरस्थ क्षेत्रों में शासन की प्रभावी उपस्थिति को मज़बूत करती है। शिक्षक, प्रशासक और सहायक कर्मचारी राज्य के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करते हैं, विश्वास को बढ़ावा देते हैं और यह भावना सुदृढ़ करते हैं कि विकास सबसे अलग-थलग समुदायों तक भी पहुंच रहा है।

आधुनिक आधारभूत संरचना और डिजिटल सशक्तीकरण

ईएमआरएस की सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक, आधुनिक आधारभूत संरचना पर उनका विशेष बल है। ये विद्यालय केवल सामान्य शैक्षणिक भवन नहीं हैं, बल्कि इन्हें शहरी विद्यालयों के समकक्ष उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों के रूप में विकसित किया गया

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

है। स्मार्ट कक्षाएं, कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशालाएं और डिजिटल उपकरणों से सुसज्जित ये विद्यालय (ईएमआरएस) यह सुनिश्चित करते हैं कि आदिवासी छात्रों को आधुनिक शिक्षा प्राप्त हो।

सभी परिसरों में उच्च गति इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों को वैश्विक ज्ञान नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। स्मार्ट बोर्ड और डिजिटल शिक्षण उपकरण शिक्षा को विशेष रूप से प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थियों के लिए अधिक सहभागितापूर्ण और आकर्षक बनाते हैं। यह तकनीकी अनुभव ग्रामीण-शहरी अंतर को कम करता है और छात्रों को तेज़ी से बदलती दुनिया के लिए तैयार करता है।

नवाचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, प्रमुख संस्थानों के सहयोग से स्पेस और विज्ञान प्रयोगशालाओं जैसी उन्नत सुविधाएं शुरू की जा रही हैं। ऐसी पहल छात्रों को अत्याधुनिक क्षेत्रों से परिचित कराती हैं, जिससे जिज्ञासा और महत्वाकांक्षा को प्रोत्साहन मिलता है। एक बच्चा, जिसके पास पहले सीमित संभावनाएं थीं, अब विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान में करियर का सपना देख सकता है। इन प्रगतियों को बनाए रखने के लिए रखरखाव और उन्नयन हेतु समर्पित निधियां सुनिश्चित करती हैं कि अवसंरचना कार्यशील और प्रासंगिक बनी रहे। यह निरंतर निवेश दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का संकेत देता है और स्थानीय समुदायों में विश्वास पैदा करता है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सीबीएसई पाठ्यक्रम

केवल आधारभूत संरचना परिवर्तन नहीं ला सकती, उसके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण भी आवश्यक है। ईएमआरएस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन (सीबीएसई) से संबद्ध हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि छात्रों को देश के श्रेष्ठ विद्यालयों के समान मानकीकृत पाठ्यक्रम प्राप्त हो। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि आदिवासी छात्र शैक्षणिक रूप से पीछे न रह जाएं।

शिक्षकों की भर्ती अखिल भारतीय परीक्षा के माध्यम से की जा रही है, ताकि उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षक छात्रों को शिक्षण प्रदान कर सकें। शिक्षक प्रशिक्षण भी एक महत्वपूर्ण घटक है। ईएमआरएस में शिक्षक केवल प्रशिक्षक नहीं, बल्कि मार्गदर्शक और परामर्शदाता भी होते हैं। वे छात्रों को शैक्षणिक चुनौतियों के साथ-साथ सामाजिक और भावनात्मक चुनौतियों को समझने तथा निपटने में भी सहायता करते हैं। आलोचनात्मक सोच और विवेकपूर्ण निर्णय क्षमता को प्रोत्साहित कर शिक्षक वैचारिक भटकाव या दुष्प्रभाव को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

एक शिक्षित और जागरूक छात्र के उग्रवादी विचारधाराओं से प्रभावित होने की संभावना बहुत कम होती है। इसके विपरीत, वह प्रश्न पूछने, विश्लेषण करने और सकारात्मक मार्ग चुनने में सक्षम होता है।

उत्कृष्टता केंद्र और प्रतियोगी परीक्षाएं

ईएमआरएस की एक प्रमुख विशेषता छात्रों में ऊंचे लक्ष्य और आकांक्षाएं विकसित करना है। आईआईटी और नीट (एनईईटी) जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां छात्रों को विशेष कोचिंग प्रदान की जाती है। ये पहल प्रतिष्ठित संस्थानों तक पहुंचने का स्पष्ट मार्ग तैयार करती हैं।

आकांक्षा उग्रवाद के विरुद्ध एक शक्तिशाली प्रतिरोधक है। जब छात्र स्वयं को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासक या वैज्ञानिक के रूप में देखने लगते हैं, तो वे हिंसा की ओर आकर्षित नहीं होते। प्रत्येक सफलता की कहानी पूरे समुदाय के लिए प्रेरणा बन जाती है और यह सिद्ध करती है कि शिक्षा जीवन बदल सकती है।

बढ़ती लोकप्रियता और सामाजिक विश्वास

ईएमआरएस में प्रवेश के लिए बढ़ती आवेदन संख्या इन विद्यालयों की विश्वसनीयता और लोकप्रियता को दर्शाती है। आदिवासी परिवार जो कभी संदेह में रहते थे या परिस्थितियों से बाधित थे, वे अब सक्रिय रूप से अपने बच्चों के लिए प्रवेश की मांग कर रहे हैं। आवासीय व्यवस्था, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समग्र विकास ने इन विद्यालयों को अत्यंत आकर्षक बना दिया है।

यह परिवर्तन मानसिकता में व्यापक बदलाव को दर्शाता है। शिक्षा को अब दूर की संभावना नहीं, बल्कि प्रगति के एक वास्तविक मार्ग के रूप में देखा जा रहा है। ऐसा परिवर्तन नक्सलवाद के वैचारिक आधार को कमज़ोर करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

ईएमआरएस का स्मार्ट क्लासरूम

खेल, संस्कृति और सर्वांगीण विकास

ईएमआरएस सर्वांगीण विकास पर बल देते हैं, जिसमें शिक्षा को खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ जोड़ा जाता है। राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक उत्सवों जैसे कार्यक्रम छात्रों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने और देशभर के अन्य छात्रों के साथ संवाद करने के अवसर प्रदान करते हैं। खेलों में भागीदारी छात्रों में अनुशासन, टीम भावना और धैर्य का निर्माण करती है, जबकि सांस्कृतिक आदान-प्रदान राष्ट्रीय एकता और गौरव को बढ़ावा देता है। इससे छात्रों को विविध परंपराओं और दृष्टिकोणों को समझने का अवसर मिलता है, जिससे एक बड़े राष्ट्र के हिस्से के रूप में उनकी पहचान मज़बूत होती है।

ईएमआरएस के पूर्व छात्र बन रहे हैं परिवर्तन के प्रेरक

ईएमआरएस के पूर्व छात्रों का बढ़ता नेटवर्क इस योजना की सफलता का प्रमाण है। आज इसके छात्र स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग, शिक्षा और लोक सेवा सहित विभिन्न पेशेवर भूमिकाओं में समाज में योगदान दे रहे हैं। उनकी उपलब्धियां नए छात्रों के लिए प्रेरणा बनती हैं और शिक्षा के महत्व को और अधिक सुदृढ़ करती हैं। कई पूर्व छात्र अपने समुदायों में लौटकर मार्गदर्शक और प्रेरणास्रोत की भूमिका निभा रहे हैं। इससे आकांक्षा और उपलब्धि का ऐसा चक्र विकसित हो रहा है, जो धीरे-धीरे उग्रवादी विचारधाराओं के प्रभाव को प्रतिस्थापित कर रहा है।

आदिवासी युवाओं को अवसर

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय नक्सलवाद के मूल कारणों को संबोधित करके उससे मुकाबला करने के एक शक्तिशाली साधन के रूप में उभरे हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक आधारभूत संरचना, कौशल विकास और समग्र विकास के माध्यम से ये विद्यालय आदिवासी युवाओं को ऐसे अवसर प्रदान करते हैं, जो कभी उनकी कल्पना से परे थे।

आकांक्षाओं को प्रोत्साहित कर, आत्मविश्वास का निर्माण कर और समुदायों को मुख्यधारा से जोड़कर ईएमआरएस उन आधारों को कमज़ोर करते हैं, जिन पर उग्रवाद पनपता है। ये विद्यालय यह सिद्ध करते हैं कि शिक्षा केवल एक विकासात्मक साधन नहीं है, बल्कि शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने का भी एक प्रभावी माध्यम है।

दीर्घकाल में ईएमआरएस की सफलता एक मूल सत्य को रेखांकित करती है कि नक्सलवाद जैसी जटिल चुनौतियों का स्थायी समाधान केवल बल प्रयोग में नहीं, बल्कि लोगों को ज्ञान, अवसर और आशा के माध्यम से सशक्त बनाने में निहित है। ❑

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड	110003	011-24367260
पुणे	ग्राउंड फ्लोर, कैरियर बिल्डिंग, महादाजी शिंदे, बीएसएनएल, टीई कंपाउंड, क्लब के पास, कैंप	411001	
कोलकाता	8,एस्प्लेनेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बेसेंट नगर	600090	044-24917673
तिरुवनंतपुरम	प्रेस रोड, गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवाड़ीगुड़ा, सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बेंगलुरू	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2675823
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज	226024	0522-2325455
गुजरात	4-सी, नेप्च्यून टावर, चौथी मंजिल, आश्रम रोड, अहमदाबाद	380009	079-26588669
गुवाहाटी	दूरदर्शन कैम्पस, आर जी बरूआ रोड, कामरूप मेट्रोपोलिटन, असम	781024	9101982938

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

संयोजन

रीतेश कावडिया

सुरक्षा से संपर्क तकः नक्सल-मुक्त भारत में दूरसंचार क्रांति की भूमिका

दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार से स्थानीय उद्यमिता को भी बढ़ावा मिला है और ग्राम स्तर के उद्यमियों को डिजिटल तथा वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाया है। बेहतर कनेक्टिविटी ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों और छोटे उत्पादकों को डिजिटल बाज़ारों तक पहुंच प्रदान की है, जिससे आजीविका के अवसर बढ़े हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं व्यापक तौर पर बाज़ारों से जुड़ पाई हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दो साल पहले अगस्त 2024 में नक्सल-मुक्त भारत के अपने वादे को पूरा करते हुए, 30 मार्च, 2026 को लोकसभा में अपने संबोधन में घोषणा की, 'भारत अब नक्सल-मुक्त है।' पांच दशकों से अधिक समय तक देश को त्रस्त रखने वाले इस आंदोलन को शासन व्यवस्था की खामियों, बुनियादी सेवाओं की कमी, विकास संबंधी असमानताओं और हाशिए पर धकेल दिए जाने की शिकायतों से बल मिला। इन्हीं स्थितियों में इसके समाधान की कुंजी भी छिपी थी। विकास पर निरंतर ध्यान केंद्रित करके उपेक्षा की पुरानी शिकायतों का समाधान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कभी व्यापक रूप से फैला 'रेड कॉरिडोर' धीरे-धीरे अलग-थलग 'रेड पॉकेट' में सिमटने लगा। यह कार्रवाई सुरक्षा संबंधी गतिविधियों से परे एक समग्र विजन यानी हिंसा के प्रति शून्य सहिष्णुता, त्वरित विकास और बुनियादी ढांचे का विस्तार तथा मुख्यधारा में लौटने के इच्छुक लोगों के पुनर्वास तक विस्तारित हुई।

संपर्क, सुशासन और अवसरों के नए संकेत

दशकों तक, भारत के वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित विशाल क्षेत्र पहुंच से बाहर, भौतिक और डिजिटल दोनों रूपों में देश की मुख्यधारा से कटे हुए रहे। इन क्षेत्रों में शासन व्यवस्था कमज़ोर हो गई और उग्रवाद को पनपने का अवसर मिला। इसलिए इस खाई को पाटना केवल बुनियादी ढांचे से संबंधित चुनौती नहीं थी, बल्कि शासन की उपस्थिति और जनविश्वास को बहाल करने का प्रश्न भी था। आज इन क्षेत्रों की पहचान रहे सन्नाटे और अलगाव की स्थिति को तेज़ी से संपर्क, सुशासन और अवसरों के नए संकेत प्रतिस्थापित कर रहे हैं।

इन क्षेत्रों में दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर केवल कनेक्टिविटी का मामला नहीं है, बल्कि यह अपने आप में देश की उपस्थिति का प्रतीक है। टावर और फाइबर नेटवर्क केवल सिग्नल संचारित करने से कहीं अधिक कार्य करते हैं। वे शासन, अवसर और विश्वास का संचार करते हैं। आज के डिजिटल इंडिया में, दूरसंचार नेटवर्क कल्याणकारी सेवाओं की रीढ़ हैं, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री जन धन योजना, यूपीआई और आयुष्मान भारत जैसे कार्यक्रमों को सक्षम बनाते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से अनेक अवसरों का विस्तार होता है और समावेशन की प्रक्रिया को मज़बूती मिलती है।

इन क्षेत्रों के लोगों के लिए दूरसंचार टावर महज बुनियादी ढांचा नहीं है; यह एक व्यापक दुनिया का द्वार है, जो छात्रों को कक्षाओं

छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 2022 में लगाया गया मोबाइल टावर

लेखक संचार मंत्रालय, भारत सरकार के दूरसंचार विभाग में उप महानिदेशक (डीबीएन) के पद पर कार्यरत हैं।
ईमेलः ddgmobile.usof-dot@gov.in

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

से जोड़ता है, किसानों को बाज़ार तक पहुंच और अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराता है। बुजुर्गों को समय पर पेंशन देता है, लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खाते में धनराशि पहुंचाता है और परिवारों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। कनेक्टिविटी प्रशासनिक पहुंच को भी मज़बूत करती है और सुरक्षा बलों के बीच समन्वय बढ़ाती है, जिससे क़ानून व्यवस्था में सुधार होता है और विकास के सकारात्मक तथा आत्म-सुदृढ़ चक्र को मज़बूत करती है।

डिजिटल भारत निधि की स्थापना

समावेशी विकास को प्राप्त करने में कनेक्टिविटी की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, डिजिटल विभाजन को पाटने के उद्देश्य से दूरसंचार विभाग के अंतर्गत डिजिटल भारत निधि (डीबीएन), पूर्व में यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य दूरस्थ और कम विकसित क्षेत्रों में, जहां व्यावसायिक व्यवहार्यता सीमित है, मोबाइल कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड और आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर सहित दूरसंचार सेवाओं तक किफायती तथा समान पहुंच सुनिश्चित करना है। डीबीएन की स्थापना का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास केवल बाज़ार की ताकतों द्वारा निर्देशित न होकर, समावेशन की अनिवार्यता द्वारा निर्देशित हो।

इसी उद्देश्य से, डीबीएन ने गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए लक्षित क्रियाकलाप शुरू किए। इसका लक्ष्य इन क्षेत्रों को विकसित भारत की व्यापक विकास यात्रा से जोड़ना था। व्यावसायिक रूप से अव्यवहार्य होने के कारण ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित इन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की कमी को दूर करने के लिए निरंतर सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता थी।

2जी के बुनियादी ढांचे से 4जी का सफर

2014 में मंत्रिमंडल ने गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित 10 राज्यों के वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 106 जिलों में 2जी मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने की योजना के पहले चरण को मंजूरी दी। इस पहल के तहत, 2,340 मोबाइल टावर स्थापित किए गए। इसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की आधारभूत संरचना तैयार हुई। इनमें से अधिकांश टावरों को 4जी में अपग्रेड कर दिया गया है। इससे सेवा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और सुरक्षा बलों तथा स्थानीय समुदाय, दोनों के लिए इसकी पहुंच का विस्तार हुआ है।

पहले चरण की सफलता को आगे बढ़ाते हुए, गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप, व्यवहार्यता संबंधी कमी को दूर करने हेतु वित्तपोषण मॉडल का उपयोग करके 4जी-सक्षम इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से मोबाइल कनेक्टिविटी विस्तार योजना के दूसरे चरण को 2018 में मंजूरी दी गई थी। इस चरण के तहत, 1,216 अतिरिक्त मोबाइल टावर चालू किए गए, जिससे वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 1,275 स्थानों को 4जी मोबाइल कवरेज प्रदान किया गया।

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र परियोजना के अंतर्गत चालू किए गए टावरों का राज्यवार विवरण इस प्रकार हैः

राज्य	चालू किए गए 4जी टावरों की संख्या	
	एलडब्ल्यूई-I	एलडब्ल्यूई-II
आंध्र प्रदेश	62	195
बिहार	250	1
छत्तीसगढ	491	476
झारखंड	808	73
मध्य प्रदेश	19	24
महाराष्ट्र	62	78
ओडिशा	256	358
तेलंगाना	171	11
उत्तर प्रदेश	78	0
पश्चिम बंगाल	93	0
कुल	**2,290**	**1,216**

समर्पित वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र (एलडब्ल्यूई) योजनाओं के अतिरिक्त, अन्य डीबीएन पहल के तहत एलडब्ल्यूई से प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त 5,863 मोबाइल टावर चालू किए गए हैं, जिनमें 4जी सैचुरेशन प्रोजेक्ट और आकांक्षी जिला योजना शामिल हैं, जिससे इन क्षेत्रों में समग्र कनेक्टिविटी में काफी विस्तार हुआ है।

अन्य डीबीएन परियोजना के अंतर्गत चालू किए गए टावरों का राज्यवार विवरण इस प्रकार हैः

राज्य	अन्य डीबीएन परियोजनाओं के तहत चालू किए गए टावरों की संख्या
आंध्र प्रदेश	1,456
बिहार	116
छत्तीसगढ	491
झारखंड	807
केरल	85
मध्य प्रदेश	135
महाराष्ट्र	517
ओडिशा	2,092
तेलंगाना	162
पश्चिम बंगाल	2
कुल	**5,863**

डीबीएन द्वारा वित्त पोषित 4जी सैचुरेशन प्रोजेक्ट ने अंतिम दूरी तक कनेक्टिविटी को एक महत्वपूर्ण गति प्रदान की है, जिसका उद्देश्य

upscnotes.in

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

स्वदेशी 4जी स्टैक के माध्यम से देश के कुछ सबसे दूरस्थ और हाशिए पर पड़े क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं का विस्तार करना है। यह परियोजना व्यापक मोबाइल कवरेज के लक्ष्य को गति प्रदान करने के साथ-साथ एक रणनीतिक कदम आत्मनिर्भर भारत का प्रतिनिधित्व करती है।

पर्यावरण और इंफ्रास्ट्रक्चर में संतुलन

मोबाइल सेवाओं के विस्तार के साथ-साथ, डीबीएन कनेक्टिविटी को टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने पर भी समान रूप से ज़ोर देता है। कार्यान्वयन एजेंसियों को दूरसंचार टावरों के लिए दोहरे विद्युत स्रोतों को सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर ऊर्जा एक प्रमुख विकल्प है। इसके अलावा, चूंकि डीबीएन के अधिकांश टावर दूरस्थ और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील वन क्षेत्रों में स्थित हैं, इसलिए वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) और वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) सहित वैधानिक मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करने पर पूरा ध्यान रखा जाता है। पर्यावरण सुरक्षा संबंधी उपायों के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए), सामाजिक लेखापरीक्षा और क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) के तहत क्षतिपूर्ति वनरोपण उपाय भी किए जाते हैं।

हालांकि, डीबीएन के दृष्टिकोण को वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में ज़मीनी स्तर पर कनेक्टिविटी में बदलने के लिए कई जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें सुरक्षा जोखिम, दुर्गम भूभाग और सड़क एवं बिजली जैसी सहायक बुनियादी ढांचे की कमी शामिल थी। इन कारणों से अक्सर प्रगति की गति बाधित हुई। इन क्षेत्रों में देश की उपस्थिति को बढ़ाने के प्रयासों को बाधित करने के उद्देश्य से उग्रवादी तत्वों द्वारा टावरों को जलाने की घटनाएं भी सामने आईं।

ज़मीनी चुनौतियां और मंत्रालयों का रीयल-टाइम समन्वय

इन चुनौतियों का समाधान कई हितधारकों के समन्वित प्रयासों से किया गया, जिनमें भूमि अधिग्रहण और सुरक्षा व्यवस्था में राज्य सरकारों का सहयोग, गृह मंत्रालय द्वारा समय पर हस्तक्षेप, कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में नियमित बहु-हितधारक समीक्षाएं और ज़मीनी स्तर पर कार्यान्वयन को सुगम बनाने में दूरसंचार विभाग (डीओटी) की क्षेत्रीय इकाइयों की सक्रिय भूमिका शामिल थी। नियमित बैठकें, जो अक्सर महीने में कई बार आयोजित की जाती थीं, विभिन्न मंत्रालयों और कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाती थीं, जिससे कार्यान्वयन संबंधी बाधाओं का रीयल-टाइम समाधान संभव हो पाता था।

डैशबोर्ड से पारदर्शिता और जवाबदेही

दूरस्थ क्षेत्रों में डीबीएन द्वारा दूरसंचार के विस्तार की एक प्रमुख विशेषता डेटा-आधारित निगरानी प्रणालियों को अपनाना रहा है। पीएमआईएस (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम) और एमओसी (संचार मंत्री) जैसे समर्पित डैशबोर्ड तथा समीक्षा प्रणालियां, कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और चुनौतियों के संदर्भ में प्रगति की निरंतर निगरानी में सक्षम बनाने के साथ-साथ वरिष्ठ प्रशासनिक स्तरों पर नियमित पर्यवेक्षण भी सुनिश्चित करती हैं। उच्च स्तरीय निगरानी के साथ, हितधारकों को स्पष्ट लक्ष्य और समय-सीमा निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे जवाबदेही और समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित होता है। इस दृष्टिकोण ने परिणामोन्मुख शासन व्यवस्था की संस्कृति को बढ़ावा दिया है, ताकि त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई को सुगम बनाया जा सके और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी परियोजनाओं को गति बनाए रखने में मदद मिल सके।

सुकमा-मलकानगिरी में उद्यमिता का नया सवेरा

इस मज़बूत ढांचे की बदौलत, डीबीएन के तहत स्थापित मोबाइल टावर आज 30 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान करते हैं, जिनमें एलडब्ल्यूई से प्रभावित क्षेत्रों में 10 लाख से अधिक उपयोगकर्ता शामिल हैं। मोबाइल कनेक्टिविटी से आए बदलाव का एक स्पष्ट उदाहरण छत्तीसगढ़ के सुकमा और ओडिशा के मलकानगिरी जैसे जिलों में देखा जा सकता है। पहले इन क्षेत्रों में मोबाइल कवरेज लगभग न के बराबर था। इससे स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों, दोनों के लिए संचार मुश्किल था। डीबीएन मोबाइल परियोजनाओं के तहत मोबाइल टावरों की स्थापना से, पहले से मोबाइल नेटवर्क से वंचित कई गांवों को अब कवरेज मिल गया है और संवाद तथा समन्वय में काफी सुधार हुआ है। इससे न केवल सुरक्षा बलों की संचालन क्षमता बढ़ी है, बल्कि समुदायों को आवश्यक सेवाओं और अवसरों से जोड़कर सामाजिक-आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिला है। यह दर्शाता है कि कैसे कनेक्टिविटी पहले दुर्गम क्षेत्रों में शासन और सुरक्षा दोनों के लिए एक शक्तिवर्धक कारक के रूप में कार्य करती है।

दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार से स्थानीय उद्यमिता को भी बढ़ावा मिला है और ग्राम स्तर के उद्यमियों को डिजिटल तथा वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाया है। बेहतर कनेक्टिविटी ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों और छोटे उत्पादकों को डिजिटल बाज़ारों तक पहुंच प्रदान की है, जिससे आजीविका के अवसर बढ़े हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं व्यापक तौर पर बाज़ारों से जुड़ पाई हैं।

बंदूक की नोक बनाम नेटवर्क की शक्ति

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार हस्तक्षेपों की सफलता उन इलाकों में जटिल अवसंरचना उपलब्ध कराने में राज्य की क्षमता की व्यापक भूमिका को दर्शाती है, जहां केवल बाज़ार आधारित व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं होतीं। इन क्षेत्रों का विकास एक व्यापक बदलाव को दर्शाता है, जहां दमन से जुड़ाव, बहिष्कार से समावेशन और विद्रोह से एकीकरण की ओर बदलाव हो रहा है। यह माओवादी सिद्धांत 'सत्ता बंदूक की नोक से निकलती है' का खंडन करते हुए एक ऐसी वास्तविकता बताती है जहां 'विकास में कनेक्टिविटी की भूमिका उजागर होती है।' ❑

upscnotes.in

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

कंचन लक्ष्मण

सुरक्षा, समन्वय और संकल्प ऐसे बना नक्सल-मुक्त भारत

'नक्सल-मुक्त भारत' केवल सुरक्षा के क्षेत्र में हासिल की गई उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह एक संवैधानिक पुनर्स्थापना है-भारतीय राज्य की अपने भूभाग के प्रत्येक हिस्से में पुनः वापसी और वहां के नागरिकों को उनके अधिकार एवं सम्मान की पुनर्प्राप्ति।

31 मार्च, 2026 का ऐलान कोई संयोग नहीं था, बल्कि यह एक सतत और संस्थागत रूप से संचालित परिवर्तन का परिणाम था, जिसमें ख़ुफ़िया एजेंसियों ने नेतृत्व किया, सुरक्षा बलों ने एकजुट होकर काम किया और संस्थागत समन्वय के साथ-साथ राजनीतिक इच्छाशक्ति भी दृढ़ रही। इन सभी ने मिलकर वह हासिल किया जो दशकों की प्रतिक्रियात्मक आतंकवाद-विरोधी नीतियों से संभव नहीं हो सका था।

छह अप्रैल, 2010 को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में माओवादियों के एक ही हमले में केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल के 76 जवान शहीद हो गए। यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में सुरक्षा बलों पर हुआ सबसे घातक हमला था। अपने चरम पर, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) ने 10 राज्यों के 223 से अधिक जिलों पर अपना प्रभाव जमा रखा था। झारखंड से छत्तीसगढ़ तक के वनों में समानांतर प्रशासन चला रखा था और भारत के खनिज संपन्न आदिवासी क्षेत्रों के बड़े हिस्से को लगभग प्रशासन विहीन बना दिया था, जहां प्रभावी शासन चलाना लगभग असंभव हो गया था। 31 मार्च, 2026 को भारतीय राज्य द्वारा नक्सल-मुक्त भारत घोषित करना केवल एक सुरक्षा उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह संविधान की बहाली है।

दंतेवाड़ा हमला और मार्च 2026 के बीच जो बदलाव आया, वह केवल बेहतर उपकरण या अधिक सैन्य कर्मियों की तैनाती ही नहीं थी, असल में वह परिवर्तन रणनीतिक ढांचे में हुआ- राजनीतिक इच्छाशक्ति को संचालन संबंधी सिद्धांतों में बदलने का, ख़ुफ़िया सूचनाओं को सटीक कार्रवाई में परिवर्तित करने का और केंद्र-राज्य के बीच मौजूद मतभेदों को संस्थागत समन्वय में बदलने का था। भारत ने दुनिया के सबसे लंबे माओवादी उग्रवाद को जिस तरह समाप्त किया, उसकी कहानी मूल रूप से एक ऐसे राज्य की कहानी है जिसने निर्णायक रूप से निर्णय लेने, समन्वय स्थापित करने और प्रभावी कार्रवाई करने का रास्ता चुना।

गृह मंत्रालय की केंद्रीय भूमिका

केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने न केवल उग्रवाद विरोधी अभियान की निगरानी की, बल्कि उसका नेतृत्व भी किया। 2015 की राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना ने उग्रवाद विरोधी अभियान के केंद्र

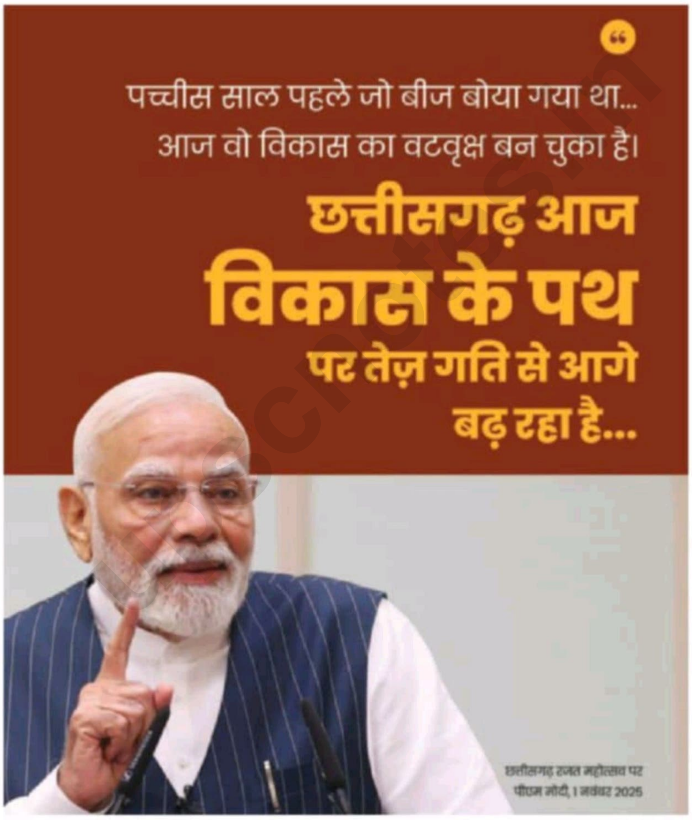

लेखक दिल्ली स्थित राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषक हैं। ईमेलः kanchanlakshman@gmail.com

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक नवंबर, 2025 को छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में एक प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए।

में गृह मंत्रालय को रखा, जिसमें सुरक्षा अभियान, विकास वितरण और अंतर-राज्यीय समन्वय को एकीकृत किया गया। जिला स्तरीय निगरानी प्रणाली स्थापित की गई, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए निधि को सुव्यवस्थित किया गया और सबसे संवेदनशील संघर्ष क्षेत्रों में धीरे-धीरे एक एकीकृत कमान संरचना स्थापित की गई। इस संस्थागत परिवर्तन का केंद्र बिंदु 'समाधान' (एसएएमएडीएचएएन) सिद्धांत था - गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित एक ढांचा जिसने उस अभियान को परिचालन स्तर पर एकरूपता प्रदान की, जो लंबे समय से बिखरे हुए ढांचे में संचालित हो रहा था।

निर्णायक राजनीतिक संकेत 2024 में मिला, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सार्वजनिक रूप से एक निश्चित समय सीमा की घोषणा करते हुए कहा, '31 मार्च, 2026 तक देश से सशस्त्र नक्सलवाद का सफाया कर दिया जाएगा।' यह महज़ राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि एक निर्देश था। यह एक समयबद्ध प्रतिबद्धता थी जिसने प्राथमिकताओं को निर्धारित किया, जवाबदेही को बढ़ाया और सुरक्षा संस्थानों में अभियानों को गति दी। निरंतर समीक्षाओं, ग्राउंड दौरों और प्रत्यक्ष निगरानी के माध्यम से, गृह मंत्री ने गृह मंत्रालय की भूमिका को समन्वय से नेतृत्व में बदल दिया। साथ ही नक्सल के खिलाफ इरादे को क्रियान्वयन में परिवर्तित कर दिया।

जब इंटेलिजेंस बना अभियान का सबसे बड़ा हथियार

यदि नक्सल-विरोधी अभियान की दिशा को निर्णायक रूप से बदलने वाला कोई एक कारक है, तो वह ख़ुफ़िया संरचना का रूपांतरण है। माओवादी विद्रोह के इतिहास के अधिकांश समय में, सुरक्षा बलों के अभियान प्रतिक्रियात्मक थे, यानी माओवादी हमलों के ऐसे इलाकों में कार्रवाई की जाती थी जहां पर उग्रवादी जमा होते थे। हालांकि ख़ुफ़िया जानकारी पर आधारित अभियानों की ओर हुए बदलाव ने इस स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया और पीछा करने की रणनीति को पहले से रोकथाम करने की रणनीति में बदल दिया, जहां सूचना स्वयं नियंत्रण का साधन बन गई।

इस बदलाव की नींव उन क्षेत्रों में ह्यूमिन्ट (मानव स्रोत से प्राप्त ख़ुफ़िया जानकारी) नेटवर्क के व्यवस्थित विस्तार पर आधारित थी, जो कभी माओवादियों के प्रभाव में थे। आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों का पुनर्वास किया गया और उन्हें सुरक्षा बलों के लिए उपयोगी बनाया गया। इनसे पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (पीएलजीए) की संरचनाओं, गतिविधियों और नेतृत्व के बारे में विस्तृत जानकारी

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

मिली। समय के साथ, ग्राम-स्तर के मुख़बिर नेटवर्क ने सुरक्षा बलों को वह स्थानीय जानकारी प्रदान की जो पहले केवल माओवादियों के पास थी। इस ह्यूमिन्ट आधार के साथ-साथ, ड्रोन, मोबाइल सिग्नल अवरोधन और उपग्रह इमेजरी जैसे तकनीकी उपकरणों का भी उपयोग किया गया, जिससे सुरक्षा बलों को माओवादी इकाइयों की पहचान करने और उनके कार्रवाई करने से पहले ही उन्हें निष्क्रिय करने में मदद मिली।

इसके परिणाम ऐतिहासिक रूप से अभूतपूर्व थे। 2022 और 2026 के बीच, वरिष्ठ माओवादी नेताओं (पोलित ब्यूरो सदस्यों, केंद्रीय समिति के पदाधिकारियों और पीएलजीए के सैन्य कमांडरों) को इतनी तेज़ी से निष्क्रिय किया गया कि आंदोलन की नेतृत्व संरचना को व्यवस्थित रूप से ध्वस्त कर दिया गया। यह कोई संयोग या सामरिक भाग्य नहीं था, बल्कि यह ख़ुफ़िया जानकारी जुटाने में वर्षों के निवेश का परिणाण था, जिसने अंततः ऑपरेशनल स्तर पर निर्णायक परिणाम दिए।

बस्तर और अबूझमाड़ की चुनौती

माओवादी वामपंथी आंदोलन के सबसे भयानक युद्ध बस्तर (सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर के पार) और अबूझमाड़ में लड़े गए। दशकों से ये दूरस्थ वन क्षेत्र माओवादियों का प्रमुख गढ़ रहे थे। इन क्षेत्रों में घने जंगल, बेहद चुनौतीपूर्ण भूभाग, माओवादी कार्यकर्ताओं द्वारा लंबे समय से पोषित आदिवासी समुदाय और पीएलजीए बटालियन-स्तरीय टुकड़ियों की अधिकता थी, जिसने इन्हें संघर्ष का सबसे कठिन क्षेत्र बना दिया था।

बस्तर में सीएपीएफ की रणनीति फॉरवर्ड ऑपरेशन बेस (एफओबी) के विस्तार पर केंद्रित थी, जिसके तहत लंबे समय से राज्य के नियंत्रण से बाहर रहे जंगलों के भीतर स्थायी सुरक्षा उपस्थिति स्थापित की गई। प्रत्येक एफओबी ने माओवादियों को शरण देने से इनकार कर दिया। उनकी आपूर्ति लाइनों को बाधित किया और एक पीढ़ी से वीरान पड़े क्षेत्रों में राज्य के अधिकार की वापसी का प्रतीक बना। विवादित क्षेत्रों में आक्रमण का नेतृत्व सीआरपीएफ (केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल) की प्रमुख कोबरा बटालियन ने किया, जो जंगल युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों में विशेषज्ञ थीं और उन्हें बीएसएफ (सीमा सुरक्षा बल), आईटीबीपी (भारत-तिब्बत सीमा पुलिस) और राज्य पुलिस का सहयोग प्राप्त था। इस चरण तक, एक एकीकृत कमान ढांचे ने बलों के बीच के उन मतभेदों को काफी हद तक समाप्त कर दिया था, जिन्होंने पहले अभियानों को बाधित किया था, जिससे समन्वित और संगठित प्रगति संभव हो सकी।

अबूझमाड़, जिसका शाब्दिक अर्थ 'अज्ञात पहाड़ियां' है। एक अद्वितीय चुनौती पेश करता था। जो दशकों तक यह भारतीय राज्य के लिए लगभग एक 'नो-गो ज़ोन' बना रहा- माओवादी आंदोलन का वैचारिक केंद्र, उसके नेतृत्व का सुरक्षित आश्रय और वह स्थान जहां पीएलजीए इकाइयां अन्य क्षेत्रों में मिली असफलताओं के बाद पुनर्गठित होती थीं।

इस गढ़ में हेलीकॉप्टर आधारित लॉजिस्टिक्स, ड्रोन द्वारा की गई निगरानी और वर्षों की मेहनत से विकसित की गई ख़ुफ़िया जानकारी के माध्यम से प्रवेश संभव हुआ। जैसे-जैसे सुरक्षा बलों ने इस सुरक्षित

बीजापुर पुलिस ने नक्सलियों द्वारा गड्ढे में छिपाए गए विस्फोटक बरामद किए।

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

आश्रय को ध्वस्त किया, वैसे-वैसे उन्होंने उग्रवाद की पुनर्जीवित होने की क्षमता को भी गंभीर रूप से कमज़ोर कर दिया।

जंगलों के भीतर सड़क निर्माण एक बल गुणक (फोर्स मल्टीप्लायर) साबित हुआ, जिसने सुरक्षा बलों की त्वरित तैनाती को संभव बनाया। साथ ही यह राज्य की स्थायी प्रशासनिक उपस्थिति का संकेत भी था। राज्य केवल वहां प्रवेश ही नहीं कर रहा था, बल्कि स्थायी रूप से अपनी उपस्थिति भी स्थापित कर रहा था।

केंद्र-राज्य समन्वय

वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) विरोधी अभियानों को लंबे समय तक केंद्र-राज्य के बीच के तनाव, अतिव्यापी क्षेत्राधिकार, ख़ुफ़िया जानकारी के असमान आदान-प्रदान और राजनीतिक हिचकिचाहट जैसी समस्याओं ने बाधित किया, जिससे राज्य स्तर पर प्रतिबद्धता कमज़ोर पड़ती थी। 2014 के बाद इस संरचनात्मक कमज़ोरी को व्यवस्थित रूप से दूर किया गया। गृह मंत्रालय और राज्यों के बीच नियमित समीक्षा बैठकों ने संस्थागत जवाबदेही स्थापित की, सबसे अधिक प्रभावित जिलों में एकीकृत कमांड संरचनाएं लागू की गईं, और सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) जैसी योजनाओं के तहत वित्तीय प्रवाह को सीधे परिचालन प्रदर्शन संकेतकों से जोड़ा गया।

छत्तीसगढ़ का केंद्र की परिचालनात्मक रणनीति के साथ समन्वय, जिसमें राज्य पुलिस के स्थानीय ज्ञान को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की मारक क्षमता और ख़ुफ़िया तंत्र के साथ जोड़ा गया, प्रभावी नक्सल-विरोधी संघवाद (एंटी-एलडब्ल्यूई संघवाद) का एक आदर्श मॉडल बन गया। संयुक्त रूप से प्रशासित आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति ने एक और आयाम जोड़ा- माओवादी कैडरों को बाहर निकलने का रास्ता प्रदान करना और साथ ही माओवादी संगठन को भीतर से समझने वाले सूत्रों से महत्वपूर्ण ख़ुफ़िया जानकारी प्राप्त करना था।

नागरिक कार्रवाई और विश्वास निर्माण

वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) का दायित्व केवल हिंसात्मक कार्रवाई तक सीमित नहीं था। सुरक्षा अभियानों के साथ-साथ, चिकित्सा शिविर, स्कूल सहायता, बुनियादी ढांचागत सहायता और सामुदायिक संपर्क जैसे नागरिक कार्रवाई कार्यक्रमों ने उन आदिवासी क्षेत्रों में राज्य की रचनात्मक उपस्थिति को लगातार दर्शाया, जहां माओवादियों द्वारा उपेक्षा की कहानियां गूंजती थीं। आत्मसमर्पण की अपील और सामुदायिक संवाद जैसी मनोवैज्ञानिक पहल के साथ मिलकर, इन प्रयासों ने माओवादियों के प्रभाव को धीरे-धीरे कम किया, जिससे आदिवासी समुदाय निष्क्रिय या सक्रिय समर्थकों से सुरक्षा परिणामों में हितधारक बन गए।

स्थायी शांति

वामपंथी उग्रवाद विरोधी अभियान केवल सैन्य विजय तक सीमित नहीं था। इसका मूल उद्देश्य उन नागरिकों तक भारतीय राज्य के संरक्षण, अधिकार और संवैधानिक वादों को पहुंचाना था, जो पिछले पांच दशकों से इससे वंचित रहे थे। आदिवासी क्षेत्रों में सुशासन, न्याय और समावेशन सुनिश्चित करना ही 'नक्सल-मुक्त भारत' की कहानी का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। ❑

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

विश्वास निर्माण

अभिराम घड़्याल पाटिल

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विश्वास, विकास और लोकतंत्र की जीत

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में वह व्यवस्था भी थी जिसे नक्सल "जनताना सरकार" कहते थे, जो एक खुलकर लोकतंत्र-विरोधी और असंवैधानिक समानांतर दंडात्मक ढांचा था। इस गैर-क़ानूनी संरचना का विघटन और भारत के संविधान को भूमि का एकमात्र क़ानून स्थापित करना नक्सली उग्रवाद के विरुद्ध एक स्पष्ट और अत्यंत आवश्यक पहली जीत है। इस भौगोलिक और क्षेत्रीय विजय ने लोकतंत्र के लिए एक सुरक्षित, दृश्यमान और प्रेरणादायक वातावरण तैयार किया है।

भारत द्वारा 31 मार्च, 2026 को आधिकारिक रूप से वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) के अंत की घोषणा किए जाने के एक महीने से भी कम समय बाद, मैंने छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के प्रशासनिक मुख्यालय जगदलपुर में आयोजित एक डिजिटल लोकतंत्र सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में अलग-अलग सामाजिक और आयु वर्गों से जुड़े 60 कंटेंट क्रिएटर्स को आमंत्रित किया गया था, ताकि वे स्वयं ज़मीनी स्थिति को देख सकें।

उन्होंने पूर्व वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, इंद्रावती नदी में बांस की नावों पर राफ्टिंग की, स्थानीय आदिवासियों द्वारा विकसित सामुदायिक पर्यटन केंद्रों में भोजन किया और उन पूर्व नक्सलियों की बातें सुनीं जिन्होंने हथियार छोड़कर लोकतांत्रिक मुख्यधारा को अपनाया और यह बताया कि उन्होंने यह निर्णय क्यों लिया। इंद्रावती के तट पर या नदी में राफ्टिंग करते हुए इन कंटेंट क्रिएटर्स ने वीडियो बनाए और उस परिवर्तन को रिकॉर्ड किया, जिसे उन्होंने अपनी आंखों से देखा। यह सब उन स्थानों से कुछ ही किलोमीटर दूर था, जहां कभी नक्सलियों ने सुरक्षा बलों और नेताओं पर सबसे घातक हमले किए थे। भारत के अधिकांश हिस्सों में यह सामान्य बात मानी जाती, लेकिन छत्तीसगढ़ में कुछ वर्ष पहले तक ऐसी सामान्य स्थिति की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।

नक्सलवाद पर लोकतंत्र की निर्णायक जीत

बदलाव के दौर से गुजरते बस्तर का यह परिचय, दशकों पुराने वामपंथी उग्रवाद पर लोकतंत्र की विजय का अत्यंत सशक्त और प्रभावशाली प्रमाण था, जिसने भारत के लोकतंत्र और संविधान दोनों को अस्वीकार किया था। भारत की सुरक्षा व्यवस्था द्वारा वामपंथी उग्रवाद पर हासिल की गई इस ऐतिहासिक सफलता ने इन क्षेत्रों में ज़मीनी लोकतंत्र की व्यापक और स्थायी स्थापना की उम्मीदें बढ़ा

> "यह सच है कि माओवादी हिंसा ने मध्य और पूर्वी भारत के कई जिलों की प्रगति को रोक दिया था। इसीलिए 2015 में हमारी सरकार ने माओवादी हिंसा को खत्म करने के लिए एक व्यापक 'राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना' तैयार की। हिंसा के प्रति शून्य सहिष्णुता के साथ-साथ, हमने इन क्षेत्रों में गरीब लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए बुनियादी ढांचे और सामाजिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केन्द्रित किया है।"
>
> *– प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी*

लेखक वरिष्ठ पत्रकार, नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास के पूर्व राजनीतिक सलाहकार हैं और वर्तमान में राजनीतिक नेतृत्व प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं क्षमता निर्माण संगठन रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। ईमेलः ed@rmponweb.org

upscnotes.in
PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

दी हैं। विडंबना यह है कि जिन्हें नक्सली "मुक्त क्षेत्र" कहा करते थे, वहां लोकतंत्र अब सफलता की कहानी बनकर उभर रहा है। ये वही इलाके हैं, जो कुछ समय पहले तक राज्य की संस्थाओं और प्रतिबंधित माओवादी संगठनों के बीच हिंसक संघर्ष के केंद्र हुआ करते थे।

'जनताना सरकार' से संविधान के शासन तक

यह कहना उचित नहीं होगा कि उन क्षेत्रों में लोकतंत्र बिल्कुल मौजूद नहीं था जिन्हें नक्सली और उनसे जुड़े तंत्र "रेड कॉरिडोर" कहना पसंद करते थे। ये क्षेत्र भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों के लिए अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को भेजते थे। लेकिन यह अधिकतम सीमित लोकतंत्र था और यह वहां रहने वालों को जीवन की सुरक्षा तथा विधि के शासन की वह गारंटी नहीं दे पाता था जिसे भारत का संविधान सुनिश्चित करता है। इन क्षेत्रों में माओवादियों का प्रभाव भी संविधान के सीमित और चुनौतीपूर्ण प्रभाव के साथ-साथ चलता था। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में वह व्यवस्था भी थी जिसे नक्सल "जनताना सरकार" कहते थे, जो एक खुलकर लोकतंत्र-विरोधी और असंवैधानिक सतर्कतावादी ढांचा था।

समयबद्ध रणनीति और निर्णायक नेतृत्व

इस गैर-क़ानूनी संरचना का विघटन और भारत के संविधान को भूमि का एकमात्र क़ानून स्थापित करना, नक्सली उग्रवाद के विरुद्ध एक स्पष्ट और अत्यंत आवश्यक पहली जीत है। इस क्षेत्रीय और भौगोलिक विजय ने लोकतंत्र के लिए एक सुरक्षित, स्पष्ट और प्रेरणादायक वातावरण तैयार किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्पष्ट दृष्टिकोण वाले और निर्णायक नेतृत्व में, जिन्होंने इस वामपंथी उग्रवाद विरोधी अभियान को अभूतपूर्व राजनीतिक समर्थन, प्रतिबद्धता और विश्वसनीयता प्रदान की, सुरक्षा बलों ने वह उपलब्धि हासिल की है, जो 1960 के दशक के अंत में शुरू हुए माओवादी विद्रोह के बाद से कोई भी सरकार नहीं कर सकी थी। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जिसकी तुलना जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को संवैधानिक और संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से हटाने तथा उसके बाद वहां पूर्ण क्षेत्रीय नियंत्रण, नागरिकों और सुरक्षा बलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा एक नए प्रशासनिक ढांचे की स्थापना से की जा सकती है।

विकास और सुरक्षा का दोहरा अभियान

एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार, विशेषकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में गृह मंत्रालय, वामपंथी उग्रवाद पर इतनी निर्णायक चोट कर सका, जबकि पिछली सरकारें ऐसा नहीं कर पाईं। अमित शाह ने सुरक्षा तंत्र के सामने इस समस्या को समाप्त करने की समय-सीमा निर्धारित की। भारत में जहां सरकारी समय-सीमाओं का पालन अक्सर नहीं किया जाता, वहां इस सरकार ने बड़े और साहसिक लक्ष्य निर्धारित किए और उन्हें समय पर पूरा भी किया, जो अपने आप में एक अनूठी उपलब्धि है। वामपंथी उग्रवाद पर नज़र रखने वाले अधिकांश विशेषज्ञ, यहां तक कि वे आलोचक भी जो इस रणनीति को लेकर संदेह में थे, अब स्वीकार करते हैं कि इस स्पष्ट घोषणा ने सुरक्षा तंत्र को उद्देश्य, समर्पण और एकाग्रता प्रदान की। यद्यपि यह सैन्य अभियान नहीं था, फिर भी "क्लियर, होल्ड और बिल्ड" रणनीति के पहले दो चरण सफलतापूर्वक पूरे किए गए।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सल प्रभावित गुंडम का दौरा किया।

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक नवंबर, 2025 को छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का अवलोकन किया।

मुख्यधारा की ओर लौटते पूर्व नक्सली

वामपंथी उग्रवाद विरोधी अभियान इसलिए भी सफल रहा क्योंकि उसने विद्रोह के मूल कारण विकास की कमी और उससे उत्पन्न अलगाव की भावना को संबोधित किया। इसी भावना ने आदिवासियों को राज्य के विरुद्ध हथियार उठाने के लिए प्रेरित किया था। नक्सलियों और उनके समर्थक बुद्धिजीवी तंत्र ने इस समस्या को एक दुष्चक्र में बदल दिया था। वे विकास की कमी को विद्रोह का कारण बताते थे, लेकिन साथ ही किसी भी विकास योजना को आदिवासियों तक पहुंचने नहीं देते थे। यह तर्क लंबे समय तक नक्सलियों के पक्ष में काम करता रहा, लेकिन वर्तमान सरकार ने सुरक्षा सुनिश्चित कर इस दुष्चक्र को तोड़ दिया, जिससे विकास कार्य संभव हो सके। नई रणनीति के तहत सरकार ने उन क्षेत्रों की पहचान की जहां विद्रोह सबसे अधिक तीव्र था और सुरक्षा बलों को माओवादी नेतृत्व के शीर्ष स्तर को निशाना बनाने का निर्देश दिया ताकि वामपंथी उग्रवाद नेतृत्वविहीन और मनोबलहीन हो जाए। इसके परिणामस्वरूप 2025 में 87 नए सुरक्षा शिविर स्थापित किए गए और 2026 में अब तक 16 नए शिविर बनाए जा चुके हैं। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में कुल 833 सुरक्षा शिविरों में से 400 से अधिक 2019 के बाद स्थापित किए गए हैं। 2025-26 में सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए माओवादी कैडरों में आधे से अधिक एरिया कमेटी के सदस्य थे, जबकि 2025 में मारे गए 11 माओवादी केंद्रीय समिति सदस्य थे।

सुरक्षा अभियानों और माओवादी समूहों की बातचीत की पेशकशों के प्रति सरकार की रणनीतिक उदासीनता का अपेक्षित प्रभाव पड़ा। जैसे-जैसे अभियान तेज़ हुआ और सरकार का नियंत्रण बढ़ा, अधिक से अधिक माओवादी कैडरों ने आत्मसमर्पण करना शुरू किया। 2024 में 881 माओवादी कैडरों ने आत्मसमर्पण किया था। 2025 में यह संख्या लगभग तीन गुना बढ़कर 2337 हो गई। इस वर्ष अब तक 700 से अधिक माओवादी हथियार छोड़ चुके हैं।

विकास से बढ़ा विश्वास

विकास कार्यों ने भी सुरक्षा उपलब्धियों को मज़बूत किया और लोगों की सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाया। 2024 के बाद वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में सड़कों की कुल लंबाई में 25 प्रतिशत वृद्धि हुई है। अब इन क्षेत्रों के 96 प्रतिशत से अधिक गांव मोबाइल नेटवर्क से जुड़ चुके हैं। पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बैंक शाखाओं की संख्या 2014 में 3320 थी, जो अब बढ़कर 5124 हो गई है। इससे ये क्षेत्र राष्ट्रीय औसत प्रति 8300 लोगों पर एक बैंक के करीब पहुंच गए हैं।

2017 से 2026 के बीच वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में लगभग 6000 नए डाकघर खोले गए हैं। स्थानीय स्तर पर छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव जैसे आदिवासियों की सुरक्षा बलों में भर्ती, "बस्तर ओलंपिक" और "बस्तर पंडुम" जैसे आयोजन तथा 2014 के बाद एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की संख्या में चार गुना से अधिक वृद्धि ने विश्वास की कमी को दूर किया है और उन लोगों में नई आकांक्षाएं पैदा की हैं, जो कभी नक्सलियों के भय में रहते थे तथा शासन, सेवाओं की उपलब्धता और लोकतंत्र के वास्तविक कल्याणकारी स्वरूप से वंचित थे। ❑

upscnotes.in

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

बस्तर पंडुमः संस्कृति, पहचान और शांति की पुनर्स्थापना

55,000 से अधिक आदिवासी व्यक्तियों की भागीदारी केवल एक आंकड़ा नहीं है। यह भय से दूर और सामूहिक आत्मविश्वास की ओर क्षेत्र के परिवर्तन का एक प्रतिबिंब है। इस संदर्भ में सांस्कृतिक आत्मविश्वास दशकों के अलगाव और संघर्ष के विरुद्ध एक वैकल्पिक विमर्श प्रस्तुत करता है।

नक्सल-मुक्त भारत की अवधारणा को अब केवल सुरक्षा अभियानों के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण, सहभागी शासन और समावेशी विकास के परिप्रेक्ष्य से भी समझा जाने लगा है। छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र, जो कभी लंबे समय तक चले उग्रवाद का प्रतीक माना जाता था, आज एक परिवर्तनकारी बदलाव का साक्षी बन रहा है। इस परिवर्तन के केंद्र में बस्तर पंडुम 2026 है, जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण और सामाजिक-राजनीतिक मील के पत्थर, दोनों के रूप में उभरा है। विशेष रूप से मार्च के अंत तक नक्सल-मुक्त दिशा में मिली महत्वपूर्ण उपलब्धियों की पृष्ठभूमि में।

जीवन और पहचान में रचा-बसा एक उत्सव

बस्तर पंडुम केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं है; यह बस्तर के जनजातीय समुदायों के जीवन अनुभव, मौसमी चक्रों और सामूहिक पहचान की एक अभिव्यक्ति है। जैसा कि सात फरवरी, 2026 को जगदलपुर में उद्घाटन समारोह के दौरान भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा कहा गया था कि "जब किसान बीज बोते हैं, तो वह पंडुम है; जब आम पकते हैं, तो वह पंडुम है", जो इस बात का प्रतिबिंब है कि यह अवधारणा दैनिक जीवन में कितनी गहराई से समाहित है। यह उत्सव केवल प्रदर्शन कलाओं का नहीं, बल्कि प्रकृति और सामुदायिक परंपराओं के साथ सामंजस्य पर आधारित एक सम्पूर्ण जीवन-दृष्टि का उत्सव है।

पांच जनवरी से नौ फरवरी तक आयोजित 2026 संस्करण में 54,745 व्यक्तियों ने भाग लिया, जिसमें बस्तर संभाग के सभी सात जिलों (सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कोंडागांव, नारायणपुर और कांकेर) की सहभागिता रही। सभी 1,885 ग्राम पंचायतों को कवर करते हुए 32 ब्लॉक मुख्यालयों में प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जो ज़मीनी स्तर पर जुड़ाव के एक अभूतपूर्व पैमाने को दर्शाती हैं।

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

सांस्कृतिक मंचों का विस्तार और संस्थागतकरण

अपने पिछले संस्करण की सफलता के आधार पर, बस्तर पंडुम 2026 ने अपने दायरे को सात श्रेणियों से बढ़ाकर 12 विधाओं तक विस्तारित किया। इनमें जनजातीय नृत्य, संगीत, नाटक, प्रदर्शन कला, वेशभूषा, आभूषण, हस्तशिल्प, चित्रकला, पेय पदार्थ, व्यंजन, क्षेत्रीय साहित्य और वन-आधारित औषधीय ज्ञान शामिल थे। यह विस्तार जनजातीय विरासत के विविध आयामों को दस्तावेजीकृत करने, संरक्षित करने और प्रोत्साहित करने के एक सचेत प्रयास का प्रतीक है।

12 मार्च से पांच अप्रैल तक आयोजित 2025 संस्करण ने पहले ही लगभग 47,000 कलाकारों की भागीदारी और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल होकर एक मज़बूत उदाहरण स्थापित किया था। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में इस उत्सव की निरंतरता और विस्तार सांस्कृतिक सशक्तीकरण के प्रति सतत नीतिगत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

राष्ट्रीय नेतृत्व की उपस्थिति से बढ़ा बस्तर पंडुम का महत्व

बस्तर पंडुम 2026 का महत्व, उद्घाटन और समापन दोनों समारोहों में राष्ट्रीय नेतृत्व की उपस्थिति से और अधिक बढ़ गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने उत्सव का उद्घाटन किया, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नौ फरवरी, 2026 को जगदलपुर में आयोजित समापन समारोह में शामिल हुए।

अपने संबोधन में, गृह मंत्री ने बस्तर की पहचान में 'मोर्टार के गोले, गोलीबारी और आईईडी धमाकों' से जुड़े क्षेत्र से लेकर एक ऐसे क्षेत्र के रूप में एक मौलिक बदलाव को रेखांकित किया, जहां 55,000 से अधिक लोगों ने 12 विधाओं में संस्कृति का जश्न मनाया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि बस्तर की पहचान अब 'बारूद' से नहीं, बल्कि इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी होनी चाहिए। यह धारणा-परिवर्तन क्षेत्र की आंतरिक और बाहरी दोनों धारणाओं को फिर से परिभाषित करने में महत्वपूर्ण है।

सांस्कृतिक आत्मविश्वास से कमज़ोर पड़ता उग्रवाद

जैसा कि समापन समारोह के दौरान रेखांकित किया गया था, 55,000 से अधिक आदिवासी व्यक्तियों की भागीदारी केवल एक आंकड़ा नहीं है। यह भय से दूर और सामूहिक आत्मविश्वास की ओर क्षेत्र के परिवर्तन का एक प्रतिबिंब है। इस संदर्भ में सांस्कृतिक आत्मविश्वास दशकों के अलगाव और संघर्ष के विरुद्ध एक वैकल्पिक विमर्श प्रस्तुत करता है।

इस उत्सव ने जनजातीय कलाकारों को सम्मान और पहचान प्रदान करने में भी भूमिका निभाई है। प्रदर्शन और प्रतियोगिता के लिए संगठित मंच तैयार करके यह स्थानीय परंपराओं को व्यापक सांस्कृतिक और आर्थिक ढांचों से जोड़ता है। वन उपज और हस्तशिल्प सहित जनजातीय उत्पादों की ब्रांडिंग और विपणन को बढ़ावा देने की पहल, आजीविका के अवसरों को और अधिक मज़बूत करती है।

सांस्कृतिक पुनर्जागरण के साथ विकास का विस्तार

बस्तर पंडुम के माध्यम से देखा गया सांस्कृतिक पुनरुत्थान विकासात्मक पहल की एक श्रृंखला के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। जैसा कि कार्यक्रम के दौरान रेखांकित किया गया था, कई बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी उपाय लागू किए जा रहे हैं:

- लगभग 40 वर्षों से बंद पड़े विद्यालयों का पुनः संचालन
- सड़क संपर्क का विस्तार और मोबाइल टावरों की स्थापना
- पांच किलोमीटर के दायरे में डाकघर और बैंकिंग सुविधाओं की स्थापना
- प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलोग्राम निःशुल्क चावल की व्यवस्था
- गैस सिलेंडर और घरेलू नल जल कनेक्शन की आपूर्ति

इसके अतिरिक्त, 118 एकड़ में एक नया औद्योगिक क्षेत्र और ऑटो गिग हब विकसित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आदिवासी युवाओं के लिए रोज़गार पैदा करना है। प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं में 3,500 करोड़ रुपये की रावघाट-जगदलपुर रेल परियोजना और

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 25 अक्टूबर, 2016 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय मेले का उद्घाटन किया।

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

> देशभर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय बनाना हो... या भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को, जनजातीय गौरव दिवस घोषित करना हो...
>
> **हमारी कोशिश यही है कि आदिवासी समाज के योगदान का हमेशा गौरवगान होता रहे।**
>
> छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव पर पीएम मोदी, 1 नवंबर 2025

इंद्रावती नदी पर 36 करोड़ रुपये की सिंचाई परियोजना शामिल है, जिससे 120 मेगावाट बिजली उत्पादन की उम्मीद है। 90,000 से अधिक युवाओं को लक्षित करने वाली कौशल विकास पहल विकास एजेंडे को और अधिक मज़बूत करती हैं।

सुरक्षा कार्रवाई के साथ सम्मानजनक पुनर्वास की नीति

नक्सल-मुक्त बस्तर की दिशा में परिवर्तन सुरक्षा उपायों और पुनर्वास नीतियों के संतुलित दृष्टिकोण पर भी आधारित है। सरकार ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि आत्मसमर्पण करने वालों का सम्मानपूर्वक पुनर्वास किया जाएगा, जबकि हिंसक गतिविधियों का कड़ा जवाब दिया जाएगा।

पुनर्वास ढांचे को विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए, मुख्यधारा के समाज में पुनः एकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार किया गया है। परिवारों से अपील की गई है कि वे नक्सली गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के आत्मसमर्पण का समर्थन करें, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे अपना जीवन फिर से संवार सकें। साथ ही नक्सल विरोधी अभियानों का मार्गदर्शन करने वाला मुख्य सिद्धांत आदिवासी किसानों, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बना हुआ है-वे समूह जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से हिंसा का सबसे अधिक खामियाजा भुगता है।

मान्यता और समावेशन का महत्व

जनजातीय योगदान की राष्ट्रीय मान्यता इस परिवर्तन का एक अन्य महत्वपूर्ण आयाम रही है। बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया जाना और उनकी 150वीं जयंती को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया जाना, जनजातीय विरासत को सम्मानित करने के प्रति एक व्यापक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इसके अतिरिक्त बस्तर क्षेत्र के व्यक्तियों, जैसे कि पंडित राम मंडावी, हेमचंद मांझी, अजय कुमार मंडावी और बुधरी ताती को कला, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ऐसी मान्यताएं जनजातीय समुदायों के बीच गर्व और अपनेपन की भावना को सुदृढ़ करती हैं।

पर्यटन और भविष्य की संभावनाएं

नक्सली प्रभाव में गिरावट के साथ, बस्तर सांस्कृतिक और ईको-पर्यटन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरने के लिए तैयार है। प्रस्तावित पहल में एडवेंचर टूरिज्म, होमस्टे, कैनोपी वॉक और ग्लास ब्रिज शामिल हैं। इन प्रयासों से रोज़गार पैदा होने की उम्मीद है और साथ ही बस्तर की अद्वितीय सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का प्रदर्शन भी होगा।

बस्तर की संस्कृति को राष्ट्रीय और वैश्विक मंचों पर प्रस्तुत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा व्यक्त किया गया दृष्टिकोण इन पहल के अनुरूप है, जो इस क्षेत्र को भारत की सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में स्थापित करता है।

उपलब्धियों का सुदृढ़ीकरण

बस्तर के घटनाक्रमों को नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में भारत की प्रगति के व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए, जिसमें मार्च के अंत तक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गईं। बस्तर पंडुम 2026 इस प्रगति के प्रतिबिंब और सुदृढ़ीकरण दोनों के रूप में कार्य करता है।

यह उत्सव दर्शाता है कि स्थायी शांति केवल सुरक्षा हस्तक्षेपों से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान की स्वीकृति और सशक्तीकरण, आर्थिक समावेशन तथा सहभागी शासन के माध्यम से भी निर्मित होती है। 1,885 ग्राम पंचायतों में समुदायों की बड़े पैमाने पर भागीदारी विकास के 'बॉटम-अप' (नीचे से ऊपर) दृष्टिकोण की सफलता को उजागर करती है।

बस्तर पंडुम 2026 एक ऐसे क्षेत्र के परिवर्तन को समाहित करता है जो कभी संघर्ष से परिभाषित होता था और आज सांस्कृतिक जीवंतता और विकास की नई गति से पहचाना जाता है। परंपरा को आधुनिक शासन के साथ जोड़ते हुए यह जटिल सामाजिक-राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए एक अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत करता है। ❑

स्रोतः पीआईबी

upscnotes.in

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस
(21 जून)

डॉ. हंसाजी योगेंद्र

मन की शांति से समाज की शांति तक योग का जीवन दर्शन

शांत समाज का निर्माण केवल क़ानूनों, संस्थानों या आर्थिक प्रगति से नहीं हो सकता। इसका निर्माण भावनात्मक रूप से स्वस्थ लोगों के माध्यम से भी होना चाहिए। जब लोगों और समुदायों में निराशा, अलगाव, क्रोध और हताशा अनसुलझे रह जाते हैं, तो वे धीरे-धीरे उनके आसपास के सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित करते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर भावनात्मक असंतुलन अक्सर सामूहिक स्तर पर संघर्ष के रूप में प्रकट होता है, इसलिए मानसिक स्वास्थ्य केवल व्यक्तिगत नहीं है। यह सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय कल्याण से गहराई से जुड़ा हुआ है।

भारत आज अपनी यात्रा के महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, हमने प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, डिजिटल परिवर्तन और वैश्विक प्रभाव में अभूतपूर्व प्रगति देखी है। भारत नवाचार, विकास और राष्ट्रीय उद्देश्य की एक नई भावना से प्रेरित होकर, विश्व मंच पर आत्मविश्वासी और शक्तिशाली आवाज़ के रूप में उभर रहा है। फिर भी, इस प्रत्यक्ष प्रगति के साथ-साथ घरों, कार्यस्थलों, स्कूलों और समुदायों में एक और वास्तविकता उभर रही है। यह मानसिक अशांति का बढ़ता संकट है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वैश्विक स्तर पर लगभग हर आठ में से एक व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य समस्या से ग्रस्त है। भारत में तनाव, चिंता, भावनात्मक थकान, अकेलापन और मानसिक तनाव न केवल वयस्कों बल्कि बच्चों और युवाओं को भी तेज़ी से प्रभावित कर रहे हैं। पहले से कहीं अधिक डिजिटल रूप से जुड़े होने के बावजूद, मनुष्य स्वयं से और एक-दूसरे से गहराई से अलग-थलग महसूस कर रहे हैं।

कई लोग थके हुए उठते हैं, भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण समय को जल्दबाजी में बिताते हैं और मानसिक रूप से तरोताजा महसूस किए बिना सो जाते हैं। यह केवल एक चिकित्सीय चुनौती नहीं है। यह एक मानवीय चुनौती है।

मानसिक स्वास्थ्य इस बात को दर्शाता है कि लोग कैसे सोचते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, संबंध बनाते हैं, काम करते हैं और अंततः समाज के रूप में एक साथ रहते हैं। स्वस्थ मन वह नहीं है जो कभी कठिनाइयों का सामना नहीं करता, बल्कि वह है जो स्पष्टता और संतुलन के साथ जीवन में आगे बढ़ना सीखता है।

बीमारी की अनुपस्थिति से परे

मानसिक स्वास्थ्य को अक्सर केवल बीमारी ना होने की स्थिति के रूप में समझा जाता है। वास्तव में यह अनिश्चितता के बीच भावनात्मक स्थिरता बनाए रखने, दबाव की स्थिति में शांत रहने और स्वयं तथा दूसरों के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने की क्षमता है।

आज कई लोग बाहरी रूप से सफल दिखते हैं, लेकिन अंदर से अत्यधिक अशांत महसूस करते हैं। आधुनिक जीवन ने सुविधा और अवसर तो दिए हैं, लेकिन साथ ही तुलना, अति-उत्तेजना, अधीरता तथा भावनात्मक थकावट को भी बढ़ा दिया है। हमारे समय के सबसे बड़े विरोधाभासों में से एक यह है कि मनुष्य मशीनों को कुशलतापूर्वक चलाना तो सीख गए हैं, लेकिन धीरे-धीरे अपने मन को नियंत्रित करना भूलते जा रहे हैं।

योग संस्थान में जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ दशकों के कार्य के दौरान हमने देखा है कि पीड़ा अक्सर केवल बाहरी परिस्थितियों के कारण ही नहीं बढ़ती, बल्कि इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि मन को जीवन के प्रति शांत प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया है। एक छोटी सी आलोचना क्रोध उत्पन्न करती है। एक झटका निराशा पैदा करता है। निरंतर तुलना असुरक्षा पैदा करती

लेखक, विश्व के सबसे पुराने योग केंद्रों में से एक मुंबई स्थित योग संस्थान के निदेशक हैं। वे एक प्रसिद्ध योग चिकित्सक, लेखक और प्रेरक वक्ता भी हैं। ईमेलः info@theyogainstitute.org

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

है। भावनात्मक असंतुलन धीरे-धीरे शारीरिक स्वास्थ्य, संबधों और जीवन की समग्र गुणवत्ता को प्रभावित करने लगता है।

भगवद्गीता मानसिक स्थिरता के महत्व का सुंदर वर्णन करती हैः

> **"समत्वं योग उच्यते"**
> "योग संतुलन की अवस्था है।"
> (भगवद्गीता 2.48)

यह सरल लेकिन गहन शिक्षा हमें याद दिलाती है कि योग केवल शारीरिक लचीलापन नहीं है। यह भावनात्मक संतुलन है।

बेचैन जीवनशैली की कीमत

आधुनिक जीवन अत्यंत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। मौन, आत्मनिरीक्षण और भावनात्मक विराम का समय ना के बराबर है। लोग सूचनाओं, संदेशों और अन्य विकर्षणों पर प्रतिक्रिया देने में घंटों बिताते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को समझने के लिए बहुत कम समय देते हैं। आज के बच्चे और युवा अत्यधिक शैक्षणिक तथा सामाजिक दबाव का सामना कर रहे हैं। आज आत्म-मूल्य का आकलन बढ़ते हुए प्रदर्शन, बाहरी रूप-रंग, सामाजिक स्वीकृति और बाहरी उपलब्धियों के आधार पर किया जाने लगा है। यहां तक कि वयस्क भी निरंतर तनाव में जी रहे हैं। वे पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं कि यह उनके भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को कितनी गहराई से प्रभावित करता है। मानव तंत्रिका तंत्र निरंतर उत्तेजना के लिए नहीं बना है।

प्राचीन योगिक ऋषियों ने इसे गहराई से समझा था। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में योग को सबसे शाश्वत और प्रासंगिक तरीके से परिभाषित किया हैः

> **"योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः"**
> "योग मन के उतार-चढ़ाव को शांत करता है।"
> (योगसूत्र 1.2)

आज मन की चंचलता बहुत बढ़ गई है। अंतहीन जानकारी, तुलना, भय, महत्वाकांक्षा और भावनात्मक अतिभार लगातार आंतरिक शांति को भंग करते हैं। परिणामस्वरूप कई व्यक्ति शारीरिक रूप से तो सक्रिय रहते हैं, लेकिन मानसिक रूप से थके हुए होते हैं। यदि जीवन केवल बाहरी रूप से ही व्यतीत किया जाए तो मन स्वस्थ नहीं रह सकता। आंतरिक विकास भी उतना ही आवश्यक है।

आंतरिक संतुलन के लिए योग

आजकल योग को अक्सर शारीरिक आसनों या फिटनेस दिनचर्या तक ही सीमित कर दिया जाता है। वास्तव में योग एक संपूर्ण जीवन शैली है जो शरीर, मन, भावनाओं और व्यवहार के बीच सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होती है। योग के शारीरिक अभ्यास शरीर में संचित तनाव को दूर करने में सहायता करते हैं। शांत शरीर स्वाभाविक रूप से शांत मन को सहारा देता है। श्वास जागरूकता और प्राणायाम, भावनात्मक उथल-पुथल को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं क्योंकि

21 जून, 2025 को नई दिल्ली स्थित सफदरजंग मकबरे में आयोजित 11वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह की झलकियां।

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

श्वास और मन आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। जब भावनाएं अशांत हो जाती हैं, तो श्वास लेने का तरीका भी बिगड़ जाता है। सचेत रूप से श्वास लेना सीखने से धीरे-धीरे संतुलन बहाल होता है।

आज वैज्ञानिक अध्ययन प्राचीन योगिक अभ्यासों का समर्थन करते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जैसे संस्थानों द्वारा प्रकाशित शोध से पता चला है कि योगिक श्वास और ध्यान अभ्यास तनाव हार्मोन को कम करने, भावनात्मक नियंत्रण में सुधार करने, नींद की गुणवत्ता बढ़ाने और समग्र मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं। हालांकि, योग की असली शक्ति तनाव कम करने से कहीं अधिक है।

योग आत्म-जागरूकता सिखाता है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण लोगों को अपने विचारों को पूर्णतः वश में करने के बजाय उनका अवलोकन करने में मदद करते हैं। अधिकांश लोग यंत्रवत जीवन जीते हैं। प्रतिक्रियाएं आदत बन जाती हैं। योग लोगों को बिना किसी पूर्वाग्रह के रुककर स्वयं का अवलोकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यही जागरूकता अपने आप में परिवर्तनकारी बन जाती है।

सचेत जीवन का सार

सचेत जीवन का अर्थ जिम्मेदारियों से भागना या समाज से अलग-थलग रहना नहीं है। इसका अर्थ है रोजमर्रा की जिंदगी में अधिक जागरूकता के साथ जीना सीखना और इस बात के प्रति सचेत होना कि हम कैसे सोचते हैं, बोलते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, जानकारी ग्रहण करते हैं और दूसरों से संबंध बनाते हैं। इसका अर्थ आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्यपूर्वक सुनना और भावनात्मक आक्रामकता के बजाय संवेदनशीलता से प्रतिक्रिया देना भी है। एक सचेत व्यक्ति परिपक्वता और संतुलन के साथ जीवन का सामना करने की क्षमता विकसित करता है।

आजकल, बहुत से लोग अस्वस्थ जीवनशैली अपनाते हुए अस्थायी रूप से तनाव से राहत पाने का प्रयास करते हैं। जबकि योग, बेचैनी की जड़ को समाप्त करता है। यह दैनिक जीवन की गुणवत्ता को धीरे-धीरे बदलता है। सचेत श्वास, संतुलित दिनचर्या, जीवनशैली में संयम, सार्थक मौन, भावनात्मक जागरूकता और करुणापूर्ण संवाद जैसे सरल अभ्यास धीरे-धीरे मानसिक स्वास्थ्य को मज़बूत करते हैं।

ईशा उपनिषद हमें बहुत सुंदर ढंग से याद दिलाता हैः

> **"तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा"**
>
> "संयम और संतुलन के साथ आनंद लें।"

आधुनिक समाज अक्सर अतिवाद को बढ़ावा देता है, जैसे कि अत्यधिक महत्वाकांक्षा, अत्यधिक उत्तेजना, अत्यधिक उपभोग और बाहरी परिस्थितियों पर अत्यधिक भावनात्मक निर्भरता। योग का दृष्टिकोण संतुलन, सादगी और संतोष सिखाता है। आंतरिक शांति एक पल में नहीं मिलती। यह हमारे दैनिक जीवन जीने के तरीके से विकसित होती है।

शांति और सामाजिक सद्भाव

शांतिपूर्ण समाज का निर्माण केवल क़ानूनों, संस्थाओं या आर्थिक प्रगति से नहीं हो सकता। इसका निर्माण भावनात्मक रूप से स्वस्थ लोगों के माध्यम से भी होना चाहिए। जब लोगों और समुदायों के भीतर कुंठा, अलगाव, क्रोध और निराशा अनसुलझी रहती है, तो धीरे-धीरे उनके आसपास का सामाजिक ताना-बाना प्रभावित होता है। व्यक्तिगत भावनात्मक असंतुलन अक्सर सामूहिक स्तर पर संघर्ष के रूप में प्रकट होता है, इसलिए मानसिक स्वास्थ्य केवल व्यक्तिगत

upscnotes.in

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

नहीं है। यह सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय कल्याण से गहराई से जुड़ा हुआ है।

योग धैर्य, सहानुभूति, आत्म-अनुशासन, भावनात्मक लचीलापन और स्पष्ट सोच जैसे गुणों को पोषित करता है जो व्यक्तियों और समुदायों दोनों को मज़बूत बनाते हैं। ये गुण सामंजस्यपूर्ण परिवारों, जिम्मेदार नागरिकों और शांतिपूर्ण समाजों के निर्माण के लिए आवश्यक हैं।

देश के कई हिस्सों में जहां समुदाय कठिनाई, अनिश्चितता, भावनात्मक तनाव या सामाजिक विखंडन का सामना करते हैं, वहां योग आंतरिक सशक्तीकरण के लिए शांत लेकिन प्रभावशाली शक्ति बन सकता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी सुलभता है। यह महंगे बुनियादी ढांचे या जटिल प्रणालियों पर निर्भर नहीं करता है। इसके सिद्धांतों का अभ्यास सभी आयु वर्ग और पृष्ठभूमि के लोग कर सकते हैं।

शांत मन हिंसा की ओर नहीं जाता। संतुलित मन घृणा को पोषित नहीं करता। भगवद्गीता स्थिर मन के गुणों का सुंदर वर्णन करती हैः

"दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः"

"जिसका मन दुःख में भी अविचलित रहता है और सुख में भी अत्यधिक आसक्ति से मुक्त रहता है .... "

(भगवद्गीता 2.56)

ऐसी आंतरिक स्थिरता न केवल व्यक्तिगत कल्याण के लिए, बल्कि सामूहिक सद्भाव के लिए भी मूल्यवान है।

भविष्य के लिए भावनात्मक शिक्षा

आज के युवाओं को अकादमिक सफलता से कहीं अधिक की आवश्यकता है। उन्हें भावनात्मक शिक्षा की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से आधुनिक शिक्षा अक्सर बौद्धिक विकास पर तो ध्यान देती है, लेकिन भावनात्मक कल्याण की उपेक्षा करती है। परिणामस्वरूप, कई लोग पेशेवर रूप से सक्षम तो हो जाते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। वे प्रतिस्पर्धा करना तो जानते हैं, लेकिन चुनौतियों का सामना करना नहीं जानते। वे सफलता प्राप्त करना तो जानते हैं, लेकिन शांत रहना नहीं जानते। योग इस अंतर को पाटने में सहायक है।

विद्यालयों, महाविद्यालयों, कार्यस्थलों, ग्रामीण समुदायों और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में योग आधारित भावनात्मक कल्याण कार्यक्रमों को शुरू करने से मानसिक स्वास्थ्य सुधार में महत्वपूर्ण योगदान मिल सकता है। शैक्षणिक संस्थानों में किए गए अध्ययनों से पता चला है कि नियमित योग और ध्यान अभ्यास से विद्यार्थियों में एकाग्रता, भावनात्मक नियंत्रण, आत्मविश्वास और तनाव प्रबंधन में सुधार होता है। जो समाज भावनात्मक कल्याण में निवेश करता है, वह दीर्घकालिक सद्भाव में निवेश करता है।

भारत का शाश्वत योगदान

जीवन की यह समग्र समझ मानवता के लिए भारत का महानतम योगदान है। योग शारीरिक स्वास्थ्य को मानसिक स्वास्थ्य से अलग नहीं करता, न ही व्यक्तिगत कल्याण को सामूहिक कल्याण से अलग करता है। यह मानव अस्तित्व के गहरे अंतर्संबंध को मान्यता देता है।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ने विश्व भर में लाखों लोगों को योग को केवल एक व्यायाम के रूप में नहीं, बल्कि स्वस्थ और अधिक सचेत जीवन जीने के मार्ग के रूप में समझने में सहायता की है। स्कूलों और अस्पतालों से लेकर सुधार केंद्रों और कार्यस्थलों तक, योग को मानसिक तथा भावनात्मक कल्याण के साधन के रूप में विश्व स्तर पर तेज़ी से अपनाया जा रहा है। केवल तकनीकी प्रगति से शांति स्थापित नहीं हो सकती। स्थायी शांति संतुलित मानव मन से शुरू होती है।

अधिक शांतिपूर्ण भविष्य की ओर

प्रत्येक व्यक्ति जो अधिक जागरूकता के साथ जीना सीखता है, वह समाज के कल्याण में मौन रूप से योगदान देता है। प्रत्येक व्यक्ति जो क्रोध के स्थान पर धैर्य, घृणा के स्थान पर समझ और आवेग के स्थान पर संतुलन विकसित करता है, वह अपने आसपास के सामूहिक वातावरण को मज़बूत करता है।

किसी राष्ट्र की सच्ची प्रगति में बाह्य विकास और आंतरिक विकास दोनों शामिल होने चाहिए। सड़कें, उद्योग, संस्थाएं और अर्थव्यवस्थाएं विकास के लिए आवश्यक हैं। लेकिन सशक्त और सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण के लिए भावनात्मक रूप से स्वस्थ नागरिक भी उतने ही आवश्यक हैं।

योग इस आंतरिक स्थिरता की ओर लोगों का मार्गदर्शन करता है। इसका उद्देश्य जीवन से पलायन करना नहीं, बल्कि बेहतर ढंग से जीवन व्यतीत करना है। यह हमें चुनौतियों के बीच स्थिर रहना, विकर्षणों के बीच संतुलन बनाए रखना और मतभेदों के बीच करुणा बनाए रखना सिखाता है।

बृहदारण्यक उपनिषद एक शाश्वत प्रार्थना प्रस्तुत करता है जो आज भी अत्यंत प्रासंगिक हैः

"असतो मा सद्गमय ।
तमसो मा ज्योतिर्गमय ।
मृत्योर्मा अमृतं गमय ॥"

"मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलें, अंधकार (अज्ञान) से प्रकाश (ज्ञान) की ओर ले चलें तथा मृत्यु से अमरता (मोक्ष) की ओर ले चलें।"

शांतिपूर्ण भविष्य केवल बाह्य परिवर्तन से नहीं आ सकता। यह आंतरिक रूपांतरण से भी आ सकता है और शायद अब मानवता को जीवन जीने के इस सचेत तरीके की पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है। ❑

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

हमारी पत्रिकाएं

योजना
विकास को समर्पित मासिक
(हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू व 10 अन्य भारतीय भाषाओं में)

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

कुरुक्षेत्र
ग्रामीण विकास मासिक
(हिंदी तथा अंग्रेज़ी)

आजकल
साहित्य एवं संस्कृति का मासिक
(हिंदी तथा उर्दू)

बाल भारती
बच्चों की मासिक पत्रिका
(हिंदी)

घर पर हमारी पत्रिकाएं मंगाना है काफी आसान...

आपको सिर्फ नीचे दिए गए 'भारत कोष' के लिंक पर जाकर पत्रिका के लिए ऑनलाइन डिजिटल भुगतान करना है–
https://bharatkosh.gov.in/Product/Product

सदस्यता दरें

प्लान	योजना या कुरुक्षेत्र या आजकल		बाल भारती	
वर्ष	ट्रैकिंग सुविधा के बिना	ट्रैकिंग सुविधा के साथ	ट्रैकिंग सुविधा के बिना	ट्रैकिंग सुविधा के साथ
1	₹ 350	₹ 434	₹ 280	₹ 364

ऑनलाइन के अलावा आप डाक द्वारा डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल ऑर्डर या मनीऑर्डर से भी प्लान के अनुसार निर्धारित राशि भेज सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल ऑर्डर या मनीऑर्डर '**अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय**' के पक्ष में **नई दिल्ली** में देय होना चाहिए।

अपने डीडी, पोस्टल ऑर्डर या मनीऑर्डर के साथ नीचे दिया गया 'सदस्यता कूपन' या उसकी फोटो कॉपी में सभी विवरण भरकर हमें भेजें। भेजने का पता है- **संपादक (प्रसार), प्रसार एकक, प्रकाशन विभाग, कक्ष सं. 779, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003**

अधिक जानकारी के लिए ईमेल करें- sec-circulation-moib@gov.in

हमसे संपर्क करें- **फोन : 011-24044000/01** (सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर प्रात: 11.00 बजे से अपराह्न 3.30 बजे तक)

कृपया नोट करें कि सदस्यता शुल्क प्राप्त होने के बाद सदस्यता शुरू होने में कम से कम आठ सप्ताह लगते हैं। कृपया इतने समय प्रतीक्षा करें और पत्रिका न मिलने की शिकायत इस अवधि के बाद करें।

सदस्यता कूपन (नई सदस्यता/नवीकरण/पते में परिवर्तन)

कृपया मुझे 1 वर्ष के प्लान के तहत .... पत्रिका .... भाषा में भेजें।

नाम (साफ व बड़े अक्षरों में) ....

पता : ....

.... ज़िला .... पिन ....

ईमेल .... मोबाइल नं. ....

डीडी/पीओ/एमओ सं. .... दिनांक .... सदस्यता सं. ....

upscnotes.in

PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर upscnotes.in सर्च करें

पीआरजीआई संख्या : 951/57
U(DN)-55/2024-26 (बिना पूर्व भुगतान के आरएमएस, दिल्ली से प्रेषित करने हेतु लाइसेंस प्राप्त)
मैगजीन पोस्ट पंजीकरण संख्या : DL(DS)-43/MP/2025-26-27
डाक पंजीकरण संख्या : DL(DS)-05/3231/2024-26
1 जून, 2026 को प्रकाशित

बस्तर पंडुम महोत्सव, जहां परंपरा खुशहाली और सुख-समृद्धि लाती है

यह पत्रिका डॉ. अनुपमा भटनागर, प्रधान महानिदेशक द्वारा प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लिए सूचना भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित की गई है। इसका संपादन त्रिनाथ त्रिपाठी द्वारा और मुद्रण राकेश कुमार शर्मा द्वारा चंदू प्रेस, 469, पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110092 से किया गया है।